खण्ड-202, अंक-7
शुक्रवार, 15 फाल्गुन, शक संवत् 1880
(6 मार्च, 1959 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 202 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५९

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, ६ मार्च, १९५९

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३५६

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्या प्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार सिन्हा, डाक्टर
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आनन्द ब्रह्मशाह, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फर्तासिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशव राम, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवाल सिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगा प्रसाद सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेश प्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गया प्रसाद, श्री
ग़यूर अली खां, श्री
ग़रीबदास, श्री

गिरधारी लाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
गोविन्द सिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिका प्रसाद, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजी लाल जाटव, श्री
छत्तर सिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीश नारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुना सिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
जुगल किशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकी सिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथ प्रसाद, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिका प्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नवल किशोर, श्री
नागेश्वर प्रसाद, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुर सिंह, श्री
प्रतापभान प्रकाशसिंह, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री

बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालक राम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारी लाल, श्री
बुलाकी राम, श्री
बूजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भोखालाल, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मदन गोपाल वैद्य, श्री
मदन मोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखान सिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुट बिहारी लाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद फ़ारूक चिश्ती, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
मोहन लाल वर्मा, श्री
मोहन सिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपाल सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथ सहाय यादव, श्री
रघुरनतेज बहादुर सिंह, श्री
रघुवीर राम, श्री
रघुवीर सिंह, श्री (एटा)
रघुवीर सिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुर सिंह, श्री
रमाकांत सिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री

रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखन सिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमी सिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथ सिंह, श्री
वजरंगबिहारी लाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती

सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुर शाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्र सिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
हरदयाल सिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्र सिंह, श्री
हरिहरबख्श सिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री, श्री महावीर सिंह, भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, ६ मार्च, १९५९

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

वित्त विभाग के श्री मधुसूदन चक्रवर्ती के कार्यकाल में वृद्धि

१—श्री प्रतापसिंह** (जिला नैनीताल)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ५८ वर्ष की उम्र पूरा कर लेने के बाद वित्त विभाग में पिछले २ वर्षों में कितने अधिकारियों तथा कर्मचारियों को कार्यकाल वृद्धि (extention) दिये गये हैं तथा कितनों को यह वृद्धि देने का प्रश्न इस समय विचाराधीन है ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—५८ वर्ष की उम्र पूरी कर लेने के बाद वित्त विभाग में पिछले दो वर्षों में केवल एक अधिकारी को कार्यकाल वृद्धि (extention) दी गई है। उस विभाग के कर्मचारियों में से किसी को भी ऐसी कार्यकाल वृद्धि नहीं दी गयी। इसके अतिरिक्त इस समय किसी अन्य को यह वृद्धि देने का प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

श्री प्रतापसिंह—क्या यह सही है कि सरकार ने नीति बनाई है कि ५८ वर्ष के बाद किसी को ऐक्सटेंशन नहीं दिया जायगा ? यदि हां, तो इनको ऐक्सटेंशन देने का क्या कारण है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सम्भव है माननीय सदस्य ने आर्डर देखा भी होगा उसमें यह है कि साधारणतया एक्सटेंशन नहीं दिया जाता, लेकिन अगर किसी स्पेशल केस में देना हो तो दिया जा सकता है।

श्री प्रतापसिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह कौन व्यक्ति है जिनको एक्सटेंशन दिया गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इनका नाम श्री मधुसूदन चक्रवर्ती है और असिस्टेंट सेक्रेटरी वित्त विभाग में हैं।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—जब ५५ से ५८ तक अवधि बढ़ा दी गई है तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि इसके बाद कोई एक्सटेंशन न दिया जाय और नीचे के लोगों को ही प्रमोट किया जाय ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—साधारणतया ऐसा ही होता है और बहुत कम ऐसे केसेज मिलेंगे जिनमें एक्सटेंशन दिया गया है। लेकिन जब कोई आदमी कोई खास काम करता है तो जरूरत प्रतीत होती है कि उसी के द्वारा वह काम पूरा हो जाय। ऐसी हालत में जरूरी हो जाता है कि उसको सार्वजनिक हित में एक्सटेंशन दिया जाय।

तारांकित प्रश्न

विधायकों को आवास व्यवस्था

*१—श्रीमती राजेन्द्र किशोरी (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या वह रायल होटल, लखनऊ में निर्मित फैमिली सूट्स को विधायक निवास घोषित करने का विचार कर रही है ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

*२—श्रीमती राजेन्द्र किशोरी (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश के विधान मंडल के सदस्यों में से कितने सदस्यों की आवास की व्यवस्था १५ अक्तूबर, १९५८ तक नहीं हो सकी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—१८ सदस्यों के आवास की व्यवस्था १५ अक्तूबर, १९५८ तक नहीं हो सकी थी।

हायर सेकेण्डरी स्कूल, खुदौली को अनुदान न मिलना

*३—कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जौनपुर जिले में कुल कितने स्कूल ऐसे हैं जिन्हें मान्यता मिले ५ साल से अधिक हो गया पर अभी तक उन्को सरकार की ओर से स्थायी अनुदान नहीं प्राप्त हुआ ?

स्वायत्त शासन उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—केवल दो।

*४—कुंवर श्रीपाल सिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला जौनपुर की तहसील शाहगंज के ग्राम खुदौली के ऐसे ही सर्वोदय हायर सेकेंडरी स्कूल को किन कारणों से अब तक अनुदान नहीं मिला है ?

श्री रामस्वरूप यादव—(१) अयोग्य अध्यापक, (२) अपर्याप्त भवन।

*५—कुंवर श्रीपाल सिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त प्रश्न में कहे गये स्कूल में कुल कितने प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—उक्त विद्यालय में २१.४९ प्रतिशत अनुसूचित जाति के और ४३.८६ प्रतिशत पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं।

कुंवर श्रीपाल सिंह—क्या मंत्री जी उन विद्यालयों के नाम बतायेंगे जो मान्यता प्राप्त हैं परन्तु उनको अनुदान नहीं मिलता ?

श्री रामस्वरूप यादव—सर्वोदय हायर सेकेंडरी स्कूल, खुदौली; खेतासराय, जौनपुर और हायर सेकेंडरी स्कूल, नेवटिया, जौनपुर।

कुंवर श्रीपाल सिंह—जैसा कि प्रश्न ४ के उत्तर में कहा गया है कि 'अयोग्य अध्यापक और अपर्याप्त भवन' तो क्या इस स्कूल में चूंकि ६४ प्रतिशत पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों के बच्चे पढ़ते हैं, इसको देखते हुये भवन निर्माण के लिये सरकार कोई अनुदान देने की कृपा करेगी ?

श्री रामस्वरूय यादव—अभी तो ऐसा सवाल नहीं है, जब यह प्रिलिमिनरी ग्रांट की लिस्ट में आ जायगा तो विचार किया जा सकता है।

कुंवर श्रीपाल सिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस स्कूल को रिकगनाइज्ड हुये ७ साल से अधिक हो गये हैं तो अब तक यह प्रिलिमिनरी ग्रांट की लिस्ट में क्यों नहीं आया ?

श्री रामस्वरूप यादव---मैंने निवेदन किया कि कुछ आवश्यक शर्तें हुआ करती हैं जो पूरी होनी चाहिये प्रिलिमिनरी ग्रांट की लिस्ट में आने के लिये। उनके पास पर्याप्त भवन नहीं हैं और उतने ट्रेन्ड अध्यापक भी नहीं हैं जितने कि होने चाहिये।

इटावा जिले में बाल विवाह संबंधी मामले

*६---**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल** (जिला आगरा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले में सन् ५४ से ५८ तक बाल विवाह के कितने केसों में सरकार के यहां दरख्वास्तें आईं? उसमें कितने के ऊपर कार्यवाही हुई?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)---इटावा जिले में सन् १९५४ से सन् १९५८ तक बाल विवाह की २४ शिकायतें आईं जिनमें २ पर उचित कार्यवाही की गई।

*७---**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कितने केस पुलिस ने ५७ से ५८ तक अपने आप बाल विवाह के इटावा जिले में पकड़े?

श्री बलदेव सिंह आर्य---चूंकि चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन्ट ऐक्ट के अन्तर्गत पुलिस को अपने आप कार्यवाही का अधिकार नहीं है, अतः पुलिस ने कोई केस नहीं पकड़ा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार यह बतायेगी कि दो के मामले में जो उचित कार्यवाही की गयी वह क्या कार्यवाही की गयी?

न्याय मंत्री (श्री हुकुम सिंह विसेन)---मुकदमा चला, आखिर में सबूत नाकाफी होने से खारिज हो गया और मुल्जिम डिस्चार्ज हो गये।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि शेष २२ पर कार्यवाही क्यों नहीं की गयी?

श्री हुकुम सिंह विसेन---१५ में पार्टीज ने सुलह कर ली आपस में और ७ मुकदमों में मुद्दई गैरहाजिर हो गये। इस वजह से वह खारिज हो गये।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो मुकदमे चलाने के बाद खारिज हो गये उनमें लड़के-लड़कियां जिनकी शादियां हुई थीं वह नाबालिग नहीं पाये गये डाक्टरी जांच में?

श्री हुकुम सिंह विसेन---जो सबूत पेश किया गया वह इतना नाकाफी था कि उसमें चार्ज भी फ्रेम नहीं हो सका।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिन मामलों में समझौता हो गया उसके आधार क्या-क्या थे?

श्री हुकुम सिंह विसेन---यह फरीकेन से पूछ लीजिये। मुझ से क्या पूछते हैं?

इटावा जिले में सामाजिक असमर्थता निवारण कानून संबंधी अभियोग

*८---**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सामाजिक असमर्थता निवारण कानून के कितने केस सरकार ने अपने आप इटावा जिले में ५५ से ५८ तक चलाये और उनमें क्या कार्यवाही हुई?

श्री रामस्वरूप यादव---१९५८ में १ केस चलाया गया और अभियुक्तों को निर्दोष पाकर छोड़ दिया गया।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार यह बतायेगी कि इन तीन सालों के भीतर सरकार के पास कितनी शिकायतें आयीं जिनमें से एक केस चलाया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव---इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री शिव प्रसाद नागर---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इन मुकदमों में भी कोई सुलहनामा दाखिल हुआ ?

श्री अध्यक्ष---इसमें जवाब दिया गया है कि अभियुक्तों को निर्दोष पाकर छोड़ दिया गया है। तो क्या आप अन्य किसी मुकदमे के बारे में पूछ रहे हैं ?

श्री शिवप्रसाद नागर---मैं पूछ रहा हूं कि कोई सुलहनामा भी दाखिल हुआ ?

श्री रामस्वरूप यादव---मैंने निवेदन किया कि एक ही मुकदमा चलाया गया और वह निर्दोष साबित हो गया। सुलहनामा किस का हुआ यह मैं समझ नहीं सका।

***९-१०---कुंवर श्रीपाल सिंह**---[सोलहवें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या १-२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

पट्टी पुरवा निवासी श्री मंगूलाल के घर मारपीट की घटना

***११---श्री शिव प्रसाद नागर**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रेलवे स्टेशन अरनी खाना के सामने ग्राम पट्टी पुरवा, जिला खीरी में सन् ५७ में कोई डकैती अशरफी कुर्मी के यहां पड़ी थी ?

श्री रामस्वरूप यादव---कथित वर्ष में श्री अशरफी कुर्मी के यहां कोई डकैती नहीं पड़ी। हां, उसके भाई श्री मंगूलाल के मकान पर एक घटना दिनांक १६/१७-१०-५७ की रात्रि को घटी जो विवेचना करने पर डकैती नहीं पाई गई ?

***१२---श्री शिव प्रसाद नागर**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पट्टी पुरवा की डकैती की सूचना स्टेशन मास्टर अरनी खाना ने मेमो भेजकर कोतवाली लखीमपुर को दी थी ?

श्री रामस्वरूप यादव---ऐसे किसी मेमो की आमद तथा सूचना कोतवाली, लखीमपुर में अंकित होना नहीं पाया गया।

***१३---श्री शिवप्रसाद नागर**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस डकैती में कितनी गिरफ्तारी हुई और कितने मुलजिम फरार रहे ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्री मंगूलाल के मकान पर घटित घटना के सम्बन्ध में एक मुकदमा धारा १४८, ४५२, ३०७ ताजीरात हिन्द के अन्तर्गत थाना कोतवाली में ५ अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अंकित किया गया। विवेचना से मुकदमा लापता रहा और अभियुक्तों का कुछ पता न चल सका।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अशरफी और मंगूलाल एक ही मकान में रहते थे, जहां यह घटना हुई ?

श्री रामस्वरूप यादव---जो थाने में रिपोर्ट हुई है वह मंगूलाल की ओर से हुई है। यह कहना कि वे एक ही मकान में रहते हैं इसके लिए नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो खीरी के स्टेशन मास्टर ने मेमो भेजा वह मेमो जानबूझ कर कोतवाली में न दाखिल करके बल्कि गायब कर दिया गया और रेलवे स्टेशन पर उसका इन्दराज मौजूद है ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, मेमो अगर कोई भेजा गया होगा तो उसका पता नहीं चल सका लेकिन कोई मंशा भी गायब करने की इस वजह से नहीं हो सकती कि मंगूलाल ने अपनी तहरीरी रिपोर्ट भेजी है थाने में और वहां की पुलिस चौकी ने फोन से कोतवाली को इत्तला दी कि कुछ आवाजें बन्दूक की आयी हैं जिससे मालूम पड़ता है कि डकैती पड़ रही है। उसके बाद पुलिस जितनी जल्दी पहुंच सकती थी पहुंच गई।

कुंवर श्रीपाल सिंह---माननीय मंत्री जी ने कहा कि डकैती नहीं हुई कुछ और हुआ, तो कुछ और क्या चीज हुई ?

श्री रामस्वरूप यादव---डकैती नहीं पायी गई। मैंने यह बतलाया कि यह नहीं साबित हुआ कि डकैती पड़ी थी। विवरण मेरे पास है अगर श्रीमन् आज्ञा दें तो मैं बता दूं ?

श्री अध्यक्ष---आप संक्षेप में दे दीजिये ।

श्री रामस्वरूप यादव---१६/१७ अक्तूबर की रात्रि में ग्राम पट्टी पुरवा में मंगूलाल के मकान पर एक घटना १४८ धारा के अन्तर्गत हुई जिसकी रिपोर्ट पांच अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अंकित है। उपरोक्त घटना के ऊपर कोतवाली पुलिस द्वारा विवेचना हुई। घटना इस तरह बतलाई गई है। उसकी रिपोर्ट मेरे पास है श्रीमन् अगर आवश्यक हो तो उसका सारांश मैं बतला दूं ?

श्री अध्यक्ष---नहीं-नहीं, आप यह बतलाइए कि वह डकैती नहीं थी तो क्या थी ?

श्री रामस्वरूप यादव---उन्होंने यह रिपोर्ट की थी कि दो बजे उनके मामा फकीरा जानवरों को चारा डालने के लिए घर से बाहर निकले। उन्होंने देखा कि मकान के सामने से पांच आदमी रास्ता गुजर रहे हैं। टोंका कि कौन है। इतने पर उन्होंने मेरे मामा को थप्पड़ों से मारा। मामा घर में शोर मचाते हुए भागे। उनके पीछे पांचों आदमी घर में घुस आये। मैं भी उठकर आगे बढ़ा तो उन्होंने मेरे भी थप्पड़ मारे। शोर मचाने पर गांव के लोग दौड़ आये। जैसी कि रिपोर्ट है उन्होंने यह भी लिखा है कि मेरे छुरें भी लगे। इससे स्पष्ट है कि मारपीट हुई और अगर छुरें भी लगे हैं तब भी दफा ३०७ का ही मुकदमा बनता था डकैती नहीं थी।

कुंवर श्रीपाल सिंह---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब बन्दूकें चलीं, छुरें लगे तो क्या वे लोग किसी दूसरे काम से आये थे या डाका डालने की नीयत से ही आये थे ?

श्री रामस्वरूप यादव---नीयत पर कोई मुकदमा नहीं चला करता है। जैसा आफेंस होता है वह, उस धारा में माना जाता है।

श्री देवनारायण भारतीय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जब ३०७ का नुमं दर्ज किया गया तो उस मारपीट का मोटिव क्या था ?

श्री रामस्वरूप यादव---मोटिव तो तब मालूम होता जब कि पता चलता कि कौन-कौन अभियुक्त थे। यह तो पता नहीं चल सका। लापता केस वह रहा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उनके पास इसकी भी सूचना है कि मंगूलाल और अशर्फी उन लोगों ने पहले कुछ व्यक्तियों के खिलाफ थाने में कोई शिकायत की थी ?

श्री रामस्वरूप यादव---ऐसी सूचना सरकार के पास नहीं है।

शिव प्रसाद गुप्त हास्पिटल, वाराणसी में होम्योपैथिक सेक्शन खोलने की प्रार्थना

*१४—श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि २७-८-५८ को वाराणसी के कुछ नागरिकों एवं होमियोपैथिक प्रेमी लोगों ने महामहिम राज्यपाल को शिवप्रसाद गुप्ता हास्पिटल, वाराणसी में एक होमियोपैथिक सेक्शन खोलने के निमित्त आवेदन-पत्र दिया है ? यदि हां, तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—जी हां। वाराणसी के नागरिकों का यह सुझाव अस्वीकार कर दिया गया है परन्तु यह पत्र दिनांक १५ सितम्बर, १९५८ का था।

*१५—श्री मुक्तिनाथ राय—क्या न्याय मंत्री उस आवेदन-पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—आवश्यक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६५३ पर)

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या माननीय न्याय मंत्री जी बतायेंगे कि जब वाराणसी के अच्छे तजुर्बेकार होम्योपैथ डाक्टर फ्री सर्विस करने को तैयार हैं तो नागरिकों का सुझाव अस्वीकार करने का क्या कारण है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—एक म्यान में एक ही तलवार रहती है।

*१६—१८—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—[राजस्व मंत्री से सम्बन्धित, चौबीसवें बुधवार के लिये प्रश्न संख्या १-३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

गैस्ट्रोइंट्राइटिस से मृत्युएं

*१९—श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जुलाई-अगस्त सन् १९५८ ई० में प्रदेश भर में गैस्ट्रोइंटेरिटिस (Gastro enteritis) रोग से कितने मनुष्य पीड़ित हुये ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—जुलाई-अगस्त, १९५८ ई० में प्रदेश भर में ६,३६६ मनुष्यों के गैस्ट्रोइंटेरिटिस (Gastro enteritis cum cholera) से पीड़ित होने की सूचना मिली है।

*२०—श्री गनेशीलाल चौधरी—इनमें से कितने मनुष्य मर गये ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—इनमें से २,१८३ मनुष्यों के मर जाने की सूचना मिली है।

श्री गनेशीलाल चौधरी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस रोग से मुकाबिला करने के लिए सरकार ने क्या योजना बनाई है ?

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—अनाज कम मिले यही योजना बनाई है।

श्री हुकुम सिंह विसेन—यह तो आपने बनाई है। हमने जो बनाई है वह मैं बताता हूं। इसके लिए दवाइयां भेजी जाती हैं, आइसोलेशन अस्पताल भी खोल दिए जाते हैं। कुएं वगैरह, मकानात वगैरह जो एफेक्टेड होते हैं उनको डिसइनफेक्ट किया जाता है और इस तरह से तमाम सफाई वगैरह का प्रबन्ध किया जाता है।

श्री गेंदासिंह—क्या यह बतलाना सम्भव है कि यह जो मौतें हुईं और इस प्रकार की मौतें पिछले दो तीन वर्षों से गैस्ट्रोइंट्राइटिस से असाधारण रूप से होती रहीं तो इसको देखते हुए सरकार ने इसको रोकने के लिए क्या किया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---मैंने पहले बताया जहां कहीं से शिकायत आती है फौरन इन्तजाम किया जाता है बिना किसी ताम्मुल के ।

श्री गेंदासिंह---क्या यह बात सही है कि इस संख्या को देखते हुए यह बीमारी दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---अब तो ज्यादा कंट्रोल मालूम होता है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या माननीय मंत्री जी इस बीमारी के संबंध में दिए हुए आश्वासन को देखते हुए बता सकेंगे कि इस बीमारी के संबंध में क्या-क्या नई खोज की जा सकी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---हम जो नई खोज होती हैं उन्हीं के अनुसार काम करते हैं । हमने जो बताई वही हैं ।

आजमगढ़ जिले में भ्रष्टाचार के मुकदमे

*२१---श्री मुक्तिनाथ राय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ के स्पेशल जज के इजलास में १ जनवरी, ५८ से लेकर ३० जून, ५८ तक कितने भ्रष्टाचार के मुकद्दमें धारा १६१ आई० पी० सी० और धारा ५ (२) प्रीवेन्शन आफ करप्शन ऐक्ट (Prevention of Corruption Act) के अन्तर्गत निर्णित किये गये ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---दो ।

श्री मुक्तिनाथ राय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन दोनों केसेज में मुलजिमों को सजा हुई या छूट गये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हाई कोर्ट ने इस के बारे में कोई मैटेरियल नहीं दिया है । इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है । मैं जवाब नहीं दे सकता हूं ।

श्री मुक्तिनाथ राय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ऐसी शिकायत आई है कि स्टेट बनाम दुर्गा दयाल के मुकदमे में वर्तमान सरकारी वकील ने मुलजिम पक्ष से मिलकर केस को खराब किया ? इस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---ऐसी कोई नोटिस आई मुझे मालूम नहीं देती ।

बेसिक स्कूल, लालबाग, लखनऊ का भवन न होना

*२२-श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लालबाग, शहर लखनऊ में बेसिक प्राइमरी स्कूल का भवन आठ साल से नहीं है और उपर्युक्त स्कूल के बच्चे विधायक निवास नम्बर १ के हाते में जमीन पर खुले मैदान में पढ़ते हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां , न तो कोई किराये का भवन ही मिला और न नवीन भवन निर्माणार्थ भूमि ही प्राप्त हो सकी ।

*२३---श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---[२० मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

*२४---२६---श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह (जिला गोंडा) व श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---[हटा दिये गये ।]

*२७-२८---श्री राम समझावन (जिला जौनपुर)---[२० मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये ।]

बैकवर्ड क्लासेज कमीशन की सिफारिशें

*२९---श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)---क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बैकवर्ड क्लासेज कमीशन की रिपोर्ट में की गई उन सिफारिशों को जिनका सम्बन्ध राज्य सरकार से है कार्यान्वित करने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री रामस्वरूप यादव---भारत सरकार ने अभी बैकवर्ड क्लासेज कमीशन की रिपोर्ट पर कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया है। भारत सरकार से पत्र-व्यवहार चल रहा है उसके निर्णय पर ही अन्य कार्यवाही संभव होगी ।

श्री रामशरण यादव---क्या माननीय मन्त्री जी कृपया बतलायेंगे कि उत्तर प्रदेशीय सरकार ने इस कमीशन की रिपोर्ट लागू किये जाने या न लागू किये जाने के बारे में अपनी सिफारिश में केन्द्रीय सरकार को क्या लिखा है और कब लिखा है ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, केन्द्रीय सरकार और प्रदेशीय सरकार के बीच लिखा पढ़ी का यहां पर उल्लेख करना मुनासिब नहीं होगा ।

श्री रामशरण यादव---क्या माननीय मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार का अपना निर्णय इस बारे में क्या है ?

श्री रामस्वरूप यादव---इस सम्बन्ध में जो कुछ भी जरूरी समझा गया है वह कर दिया है । उनकी शिक्षा के लिये जो खर्चा हो उसके लिये अनुदान दिया जा रहा है । जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा रुपया दिया जाता है और साथ ही यह प्रयत्न किया जाता है कि उनको सर्विसेज में प्रिफरेन्स दिया जाय ।

श्री रामशरण यादव---क्या माननीय मन्त्री महोदय कृपया बतायेंगे कि सर्विसेज में रिजर्वेशन के बारे में उत्तर प्रदेशीय सरकार ने अपना क्या फैसला किया है ?

श्री रामस्वरूप यादव---फैसला नहीं किया है, लेकिन रिजर्वेशन करना मुनासिब नहीं होगा। अगर संख्या देखी जाय तो १२० जातियां हैं जो उस कमीशन की राय में उत्तर प्रदेश में बैकवर्ड कही जाती हैं और उनकी जनसंख्या २,७०,००,००० होगी ।

विधायकों को आवास भत्ता

*३०---श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उन विधायकों की संख्या क्या है जिन्हें सरकार निवास न मिलने का एलाउन्स देती है ?

श्री रामस्वरूप यादव---अप्रैल, १९५७ से दिसम्बर, १९५८ तक लखनऊ स्थित विधायक निवासों में आवास के लिये स्थान न मिलने के बदले में क्षतिपूरक भत्ता पाने वाले सदस्यों की संख्या की तालिका मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६५४ पर)

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या मन्त्री महोदय बतालायेंगे कि यह जो सूची दी गई है इसमें ५७ में ५४ संख्या दी गई है और दिसम्बर, ५८ में १०२ को भत्ता दिया गया तो इतनी संख्या बढ़ने का क्या कारण है ?

श्री रामस्वरूप यादव---सन् १९५७ में जिन लोगों ने मांग की थी उनकी संख्या ५४ थी और दिसम्बर, १९५८ में आवास का प्रबन्ध नहीं था तो उस समय भत्ता पाने वालों की संख्या १०२ हो गई और इतने लोगों को भत्ता दिया गया ।

श्री कल्याण चन्द मोहिले---क्या माननीय मन्त्री महोदय बतलायेंगे कि इस समय कितने कमरों में विधायक लोग रह रहे हैं और कितने लोगों ने रहने के पहले छोड़ दिया है ?

श्री रामस्वरूप यादव---मैं समझ नहीं सका कि आपका क्या मन्शा है ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---मैं यह जानना चाहता हूं कि इस समय जितने विधायक रह रहे हैं और इसके पहले जितने रहते थे उनमें कुछ कमी हुई है ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां, कुछ लोग जो एक-एक कमरे में दो-दो रहते थे उन्होंने कमरा छोड़ कर भत्ता क्लेम किया है कि हमने कमरा छोड़ दिया है और हमें कमरे की जरूरत नहीं है । इस वक्त स्थिति यह है कि ९८ व्यक्ति ऐसे हैं जो यह चाहते हैं कि उनको कमरा न दिया जाय । वे भत्ता चाहते हैं । २३ व्यक्ति ऐसे हैं जो यह चाहते हैं कि उनको कमरा दिया जाय लेकिन इस वक्त कमरों की कमी की वजह से कमरे नहीं दिये जा सकते ।

श्री प्रताप सिंह---क्या माननीय मन्त्री जी इस समय की अपनी नीति को स्पष्ट करने की कृपा करेंगे कि उनकी नीति भत्ता देने की है या निवास स्थान बढ़ाकर फिर उनको कमरा देने की है ?

श्री रामस्वरूप यादव---नीति तो कमरा बनाकर कमरा देने की है लेकिन जब तक कमरे नहीं हैं तब तक भत्ता देने की है ।

श्री प्रताप सिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि कब तक उनका स्टेट डिपार्टमेंट यह व्यवस्था करने की कृपा करेगा ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, अभी कुछ कमरे तैयार हुये है और आशा है कि ४० कमरे जल्दी ही तैयार हो जायंगे । दरख्वास्तें इस वक्त २३ हैं जैसा कि मैंने निवेदन किया । मैं समझता हूं कि जो कमरा पाने के इच्छुक होंगे उनको कमरा मिल जायगा, लेकिन भत्ता पाने वाले भी कमरा चाहेंगे तो फिर जब बजट में रुपया होगा तो कमरे बनाये जायंगे ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---जो ४० कमरे तैयार होने जा रहे हैं वह कब तक तैयार हो जायंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव---ठीक समय तो बताना मुमकिन नहीं है, लेकिन काम जारी है और माननीय पालीवाल जी के रास्ते में वह पड़ते हैं ।

श्री शिवप्रसाद नागर---इस समय कितने कमरे खाली हैं और किस-किस विधायक निवास में ?

श्री रामस्वरूप यादव---पुराने रायल होटल में शायद एक आध सूट्स खाली हैं ।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या यह सही है कि कमरा न पाने वालों में सबसे अधिक संख्या सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों की है और बार-बार कहने पर भी उनको कमरा नहीं मिल सका ?

श्री रामस्वरूप वर्मा---कमरे तो पार्टी के आधार पर नहीं दिये जाते हैं । विधायकों में जिसकी जैसी दरख्वास्त होती है उस हिसाब से दिये जाते हैं ।

श्री रामस्वरूप यादव---क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि हर पार्टी को अनुपात के हिसाब से कमरे दिये जायं ?

श्री रामस्वरूप यादव---मेरा खयाल है कि अनुपात के हिसाब से दिये गये तो सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों को घाटा रहेगा । उनको कम कमरे मिलेंगे । कांग्रेस पार्टी के सदस्यों की संख्या बहुत काफी है ।

श्री प्रताप सिंह---रायल होटल के कमरों के एलाटमेंट में क्या सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि बर्लिगटन होटल में जो लोग रहते हैं और जिनके लिये २५० रुपया मासिक किराया दिया जाता है उनको पहले कमरे दिये जायं ?

श्री रामस्वरूप यादव---नहीं, जिनको कमरे नहीं मिल सक हैं, उनको पहले दिये जायंगे ।

श्री रामस्वरूप वर्मा---जिन लोगों को पहले से कमरे नहीं मिले हैं उनको छोड़ कर क्या कुछ ऐसे लोगों को कमरे दिये गये हैं जिनके पास पहले से कमरे थे ?

श्री रामस्वरूप यादव---इस आदरणीय सदन के सदस्यों को कैसे-कैसे कमरे मिले हैं इसकी व्याख्या नहीं है, लेकिन जिसको जैसी जरूरत थी उसको वैसे कमरे दे दिये गये, यह मैं समझता हूं ।

गाजीपुर जिले में पुलिस स्टेशन इंचार्ज के क्वार्टर तथा हरिजन व पिछड़े वर्ग के अध्यापक

*३१---**श्री यमुना सिंह** (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या गाजीपुर जिले में कुछ पुलिस स्टेशन इन्चार्ज के क्वार्टर अभी तक कच्चे भवनों में हैं ? यदि हां, तो कितने ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां, गाजीपुर जिले में पांच पुलिस स्टेशन इंचार्ज के क्वार्टर अभी कच्चे हैं ।

*३२---**श्री यमुना सिंह** (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में कुल कितने अध्यापक प्राइमरी स्कूलों तथा जूनियर हाई स्कूलों में वर्तमान समय में कार्य कर रहे हैं ? उसमें कितने हरिजन हैं तथा कितने पिछड़े वर्ग के हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---गाजीपुर जिले में प्राइमरी स्कूलों तथा जूनियर हाई स्कूलों में कुल १,६२९ अध्यापक हैं। इनमें ८६ हरिजन हैं तथा २०५ पिछड़े वर्ग के हैं।

पहाड़ी जिलों में प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के विरुद्ध शिकायत

*३३---**श्री प्रताप सिंह**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या उसकी ऐसी नीति है या आदेश है कि पहाड़ी जिले अल्मोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल के अपर प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापकों को यथासम्भव अपने निवासस्थान के गांवों की पाठशालाओं में नियुक्त किया जाय ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी नहीं ।

*३४---**श्री प्रताप सिंह**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अल्मोड़ा जिले के स्थानीय शिक्षा विभाग के अधिकारियों से इस सम्बन्ध में शिकायतें की गई हैं कि वहां के अधिकांश अध्यापक जो अपने निवास स्थान के गांवों की पाठशालाओं में कई वर्षों से लगातार कार्य कर रहे हैं, मन लगाकर कार्य नहीं करते और पाठशाला का अधिकांश समय अपने घरेलू कार्य में व्यतीत करते हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां, कूछ अध्यापकों के विरुद्ध शिकायतें की गई हैं।

*३५---**श्री प्रताप सिंह**---क्या सरकार शिक्षा विभाग तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को आवश्यक आदेश देकर इस प्रकार की व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करने का विचार रखती है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी नहीं ।

श्री प्रताप सिंह—क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पर्वतीय प्रदेश की जलवायु भिन्न है वहां के अध्यापकों को मैदान न भेजने का कोई आदेश जारी करने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—ऐसे आदेश तो जारी नहीं किये जा सकते कि जिसमें उसको कोई खास फायदा किया जा सके ।

श्री प्रताप सिंह—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को सूचना मानते हुए कि पिछले चुनाव में बहुत से अध्यापकों को प्लेन्स भेज दिया गया, उनको अपनी जगह भेजने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—ऐसी सूचना नहीं है कि अध्यापकों को प्लेन्स किसी नुकसान की वजह से भेज दिया गया । जो एडमिनिस्ट्रेटिव दृष्टिकोण था, अधिकारियों ने जो मुनासिब समझा होगा किया होगा और जो अधिकारी आज हैं वह ठीक ही करेंगे, सरकार यह आशा कर सकती है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—जो शिकायतें सरकार के पास आयी हैं उनके संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री रामस्वरूप यादव—ऐसी शिकायतें थीं जिनका संबंध उन अध्यापकों से था और यह स्थानीय संस्थायें हैं, उनका कर्त्तव्य है कि वह अपने अध्यापकों को जहां जरूरत समझें रखें । लिहाजा सरकार इस बीच में ज्यादा आती नहीं ।

श्री प्रताप सिंह—क्या यह सही है कि अभी तक इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रान्सफर्स नहीं हुआ करते, तो क्या सरकार वहां की जो जिला अन्तरिम परिषद् है उसको ऐसे आदेश देगी कि इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रान्सफर्स हो सकें ?

श्री रामस्वरूप यादव—वह तो जिला परिषद् के कर्मचारी होते हैं, ऐसा नहीं हो सकता ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—क्या सरकार को यह मालूम है कि अध्यापकों का मन लगाकर काम न करने का एक कारण यह भी है कि पहले अध्यापकों के जिम्मे केवल ३३ लड़के पढ़ाने के लिये होते थे और अब ५० कर दिये गये हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—सरकार की राय में यह सही नहीं है ।

बाराबंकी जिले में समाजवादियों की मांगें

*३६—श्री जंगबहादुर वर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या जिला बाराबंकी में जिलाधीश के बगले पर सोशलिस्ट पार्टी के लोगों ने २९ नवम्बर, १९५८ को प्रदर्शन किया था ? यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगें क्या थीं और उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां । प्रदर्शनकारियों की मांगें संलग्न तालिका "अ" में दी हुई हैं । उनमें से प्रथम चार मांगों पर जो कार्यवाही की गई है उसका विवरण संलग्न तालिका "ब" में दिया गया है । शेष मांगें अभी विचाराधीन हैं ।

श्री जंगबहादुर वर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मुख्य मांगें कौन-कौन सी थीं ?

श्री रामस्वरूप यादव---जो शोशलिस्ट पार्टी की प्रादेशिक स्तर की मांगें हैं वह सब हैं और केन्द्रीय स्तर की जो मांगें हैं वह सब हैं और इस तरह से कुल २३ हैं। अगर आप आज्ञा दें तो मैं पढ़कर सुना दूं।

श्री अध्यक्ष---आपने कापी तो दे दी होगी ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां।

श्री जंगबहादुर वर्मा---मुझे उत्तर नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष---यह प्रश्न बहुत लम्बा है इसलिये इसकी कापी मैं इस वक्त नहीं करा सकता हूं। इसको मैं मुल्तवी कर देता हूं और यह किसी दूसरे दिन ले लिया जायगा।

श्री जंगबहादुर वर्मा---श्रीमन्, किस दिन उत्तर मिलेगा ?

श्री अध्यक्ष---आपके पास अगर कोई जानकारी हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं वरना यह किसी दूसरे रोज होगा।

[प्रश्न ३६ स्थगित किया गया।]

*३७-३८---**श्री कल्याणचन्द मोहिले**---[२० मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

*३९---**श्री यमुना सिंह**---[२० मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

खेड़ा बझेड़ा परगने में अस्पताल की आवश्यकता

*४०---**श्री रूम सिंह** (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या परगना खेड़ा-बझेड़ा, तहसील तिलहर, जिला शाहजहांपुर में वह अस्पताल खोलने पर विचार कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी नहीं।

कानपुर में आनरेरी मैजिस्ट्रेटों की बेंच बढ़ाने की प्रार्थना

*४१---**श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा** (जिला कानपुर)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर के आनरेरी मैजिस्ट्रेटों की अदालतों में ३१ दिसम्बर, १९५८ को कितने मुकदमें पेंडिंग थे और कब से पेंडिंग हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---६७५ मुकदमे पेंडिंग थे जिनका ब्योरा नत्थी है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ६५५ पर।)

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो ६७५ मुकदमें पेंडिंग हैं उनमें कितने बेंच नम्बर १ में और कितने बेंच नम्बर २ में हैं ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा---क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मुकदमों की बहुतायत को ध्यान में रखकर जिले की तरफ से जनवरी, १९५८ में सिफारिश हुई थी कि तीसरी बेंच बना दी जाय उसमें क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---तीन बेंचें वहां हैं और चौथी जेरे गौर है।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा---मेरा प्रश्न यह है कि जनवरी, १९५८ में तीसरी बेंच के लिये सिफारिश हुई थी, वह अब तक बन नहीं पाई उसके लिये क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---वही तो मैंने कहा कि विचाराधीन है।

श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—क्या मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जो मुकदमें पेंडिंग हैं उनका मुख्य कारण यह है कि कानपुर के जो आनरेरी मैजिस्ट्रेट्स हैं वे मुकदमा करने के बजाय राजनीतिक कार्यवाही करते रहते हैं ?

श्री हुकुम सिंह [सेन—जी नहीं ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या यह सही है कि कुछ मुकदमे ३–३ साल के हो गये हैं ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—एक साल के ऊपर के १६ मुकदमे हैं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या मन्त्री जी उन कारणों पर प्रकाश डालेंगे जिनकी वजह से इतने ज्यादा मुकदमे पेंडिंग पड़े हैं ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—कुछ में तो सम्मन की तामील में देर हुई और कुछ में मुद्दइयों को सबूत लाने में देर हुई ।

फर्रुखाबाद राजकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल

*४२—श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सरकार फर्रुखाबाद राजकीय हायर सेकेन्डरी स्कूल को इंटर कालेज करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं ।

आगरा जिले में राजनीतिक पीड़ितों को पेन्शन

*४३—श्री गंगाधर जाटव (जिला आगरा)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि गत बजट वर्ष १९५७–५८ में आगरा जिले के कितने राजनैतिक पीड़ितों को पेन्शनें स्वीकृत की गईं ?

श्री रामस्वरूप यादव—२४ व्यक्तियों को ।

श्री गंगाधर जाटव—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५७–५८ में कितने प्रार्थना-पत्र राजनीतिक पीड़ितों के आये और शेष प्रार्थना-पत्र क्या हुये ?

श्री रामस्वरूप यादव—१९५ आवेदन-पत्र नियम के अनुसार न होने के कारण अस्वीकार कर दिये गये और ३३ विचाराधीन हैं ।

*४४—श्री खजान सिंह चौधरी (जिला उन्नाव)—[मुख्य मंत्री से सम्बन्धित १२ मार्च, १९५९ के लिये प्रश्न संख्या ६६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड तथा इलाहाबाद होम्योपैथिक मेडिकल कालेज की लेखा परीक्षा रिपोर्ट

*४५—श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य में रजिस्टर्ड होम्योपैथ्स की ३१ दिसम्बर, १९५८ तक क्या संख्या है और उनमें से दिसम्बर, १९५८ में कितने रजिस्टर्ड हुये ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—३१ दिसम्बर, १९५८ तक रजिस्टर्ड होम्योपैथ्स की संख्या ९,११५ है उनमें से दिसम्बर १९५८ में १८२ रजिस्टर्ड हुए ।

*४६—श्री मदन पांडेय (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्तमान राज्य होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड कब बनाया गया ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—३० अक्तूबर, १९५६ में ।

*४७--श्री मदन पांडेय (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद होम्योपैथिक मेडिकल कालेज की वार्षिक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट सन् १९५५-५६, १९५६-५७ तथा १९५७-५८ सरकार को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रिपोर्टों का संक्षिप्त या विस्तृत विवरण सदन के सम्मुख प्रस्तुत करेगी ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--जी नहीं ।

होम्योपैथों के रजिस्ट्रेशन में चिकित्सा-अवधि तथा आयु का प्रतिबन्ध

*४८--श्री लक्ष्मणराव कदम (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसके पास यू० पी० होमियोपैथिक मेडिकल एसोसियेशन की कार्य समिति की मीटिंग में गत २३ नवम्बर, १९५८ को पास होने वाले उस प्रस्ताव की प्रतिलिपि आई है जिसके अनुसार उसने सरकार से प्रार्थना की है कि होम्योपैथों को रजिस्टर करने के लिये अनिवार्य चिकित्सा की अवधि १० वर्ष के बजाय ५ वर्ष तथा रजिस्टर होने वाले की आयु २८ वर्ष के बजाय २३ वर्ष कर दी जाय ? यदि हां, तो उसने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--जी हां । रजिस्ट्रेशन के लिये अनिवार्य चिकित्सा अवधि तथा आयु क्रमानुसार ५ तथा २३ साल है ही ।

*४९--श्री मुक्तिनाथ राय--[२७ मार्च, १९५९ के लिये प्रश्न संख्या ५९ के अन्तर्गत निर्धारित किया गया ।]

*५०-५२--श्री घनश्याम डिमरी (जिला गढ़वाल)--[२० मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये ।]

*५३-५४--श्री गरीबदास (जिला जालौन)--[हटा दिये गये ।]

पीलीभीत जिले के पुराने हेल्थ अफसर

*५५--श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला पीलीभीत में कितने ऐसे हेल्थ आफीसर हैं जिनको तीन साल से अधिक एक स्थान पर रहते हो गये हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--एक ।

श्री हिम्मत सिंह--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ३ साल से अधिक उनको एक ही स्थान पर रखने का क्या कारण है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--उनके तबादले का मैंने हुकुम दे दिया है ।

*५६-५८--श्री चिरंजी लाल जाटव (जिला एटा)--[२० मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये ।]

*५९--श्री हिम्मत सिंह--[२६ फरवरी, १९५९ को प्रश्न संख्या ९९ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है ।]

फूलपुर में पुलिस चौकी की मांग

*६०--श्री मुरलीधर (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार आजमगढ़ जिला के फूलपुर टाउन में एक पुलिस चौकी बनाने पर विचार कर रही है और इस बाबत जिले से कोई सिफारिश भी आई है ? यदि हां, तो कब तक काम पूरा हो जायगा ?

श्री रामस्वरूप यादव--सरकार के पास अभी कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है, यद्यपि जिल से प्राप्त हुआ संबंधित प्रस्ताव इस समय पुलिस मुख्यालय में विचाराधीन है ।

श्री मुरलीधर---क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रस्ताव जिले से पुलिस मुख्यालय को कब प्राप्त हुआ ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, नोटिस की आवश्यकता है ।

अछनेरा में प्रसूत गृह की आवश्यकता

*६१---**स्वामी विश्वेश्वरानन्द** (जिला आगरा)---क्या न्याय मंत्री करबा अछनेरा में मेटरनिटी होम भी खोलने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---जी नहीं, क्योंकि पंचवर्षीय योजना में मेटरनिटी होम खोलने का कोई प्राविधान नहीं है ।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द---क्या माननीय मंत्री जी इस बढ़ती हुई जनसंख्या के युग में वहां इसी वर्ष मैटरनिटी होम की स्थापना पर विचार करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---जहां मैटरनिटी सेंटर मौजूद हैं, तब तक उसी से काम चलाइये।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द---मैं मंत्री जी को बतलाना चाहूंगा कि वह नाकाफी है और वहां पर कोई उचित व्यवस्था नहीं है ।

*६२---**स्वामी विश्वेश्वरानन्द**---[२० मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

परिगणित तथा पिछड़ी जातियों के सूचना अधिकारी

*६३---**श्री माताप्रसाद** (जिला जौनपुर)---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने जिला तथा सहायक जिला सूचना अधिकारी कार्य कर रहे हैं, उनमें कितने पिछड़ी जाति के और कितने परिगणित जाति के हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---प्रदेश में कुल ५२ जिला सूचना अधिकारी (प्रत्येक जिले में एक तथा एक मुख्यालय पर) तथा २४ अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी कार्य कर रहे हैं । उनमें से एक जिला सूचना अधिकारी और एक अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी परिगणित जाति के हैं तथा एक अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी पिछड़ी जाति के हैं ।

श्री माता प्रसाद---क्या आदरणीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन अधिकारियों की योग्यता क्या होती है ?

श्री रामस्वरूप यादव---नोटिस चाहिये, लेकिन जहां तक मेरा खयाल है जो अब चुने जाते हैं वे कम से कम ग्रेजुएट होते हैं ।

श्री माता प्रसाद---इन पदों पर पिछड़ी जाति के और परिगणित जाति के उम्मीदवारों की अर्जियां ही नहीं आईं या वे रखे ही नहीं गये ?

श्री रामस्वरूप यादव---उस योग्यता के मुकाबले में अच्छे कैंडिडेट्स नहीं आये होंगे । दरख्वास्तें आई होंगी और कमेटी ने विचार किया होगा ।

*६४---**श्री माता प्रसाद**---[२० मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

इटावा कचहरी में सोशलिस्टों की गिरफ्तारी

*६५---**श्री भजनलाल** (जिला इटावा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दिनांक १ अक्तूबर, सन् १९५८ को इटावा कचहरी पर १३ सोशलिस्ट सत्याग्रहियों को गिरफ्तार किया गया और उन पर लाठी चार्ज कर, घसीट कर ठेले में डालकर जेल ले जाया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव---१ अक्तूबर, सन् १९५८ को इटावा कचहरी पर १३ सोशलिस्ट सत्याग्रहियों को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार व्यक्तियों ने जेल जाने में बाधा डाली, अतएव पुलिस को उन लोगों को बलपूर्वक जेल ले जाना पड़ा । सत्याग्रहियों पर किसी प्रकार का लाठी चार्ज नहीं किया गया ।

*६६---**श्री भजनलाल**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला जेल के अस्पताल में कितने घायल व्यक्ति दाखिल किये गये और कितनी-कितनी चोटें कहां-कहां पर हैं तथा घायलों के नाम क्या हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---जिला जेल अस्पताल में कोई भी व्यक्ति दाखिल नहीं किया गया । खींचतान में चार व्यक्तियों को साधारण चोटें आईं । व्यक्तियों के नाम तथा चोटों का विवरण इस प्रकार है :

१---श्री प्रताप सिंह---Abrasion 1 3/4"×1/4" on back of left forearm middle third.

२---श्री देशराज सिंह---Interrupted abrasion in an area of 1"×1 1/2" on left thigh upper third back.

३---श्री राम जीवन शर्मा---Contused wound 1/3"×1/5" on inner side of left half of lower lip.

४---श्री रघुवर दयाल---Abrasion 1/4"×1/4" on left arm lower third back aspect.

श्री भजन लाल---क्या यह सही है कि सत्याग्रहियों को गिरफ्तार करके जबरन ठेलों में बैठाकर १००-१०० मील की दूरी पर छोड़ा गया ?

श्री रामस्वरूप यादव---जो कोई सज्जन थे जबरदस्ती कानून तोड़कर एक एस० डी० एम० की अदालत में घुसे ।

श्री भजन लाल---क्या यह सही है कि जब इस प्रकार से सत्याग्रही दूर छोड़े गये तभी उन १३ व्यक्तियों ने यह समझ कर कि उन्हें भी ऐसे ही दूर ले जाकर छोड़ा जायगा, कहा कि हम पैदल चलेंगे लेकिन उनको जबरदस्ती घसीटकर ठेले में ले जाया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव---यह बात सही नहीं है कि वे पैदल जाने के लिये तैयार थे । वे जेल जाने के लिये ही तैयार नहीं थे, इसलिये पुलिस ने उन्हें जबरदस्ती पकड़कर ठेले में बैठाया ।

श्री भजन लाल---श्री प्रतापसिंह के १ ३/४" × १/४, श्री देशराज सिंह के बाईं जांघ में १" × १ १/२ इंच, श्री रामजीवन शर्मा के होंठों पर १/३" × १/५" और रघुवर दयाल के १/४ × १/४ इंच की चोटें क्या इस बात का सबूत नहीं है कि उन पर लाठी चार्ज किया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव---ये चोटें बहुत मामूली हैं । अंग्रेजी में एब्रेजन जरूर लिखा हुआ है । सरकार को मालूम है कि लाठीचार्ज नहीं हुआ ।

श्री देवनारायण भारतीय---इन चोटों का कारण डाक्टर ने क्या लिखा है कि वे लाठी से आईं या काहे से आईं ?

श्री रामस्वरूप यादव---ये खींचतान में आईं और ठेले में किसी के रगड़ लग सकती है ।

श्री देवनारायण भारतीय---डाक्टर ने उन चोटों के बारे में बाई ब्लन्ट वैपन या बाई ड्रैगिंग ऐसा कारण लिखा है ?

श्री रामस्वरूप यादव---वैसे तो डाक्टर ने यह भी लिखा है कि फ्रिक्शन से लगी हैं और ब्लन्ट वैपन भी लिखा है । लेकिन ब्लन्ट वैपन में ठेले में रगड़ भी आ सकती है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो मेडिकल रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में किसी एक्सपर्ट ने यह भी लिखा है कि खरोंच भी ब्लन्ट वैपन की चोट में ही आता है ?

श्री रामस्वरूप यादव---उस डाक्टर ने यह लिखा है कि अगर गिर कर कोई चोट आये तो उसे भी ब्लन्ट वैपन से ही चोट आना लिखा जाता है ।

श्री उग्रसेन---जैसा कि माननीय मंत्री जी ने फरमाया, लाठी चार्ज होने के बाद क्या डाक्टर ने यह नहीं लिखा है कि जो चोटें लगी हैं वे ब्लन्ट वैपन से ही लगी हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---जैसी चोट होती है उसका अन्दाजा करके लिखा जाता है कि किस वजह से चोट लगी । गिरने से चोट लगने या धक्का लगने से चोट लगने को ब्लन्ट वैपन से चोट लगना ही लिखा जाता है ।

*६७---**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)---[२० मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

बन्दूकों की लाइसेन्स फीस के साथ कथित अतिरिक्त धन की वसूली

*६८---**श्री गोविन्द सिंह विष्ट** (अनुपस्थित)---क्या सरकार ने जिलाधीशों को कोई ऐसे आदेश दिये हैं कि जो लोग बन्दूकों के नये लाइसेंस प्राप्त करते हैं अथवा जो लाइसेंस बदलने आते हैं उनसे विभिन्न सरकारी ऋणों अथवा बचत योजनाओं से रुपया जमा करवाया जाय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी नहीं ।

*६९-७०---**श्री गंगाप्रसाद वर्मा** (जिला एटा)---[२० मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये ।]

*७१---**श्री गंगा प्रसाद** (जिला गोंडा)---[२० मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

*७२---७३---**श्री गज्जूराम** (जिला झांसी)---[२० मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये ।]

मुरादाबाद जिले में अपराध की घटनाएं

*७४---**श्री बुद्धीसिंह** (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)---क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला मुरादाबाद में गत बजट वर्ष में कितनी डकैती, कत्ल और राहजनी हुई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---२० डकैती, ५२ कत्ल और ३० राहजनी हुई ।

*७५---**श्री बुद्धीसिंह** (अनुपस्थित)---क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला मुरादाबाद, तहसील बिलारी में हीरा और बहरिया नाम के दो डकैत फरार हैं और क्या वहां की पुलिस उनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां । पुलिस उनकी गिरफ्तारी का पूरा प्रयास कर रही है ।

स्टाफ कोर्स के अन्तर्गत पुलिस सब-इन्सपेक्टरों की ट्रेनिंग

*७६---**श्री गंगाधर जाटव**---क्या यह सच है कि सरकार ने पुलिस सब-इन्स्पेक्टरों की एक ऐसी नयी ट्रेनिंग जारी की है जिसे रिफ्रेशर कोर्स कहते हैं जिसकी योग्यता पास करने पर उन सब-इन्स्पेक्टरों को स्टेशन आफिसर बनाया जायेगा ?

श्री रामस्वरूप यादव---एतदर्थ रिफ्रेशर कोर्स नहीं अपितु एक स्टाफ कोर्स चालू किया गया है ।

श्री गंगाधर जाटव---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त स्टाफ कोर्स की कितने सब-इन्स्पेक्टरों को ट्रेनिंग दी गयी है और उनमें से कितने सब-इन्स्पेक्टरों को एस० ओ० बनाया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव---यह जो स्टाफ कोर्स है, जो कोई किसी थाने का इंचार्ज या सर्किल इंन्स्पेक्टर होने वाला हो तथा जिसका सेवाकाल ५ वर्ष से १० वर्ष तक का हो, ऐसे जितने सब-इन्स्पेक्टर थे उन सबको स्टाफ कोर्स देना जरूरी था और १६-१६ सब-इन्स्पेक्टरों के दो कोर्स हो चुके हैं ।

श्री प्रताप सिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह रिफ्रेशर कोर्स कितने दिनों का है ?

श्री रामस्वरूप यादव---यह कोर्स तीन महीने का है ।

श्री गंगाधर जाटव---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस ट्रेनिंग में इस साल कितना रुपया खर्च हुआ ?

श्री रामस्वरूप यादव---इस स्टाफ कोर्स में दीक्षा देने के लिये एक सर्किल इन्स्पेक्टर का स्थायी पद स्वीकार हुआ है जिस पर ३,१०० रु० खर्च हुआ है ।

श्री शिव प्रसाद नागर---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि रिफ्रेशर कोर्स की जब ट्रेनिंग दी जाती है तो कोई एक्स्ट्रा एलाउंस भी दिया जाता है ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां, ३० रु० प्रति मास प्रतिकर भत्ता दिया जाता है ।

श्री भगवती सिंह विशारद---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस समय जो कोर्स चलता है उसमें जो परीक्षार्थी हैं उनको कुछ सदाचार की भी शिक्षा दी जाती है ?

श्री रामस्वरूप यादव---कोर्स की फेहरिस्त मेरे पास है, इसमें १७ बातें हैं जो उनके विभाग से सम्बन्धित हैं और इनमें उनको दीक्षा दी जाती है ।

हरिजन कल्याण के लिए केन्द्रीय अनुदान

*७७---**श्रीमती चन्द्रावती** (जिला बिजनौर)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनवरी से दिसम्बर, १९५८ तक कितना धन हरिजन कल्याण मद में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्त हुआ ?

श्री रामस्वरूप यादव---वित्तीय वर्ष १९५७-५८ में १७,९५,५०० रु० प्राप्त हुये ।

श्रीमती चन्द्रावती---क्या सरकार बतलायेगी कि केन्द्रीय सरकार से जो हरिजन कल्याण मद में धन प्राप्त होगा उसको किस किस मद में खर्च करने का विचार है ?

श्री रामस्वरूप यादव---यह बैकवर्ड क्लासेज के वेलफेयर के लिये है । शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये ह और उनके मकान इत्यादि के सुधार के लिये है, टी० बी० पेशेंट्स के सम्बन्ध में है ।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस मद में उत्तर प्रदेश में मेहतरों के क्वार्टर बनाने के लिये भी लिखा है ?

श्री रामस्वरूप यादव---यह तो मुझे ठीक स्मरण नहीं है लेकिन मेहतरों के क्वार्टर्स बनाने के लिये प्रदेशीय सरकार ने नगरपालिकाओं को २ वर्ष हुये रुपया दिया था ।

श्री देवनारायण भारतीय---जो केन्द्रीय सरकार से धनराशि प्राप्त हुई वह वित्तीय वर्ष में सब समाप्त हो गई अथवा उसमें से कुछ शेष रह गयी ?

श्री रामस्वरूप यादव---इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता होगी ।

फर्रुखाबाद जिले के आनरेरी मैजिस्ट्रेट

*७८---**श्री राजेन्द्रसिंह यादव** (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष कितने आनरेरी मैजिस्ट्रेट जिला फर्रुखाबाद से हटे और उनके हटने का क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---कोई नहीं ।

अध्यापकों के बढ़े वेतन के लिए जिला बोर्डों को सहायता देने के सम्बन्ध में जानकारी

*७९---**श्री ऊदल** (जिला वाराणसी)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्राइमरी तथा मिडिल स्कूलों के अध्यापकों की तनख्वाह की बढ़ोत्तरी जुलाई, सन् १९५३ से की गई है ? यदि हां, तो क्या बढ़ोत्तरी का रुपया सभी जिला बोर्डों को भेज दिया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री ऊदल---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जुलाई, १९५३ से दिसम्बर, १९५४ तक की बढ़ोत्तरी सरकार ने हर जिला बोर्ड्स को दे दी है ?

श्री रामस्वरूप यादव---सरकार ने सन् १९५६ से जो बढ़ोत्तरी हुई है सब रुपया उसे दे दिया है । सन् १९५३ से सन् १९५६ के बारे में बढ़ोत्तरी का जो रुपया है वह अनुदान के रूप में हर वर्ष दिया जा रहा है । बाकी रुपया भी दे दिया जायगा । १९५६-५७ में १५,९३,८०० रु०, १९५७-५८ में २९,१६,८२९ रु० और १९५८-५९ में ३०,९४,१६६ रुपया दिया जा चुका है ।

श्री ऊदल---जुलाई, सन् १९५३ से जो बढ़ोत्तरी की गयी वह किस सन् में जिला बोर्डों को दी गयी ?

श्री रामस्वरूप यादव---सन् १९५६ वाली तो सन् १९५६ में ही देना शुरू कर दिया था और १९५६ और १९५३ के बीच में जो है उसे हर साल लम्पसम में दे। जा रहे हैं ।

आनरेरी मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति के लिए समितियां

*८०---**श्री जंगबहादुर वर्मा**---क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आनरेरी मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति के लिये कमेटियां बनती हैं ? यदि हां, तो इन कमेटियों का निर्माण कब हुआ और इनकी अवधि क्या होती है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---जी हां । इन कमेटियों का निर्माण १९५७-५८ वर्षों में हुआ था । इनकी अवधि तीन वर्ष की होती है ।

श्री जंगबहादुर वर्मा---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इन कमेटियों में कौन-कौन व्यक्ति हैं और वे किस पार्टी से सम्बन्धित हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---उनकी लिस्ट तो इस वक्त मेरे पास नहीं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या माननीय मंत्री इस बात को ध्यान में रखते हुए कि किन्हीं-किन्हीं जिलों में ये कमेटियां जो बनी हुई हैं उनमें एक ही पार्टी के सदस्य हैं, इन कमेटियों के पुनर्निम.ण पर विचार करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जिस मियाद तक के लिये बन चुकी है उस मियाद तक कानूनन नहीं खत्म कर सकते ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---प्रश्नकर्ता के अ रोप को ध्यान में रखते हुए और इसे सूचना मानते हुए क्या माननीय मंत्री इस बात का ध्यान रखेंगे कि इस प्रकार की नियुक्तियां न की जायं जिनमें एक ही पार्टी के लोग हों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---मुझे यह आरोप स्वीकृत नहीं है, मेरे पास नाम नहीं हैं फिर कैसे मान लूं कि एक ही पार्टी के हैं ।

श्री प्रतापसिंह---क्या सरकार के विचाराधीन ऐसी व्यवस्था है कि भविष्य में आनरेरी मैजिस्ट्रेट का पद समाप्त कर दिया जाय ? यदि हां, तो क्या इस कमेटी को भी समाप्त करने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---जब ऐसा तय होगा तो इसे भी समाप्त करना होगा ।

वाराणसी तहसील में उर्दू पढ़ाने की व्यवस्था

*८१---श्री ऊदल---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी तहसील में सिंधौरा, बरही नेवादा में अपर प्राइमरी तथा पिंडरा में लोअर प्राइमरी इस्लामियां (उर्दू) स्कूल किस सन् से बन्द कर दिये गये हैं और उसका कारण क्या है ?

श्री रामस्वरूप यादव---१ जून, १९५४ से बन्द कर दिये गये । मितव्ययता के दृष्टि-कोण से उपरोक्त स्कूल स्थानीय प्राइमरी स्कूलों में विलय किये गये ।

श्री ऊदल---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन स्थानों पर बहुत दिनों से उर्दू के स्कूल चल रहे थे क्योंकि मुसलमानों की बहुत ज्यादा आबादी है ? इसको खयाल में रखते हुए क्या मंत्री जी वहां पर फिर उर्दू का स्कूल चलवाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव---अंतरिम जिला परिषद् ने ऐसा निर्णय किया था । उर्दू को पढ़ने के लिये उर्दू जानने वाले अध्यापकों की व्यवस्था उन्होंने कर दी है । लेकिन अगर माननीय सदस्य को कोई शिकायत है तो वह स्वयं अंतरिम जिला परिषद् के सदस्य हैं उसमें इस प्रश्न को रख सकते हैं ।

श्री ऊदल---क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार की ऐसी नीति है कि जो क्षेत्रीय भाषा जहां हो उस भाषा को पढ़ने वाले लोग हों तो वहां उसको विशेष सुविधा देगी, इस नीति को ध्यान में रखते हुए सरकार कोई विशेष सुविधा वहां के निवासियों को देने की कृपा करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव---कोई विशेष बात अगर माननीय सदस्य लिख कर देंगे तो उसके बारे में जो उचित होगा वह किया जायगा ।

*८२---श्री नत्थूसिंह---[२० मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

*८३-८४---श्री रामसिंह चौहान (जिला आगरा)---[२० मार्च, १९५९ के लिए स्थगित किय गये ।]

गोंडा जिले में भूमिहीन हरिजनों के प्रार्थना-पत्र

*८५—श्री दीनदयालु 'करुण' (जिला गोंडा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५७–५८ में गोंडा जिले के कितने भूमिहीन पिछड़े वर्ग तथा हरिजनों ने कृषि हेतु भूमि के लिये जिला हरिजन अधिकारी को प्रार्थना-पत्र दिये हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—१५७ ।

*८६—श्री दीनदयालु 'करुण'—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कितने खेतिहर भूमिहीन मजदूरों को १९५७–५८ में गोंडा जिले की तहसील बलरामपुर, उतरौला, गोंडा तथा तरबगज में कृषि हेतु हरिजन सहायक अधिकारी द्वारा भूमि दी गई है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जिला हरिजन कल्याण अधिकारी द्वारा भूमि किसी को नहीं दी गई ।

श्री दीनदयालु 'करुण'—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो १५७ प्रार्थना-पत्र दिये गये हैं उन पर कोई कार्यवाही भी हुई है ? यदि हुई है, तो क्या ?

श्री रामस्वरूप यादव—जिला हरिजन कल्याण अधिकारी ने एक अपने उसी जिले की योजना बनायी थी । वह यह प्रयत्न कर रहे थे कि भूमिहीनों को जमीन दिलायी जाय, उसमें वह सहयोग दें । इस सम्बन्ध में उन्होंने आवेदन-पत्र मांगे थे । वे गांव सभाओं में जाकर यह प्रयत्न करते हैं कि भूमिहीनों को जमीन मिल जाय । सरकार की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं हो सकती क्योंकि यह अधिकार ग्रामसभाओं को है ।

कानपुर में कलेक्टरगंज थाने के निकट कल्लू की हत्या

*८७—श्री लक्ष्मणराव कदम (अनुपस्थित)—क्या सरकार को पता है कि कलेक्टरगंज पुलिस थाना, कानपुर के पास ही श्री कल्लू नामक एक सार्वजनिक कार्यकर्ता का अगस्त, १९५७ में दिन दहाड़े कत्ल हो गया था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां । थाने से ३ फर्लांग की दूरी पर दिन के साढ़े बारह बजे श्री कल्लू की हत्या हुई थी ।

*८८—श्री लक्ष्मणराव कदम (अनुपस्थित)—क्या उक्त मामले में सरकार का ध्यान फैसले के उस अंश पर गया है जिसमें कहा गया है कि दोषी को दंड न मिल सकने का दायित्व prosecution पर है ? यदि हां, तो इस पर उसने क्या कार्यवाही की है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उच्च न्यायालय (High Court) ने अपने निर्णय में यह लिखा है कि मुकदमे के छूटने का उत्तरदायित्व prosecution पर है। आगे कार्यवाही करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

*८९—श्री उल्फतसिंह (जिला बदायूं)—[२० मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

इटावा जिले में अदम पैरवी के कारण मुकदमों को खारिज करना

*९०—श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला इटावा की कलेक्टरी कचेहरी में एस० डी० एम० तथा जुडीशियल मैजिस्ट्रेट और स्पेशल मैजिस्ट्रेट की अदालतों में जनवरी सन् १९५८ से अब तक कितने मुकदमें अदम पैरवी में खारिज किय गय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वांछित सूचना निम्नलिखित हैं :—

सिटी मैजिस्ट्रेट	..	२
एस० डी० एम०, इटावा	..	११
,, ,, ,, भर्थना	..	३
,, ,, ,, विधूना	..	१३
,, ,, ,, औरैया	..	०
जे० ओ० इटावा	..	१
,, ,, भर्थना	..	४७
,, ,, विधूना	..	०
,, ,, औरैया	..	१७
स्पेशल मैजिस्ट्रेट	..	४२
योग	..	१३६

मिडवाइफरी की ट्रेनिंग

*६१—श्री हरिदत्त कांडपाल (जिला अल्मोड़ा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मिडवाइफरी ट्रेनिंग के कितने सेन्टर पूरे प्रदेश में हैं, इनमें कुल कितनी छात्रायें प्रत्येक सेन्टर में शिक्षा पा रही हैं, तथा प्रत्येक सेन्टर पर क्या खर्च पड़ रहा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इस समय प्रदेश में मिडवाइफरी ट्रेनिंग का कोई सेन्टर नहीं है । जो दस मिडवाइफरी ट्रेनिंग सेन्टर जनवरी, १६५६ से पहले प्रदेश में थे वे अब आगजलरी नर्स मिडवाइफ ट्रेनिंग सेन्टर के रूप में जनवरी, १६५६ से बदल दिये गये हैं जिनमें से निम्नलिखित स्थानों पर ६ सेन्टर चालू हैं तथा शेष चार के खोलने के स्थान अभी निश्चित नहीं हुये हैं । चालू सेन्टरों में छात्राओं की संख्या तथा उनका व्यय भी दिया जा रहा है :

सेन्टर	छात्राओं की संख्या जो इस समय शिक्षा पा रही हैं	—व्यय (जनवरी, १६५६)
		रु०
कानपुर ..	.. ७	२११७.६२
रामपुर ..	.. ५	कुछ नहीं
देहरादून ..	.. ८	१४८०.८४
बरेली ..	.. १०	५३.००
सहारनपुर ..	.. ६	११४०.६८
लखनऊ ..	.. १३	४३६.३८

यू० पी० होम्योपैथिक ऐक्ट में संशोधन की मांग

*६२—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या यू० पी० होम्योपैथिक सोसाइटी रजिस्टर्ड की तरफ से सरकार से यू० पी० होम्योपैथिक ऐक्ट में संशोधन करने की मांग की गई है ? अगर हां, तो क्या सरकार उस ऐक्ट में कुछ संशोधन करने जा रही है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—(१) जी हां।

(२) जी नहीं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार बतायेगी कि ऐक्ट में संशोधन की मांग को स्वीकार करने में सरकार को क्या आपत्तियां हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उससे क्वेकरी बढ़ेगी ।

आयुर्वेदिक कालेज, झांसी की हड़ताल

*९३—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आयुर्वेदिक कालेज, झांसी में छात्रों की हड़ताल चल रही है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—इस समय कोई हड़ताल नहीं चल रही है।

*९४—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—यदि हां, तो क्या सरकार छात्रों की प्रमुख मांगों को सदन में बताने की कृपा करेगी कि जिनके कारण यह हड़ताल चल रही है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—प्रश्न ही नहीं उठता ।

*९५—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उपरोक्त मांगों पर सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार बतायेगी कि जब इस प्रश्न की सूचना दी गई थी उस समय हड़ताल हो रही थी और जो हड़ताल उस समय हो रही थी वह कब समाप्त हुई और उसका कारण क्या था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—आज हम जवाब दे रहे हैं तब कोई हड़ताल नहीं है। लड़कों की कुछ मांगें थीं वे आपस में मैनेजमेंट में और उनके नुमाइन्दों के दरमियान में तय हो गईं। लिहाजा सब किस्सा तय हो गया है और सब काम ठीक चल रहा है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि इस प्रश्न की सूचना ९ दिसम्बर, १९५८ को दी गई थी और तब हड़ताल हो रही थी और इतने दिनों के बाद इसका जवाब दिय गया ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—माननीय प्रश्नकर्त्ता महोदय जो कहते हैं वह ठीक है। लेकिन जिस समय हम जवाब देते हैं तब कैसे कहा जाय कि हड़ताल चल रही है। इस वक्त कोई हड़ताल नहीं चल रही है।

हमीरपुर जिले में राजनीतिक पीड़ितों को पेंशन

*९६—श्रीमती राजेन्द्र कुमारी (जिला हमीरपुर)—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला हमीरपुर में राजनैतिक पीड़ित पेंशन के लिये कुल कितने प्रार्थना-पत्र सरकार को मिले और कितने लोगों को पेंशनें मिलीं ?

श्री रामस्वरूप यादव—४१५ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये, जिनमें से ७५ व्यक्तियों को आजीवन पेंशन तथा ६ व्यक्तियों को अस्थायी पेंशन स्वीकृत की गई।

श्रीमती राजेन्द्रकुमारी—क्या यह सही है कि जो राजनैतिक पीड़ितों के प्रार्थना-पत्र थे उनमें से कुछ खो भी गये हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—खोने की तो कोई सूचना नहीं है। अस्वीकार जरूर कुछ किये गये हैं।

श्रीमती राजेन्द्रकुमारी—मैंने आफिस से जानकारी की। उससे मालूम हुआ कि कुछ खो गये। क्या सरकार पता लगायेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—अगर कोई ऐसा आवेदन-पत्र दिया जाय कुछ व्यक्तियों के द्वारा कि प्रार्थना-पत्र खो गये हैं तो जानकारी कर ली जायेगी।

अतारांकित प्रश्न

जालौन जिले के परिगणित छात्रावासों, वाचनालयों व पुस्तकालयों को सहायता

१—**श्री गरीबदास**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला जालौन के परिगणित जातीय छात्रावासों को कितनी-कितनी सहायता सरकार द्वारा मिलती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जिला जालौन में चल रहे परिगणित जातीय छात्रावासों को गत वर्ष निम्नलिखित आवर्ती तथा अनावर्ती सहायता स्वीकृत की गई थी—

छात्रावास का नाम	स्वीकृत धनराशि (आवर्ती)
	रु०
१—हरिजन छात्रावास, कौंच	३९६
२—ठक्कर बापा हरिजन छात्रावास, राम चबूतरा, कालपी ..	४८०

इसके अतिरिक्त गत वर्ष ५०० रु० की दर से दोनों छात्रावासों को अनावर्ती अनुदान भी स्वीकृत किया गया था।

२—**श्री गरीबदास**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला जालौन के कहां-कहां कितने वाचनालय एवं पुस्तकालय परिगणित जातियों के चल रहे हैं और उनको कितनी-कितनी सहायता सरकार द्वारा प्राप्त होती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ६५६ पर)

पुलिस अधीक्षक, जिला जालौन के कार्यालय में परिगणित तथा पिछड़ी जातियों के कर्मचारी

३—**श्री गरीबदास**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला जालौन में सुपरिंटेंडेंट पुलिस के कार्यालय में कितने-कितने कर्मचारी किन-किन पदों पर कार्य कर रहे हैं और उनमें परिगणित जाति के तथा पिछड़ी जाति के किन-किन पदों पर कितने-कितने कर्मचारी हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—पुलिस अधीक्षक, जिला जालौन के कार्यालय में विभिन्न पदों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या संलग्न सूची में दी हुई है। इनमें से एक दफ्तरी परिगणित जाति का तथा एक सहायक आंकिक, एक कान्स्टेबुल मुहर्रिर और एक कहार पिछड़ी जाति के हैं।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ६५७ पर)

लखनऊ में साइकिलों की चोरी

४---श्री गनेशीलाल चौधरी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ शहर में सन् १९५८ में कितनी साइकिलों की चोरियां हुईं जिनकी रिपोर्ट की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---सन् १९५८ में कुल ४६५ साइकिलों के चोरी की सूचना लखनऊ शहर के थानों में दर्ज की गई।

५---श्री गनेशीलाल चौधरी---कितनी चोरियों का स्थानीय पुलिस द्वारा पता लगा लिया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---स्थानीय पुलिस ने ४५ साइकिलों को पता लगाकर बरामद किया।

६-७---श्री नत्थूसिंह (जिला बरेली)---[२० मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

गधेरा तथा हड़ेरा कुम्हारों की सामाजिक स्थिति

८---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में बसने वाले गधेरा कुम्हारों की सामाजिक स्थिति की जांच करा के उन्हें परिगणित जाति में शामिल कराने का इरादा रखती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी नहीं।

९---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार बांदा, हमीरपुर जिले के जो हड़ेरे, कुम्हार किसी समय से सुअर पालते थे उनकी सामाजिक स्थिति की जांच करा के उन्हें परिगणित जाति में शामिल कराने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी नहीं।

१०---श्री रामदीन---[चौऋहवें शुक्रवार, २० मार्च, १९५९, के लिये स्थगित किया गया।]

राजनीतिक पीड़ितों के आश्रितों को पेन्शन

११---श्री बलवान सिंह (जिला कानपुर)---क्या सरकार कृपया बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में जिलेवार ऐसे राजनीतिक पीड़ितों की संख्या क्या है जिनको सरकार राजनैतिक पीड़ित होने के कारण उनके आश्रितों तथा उनको आर्थिक सहायता देती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---प्रश्न के उत्तर के संबंध में सूचना संकलन करने में जो समय व श्रम लगेगा वह प्रश्न की उपयोगिता को देखते हुये उचित न होगा। यदि माननीय सदस्य किसी व्यक्ति विशेष के लिये जानना चाहते हों तो मेरे कार्यालय से सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

गढ़वाल जिले में हरिजन कल्याण पर व्यय

१२---श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी (जिला गढ़वाल)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसने विगत दो वर्षों के अन्दर गढ़वाल जिले में हरिजन कल्याण कार्य पर कुल कितना रुपया खर्च किया और किन-किन कामों में ?

श्री कमला पति त्रिपाठी—विगत दो वर्षों के अन्दर गढ़वाल जिले में हरिजन कल्याण कार्य पर कुल २,०१,५४३ रु० खर्च हुआ जिसका विवरण निम्न प्रकार है:—

नाम योजना	खर्च का विवरण	
	१९५६–५७	१९५७–५८
	रु०	रु०
पेय जल योजनायें ..	१३,३२५	३,३५७
मकान निर्माण तथा सुधार ..	१,०३५	४,९९५
कुटीर उद्योग	३,९५०	३,०००
कृषि सुधार	६,२५०	३,२५०
सम्मेलन आदि	१३४	१२०
शिक्षा	७२,८९४	८९,२३३
योग ..	९७,५८८	१,०३,९५५

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५८–५९ का द्वितीय पूरक) विधेयक, १९५९

सचिव, विधान सभा—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५८–५९ का द्वितीय पूरक) विधेयक, १९५९, पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १६ फरवरी, १९५९, की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १८ फरवरी, १९५९, की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति २८ फरवरी, १९५९ को प्राप्त हो गयी और वह १९५९ का उत्तर प्रदेश का चौथा अधिनियम बन गया।

बाराबंकी जिलान्तर्गत महादेवा के मेले में लाठीचार्ज के विषय पर नियम ५२ के अन्तर्गत स्वायत्त शासन उपमंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—नियम ५२ के अन्तर्गत एक सूचना मेरे पास आई है श्री कल्याण चन्द मोहिले की। वह चाहते हैं कि संबंधित मंत्री इसके ऊपर कोई वक्तव्य दे दें। वह यह है:—

मैं निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय नियम ५२ के अन्तर्गत माननीय सदन में उपस्थित करना चाहता हूं। श्रीमान् मुझे उपस्थित करने की आज्ञा प्रदान करेंगे:

"कल ता० ५–३–५९ को जिला बाराबंकी से लगभग २५ मील दूरी पर लोढ़ेश्वर मंदिर पर जब कि वहां पर लाखों की संख्या में ७ मार्च शिवरात्रि के अवसर पर लोग पूजा करने के लिये एकत्रित हुए, पुलिस और आये हुये यात्रियों में झगड़ा हो गया जिसके फलस्वरूप पुलिस ने लाठी चलाई तथा बहुत-सी दुकानें लूटी गईं। वहां पर बहुत संख्या में लोग जख्मी हैं तथा बहुत साधन (शायद सामान से मतलब है) लूटा गया है। इससे लोगों में आस-पास के आने वाले यात्रियों में बेचैनी है। इसकी जानकारी के लिये गृह मंत्री माननीय सदन को सूचित करेंगे कि उस स्थान की क्या सूचना है।"

(श्री रामस्वरूप यादव से) मैं समझता हूं इसके ऊपर सूचना देना आवश्यक प्रतीत होता है।

स्वायत्त शासन उपमन्त्री (श्री रामस्वरूप यादव)—श्रीमन्, सूचना जो मिली है उससे मालूम होता है कि यह बात कुछ सही नहीं है कि पुलिस और यात्रियों में झगड़ा हुआ या पुलिस ने लाठी-चार्ज किया या पुलिस ने दूकानें लूटीं।

श्री अध्यक्ष—पुलिस द्वारा दुकानें लूटने का चार्ज नहीं है। इसमें सूचना है कि दुकानें लूटी गई हैं।

श्री रामस्वरूप यादव—दुकानों के बारे में अभी निवेदन करूंगा। श्रीमन्, यह महादेव जी का जो मंदिर है वह बाराबंकी से २२ मील दूर है। वहां पर शिवरात्रि के लिये यात्री गये हुये थे। तहसीलदार फतेहपुर वहां पर नियुक्त थे। वे इंतजाम मेले का देख रहे थे। ५ मार्च, १९५९ को १२।। बजे करीब तहसीलदार को इत्तला मिली कि यात्रियों में और दुकानदारों में झगड़ा हो गया है और यात्री दुकानदारों के सामान को फेंक रहे हैं। बताया यह जाता है कि झगड़ा इस पर शुरू हुआ कि एक यात्री जालौन जिले का लाई खरीद रहा था। दुकानदार ने दो छटांक कम लाई दी जिससे झगड़ा हो गया। जब झगड़े की खबर मिली तो तहसीलदार और पुलिस वहां तुरन्त पहुंच गये और वहां की स्थिति में कोशिश की कि झगड़ा न बढ़े। एक हेड कांस्टेबिल के चोट आई और दो कांस्टेबिलों के नियंत्रण करने में चोट आई। १४४ धारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने लागू कर दी। कुछ यात्रियों ने जो बांस होते हैं दुकानों के, वह भी निकाल लिये। ७ आदमियों की गिरफ्तारी हुई। जिन दुकानदारों का सामान यात्रियों ने लूटा था उन्होंने अपनी रिपोर्ट लिखा दी। उसकी जांच हो रही है। अब स्थिति ठीक है। वहां शांति है। एस० पी० भी मेले में पहुंच गये हैं और इंतजाम ठीक हो गया है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उस स्थान पर पुलिस ने बुरी तरह से दुकानों को लूटा है और बहुत से लोग वहां घायल हुये हैं?

श्री रामस्वरूप यादव—पुलिस ने तो कोई ऐसी कार्यवाही नहीं की है, लेकिन यात्रियों और दूकानदारों में झगड़ा हुआ है, जैसा कि मैंने निवेदन किया।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो रिपोर्ट उन्होंने पढ़कर सुनाई है वह किस अधिकारी की जांच पर आधारित है?

श्री रामस्वरूप यादव—अभी तो केवल जिलाधीश से टेलीफोन पर बातचीत हुई है, कोई लिखित रिपोर्ट नहीं आई है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि कल शिवरात्रि है और वहां काफी यात्री इकट्ठा होंगे, इसलिये क्या वहां कोई विशेष प्रबन्ध शांति व्यवस्था के लिये किया गया है या नहीं?

श्री रामस्वरूप यादव—वहां के जिला अधिकारी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई अशांति न हो और यात्रियों को किसी तरह की असुविधा न हो इसकी पूरी कोशिश की जायगी।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—माननीय मंत्री जी के पास पुलिस के चोट लगने की रिपोर्ट आई है, लेकिन क्या यात्रियो के चोट लगने की भी कोई सूचना मिली है?

श्री रामस्वरूप यादव—यह भी संभव हो सकता है कि उनके भी कोई मामूली चोट पकड़धकड़ में आ गई हो, लेकिन किसी खास चोट की इत्तला हमें नहीं मिली है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---यह जो दफा १४४ लागू की गई है वह लाठी, भाले या हथियार रखने पर ही लगाई गई है या आदमियों के इकट्ठे होने के लिये भी मनाही कर दी गई है ?

श्री रामस्वरूप यादव---इसकी पूरी तफसील तो हमारे पास नहीं है, केवल इतना ही मालूम है कि दफा १४४ लगा दी गई है।

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---कल इस सदन के भी कुछ माननीय सदस्य मेले में जाने वाले हैं तो क्या उनकी सुरक्षा के लिये माननीय मंत्री जी कोई प्रबन्ध करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---यह इस वक्तव्य का स्पष्टीकरण नहीं है बल्कि एक स्वतंत्र प्रश्न है, इसलिये आप मंत्री जी से उनके कमरे में पूछ लें।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस मेले में प्रतिवर्ष प्रायः कितनी जनता एकत्रित होती है और जिले के केंद्र से उसके प्रबन्ध के लिये कितनी पुलिस हर साल भेजी जाती है ?

श्री रामस्वरूप यादव---कितने यात्री वहां इकट्ठा होते हैं यह बताना तो कठित है, लेकिन जितना प्रायः हर साल प्रबन्ध किया जाता है वह तो किया ही जायगा और इसके अलावा कल के झगड़े की वजह से विशेष ध्यान रखा जायगा कि कोई अशांति वहां न होने पाये।

श्री गेंदासिंह---क्या सरकार वहां के अधिकारियों को इस तरह की हिदायत देगी कि दफा १४४ में वहां पूरी मुश्तहरी करा दी जाय जिससे कि यात्रियों को वहां इकट्ठा होने में कोई दिक्कत न हो ?

श्री रामस्वरूप यादव---सरकार के लिये तो कोई ऐसे आदेश भेजना मुनासिब न होगा, लेकिन जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी है उनसे आशा की जाती है कि वे उसे ठीक तरह से निभायें और जो मुनासिब समझें मौके पर करें।

(बहुत से सदस्यों के प्रश्न पूछने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष---अब इसको समाप्त करना चाहिये क्योंकि तात्कालिक प्रश्न ही पूछे जा सकते हैं और जो वक्तव्य अभी दिया गया है वह केवल टेलीफोन की बात पर ही आधारित है, इसलिये अभी अधिक स्पष्टीकरण मंत्री जी नहीं कर सकेंगे।

श्री भजनलाल (जिला इटावा)---वहां पर ३-४ आदमियों की मौत हो चुकी है, मैं जानना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष---ऐसा जिक्र कहीं पर भी नहीं था।

श्री भजनलाल---मेरे पास वहां से आदमी आये हैं और मुझसे हाल बताया है।

श्री अध्यक्ष---वह स्पष्टीकरण में कहीं नहीं है, मौत हो जाना नई बात आप कह रहे हैं।

रामपुर की चीनी मिलों की हड़ताल के विषय में जानकारी

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप का बहुत अनुगृहीत हूं इस आज्ञा के लिये और आप की इजाजत से मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से दरयाफ्त करना चाहता हूं कि रामपुर स्थित दोनों चीनी मिलों में एक मास से अधिक से जो हड़ताल चल रही है और मालिकान व मजदूरों के बीच में झगड़ा जारी है सरकार उसको निबटाने के लिये कोई ऐसा उपाय सोच रही है कि हड़ताल समाप्त हो जाय, मजदूरों का विक्टेमाइजेशन न हो

यानी वे हड़ताल के कारण न निकाले जायं और उनका झगड़ा एडजुडीकेशन के सुपुर्द कर दिया जाय ?

*मुख्य मन्त्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, मैं इस सिलसिले में जो हमारी नीति है उसको कई बार इस सदन में स्पष्ट करने की कोशिश कर चुका हूं। उसी बात को फिर दोहरा सकता हूं। मैंने पहले भी कहा है कि इस वक्त दो-एक गैर-कानूनी हड़तालें चल रही हैं, ऐसी स्थिति में ऐडजुडिकेशन हो इस सवाल पर विचार नहीं हो सकता। लेकिन मैंने कहा था कि जब नार्मल कानूनी परिस्थिति फिर से कायम हो जायगी उस समय हम जरूर इस सवाल पर सहानुभूति के साथ विचार करेंगे।

जहां तक विक्टिमाइजेशन का सवाल है, यह तो आज के पहले आया नहीं था, लेकिन हमेशा हमारी इस बात की कोशिश रहती है कि कहीं भी हो विक्टिमाइजेशन न किया जाय। कानून के अन्दर जो बातें आती रहेंगी, मिल मालिक यह काम करने वालों के जो अधिकार हैं उनको तो हम छू नहीं सकते, लेकिन जब हम इस बात को सुलझाने का यत्न करते हैं तो उसके अन्दर यह चीज जरूर रहती है। यह हम जानते हैं कि विक्टिमाइजेशन से स्थिति बिगड़ती है इसलिये वह न किया जाय। यहां भी यदि किसी वक्त नार्मल कानूनी परिस्थिति फिर से कायम हुई तो यहां भी वही कोशिश होगी।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी इसकी व्यवस्था करेंगे कि मिल-मालिक जो बाहर से दो-ढाई सौ लेबरर ले आये हैं और उनके कारण जो अशान्ति फैली है उस अशान्ति को फैलाने से मिल-मालिक को रोकेंगे ?

श्री अध्यक्ष---यह तो बिलकुल नया सुझाव आप दे रहे हैं। इसे लिखकर भेज दीजियेगा। मैं इस पर वक्तव्य के लिये नहीं कहूंगा।

गृह मंत्री द्वारा इस्तीफे के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---आपकी आज्ञा से एक निवेदन करना चाहता हूं। वाराणसी के एक समाचार-पत्र में यह छपा है कि माननीय गृह मंत्री ने अपना इस्तीफा मुख्य मंत्री के पास भेज दिया है, इस सम्बन्ध में सारे देश में बड़ी उत्सुकता है लोगों को, तो मंत्री जी इसका स्पष्टीकरण करें।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं, आप मुझे लिखकर भेज दें तो यह भी अविलम्बनीय प्रश्न हो जाय। आप यह सुझाव शायद राजनारायण जी का दे रहे होंगे।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५९

वित्त मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)---अध्यक्ष महोदय, आज जैसा कि एजेंडा आया है, इसमें ५ बजे से यू० पी० सेल्स टैक्स (अमेंडमेंट) बिल, १९५९ के ऊपर विचार करने की बात रखी हुई है, तो मैं यह अर्ज करूंगा कि चूंकि कल छुट्टी है सभी माननीय सदस्य उत्सुक हैं कि वे अपने घरों को चले जायं, तो यह आज न लिया जाय ५ बजे से।

श्री अध्यक्ष---श्री गोविन्द सिंह बिष्ट ने भी कहा था कि आज न लिया जाय, लेकिन उस समय आपकी तरफ से ही यह सुझाव आया था कि आज ही रख दीजिये। तो अब तारीख ९ को रखें या १० को ?

श्री सैयद अली जहीर---१० को रख दीजिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष---तो तारीख १० को यह विधेयक लिया जायगा, आज नहीं लिया जायगा ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---मैं यह जानना चाहता हूं कि ५ बजे के बाद जो इसको लेने के लिये आपने स्वीकृति दी है यह किस नियम के अन्तर्गत है ? क्या कोई प्रस्ताव पास हो चुका है ?

श्री अध्यक्ष---यह पहले सदन में तय हो चुका था कि यह विधेयक ५ बजे के बाद रोजाना लिया जायगा ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---यह तो प्रवर समिति में जाने के पहले तय हुआ था ? आने के बाद की बात नहीं थी ?

श्री अध्यक्ष---यह निश्चय था कि जब तक विधेयक पारित न हो जाय रोजाना बैठा जायगा ५ बजे के बाद ।

१९५९-६० के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या ३५---लेखा शीर्षक ५०---नागरिक निर्माण-कार्य और ८१---राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों की पूंजी का लेखा तथा अनुदान संख्या ४९---लेखा शीर्षक ८१---राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों पर लागत

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारी लाल)---अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३५---सार्वजनिक निर्माण-कार्य स्थापना पर व्यय---लेखा शीर्षक ५०---नागरिक निर्माण-कार्य और ८१---राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण---कार्यों की पूंजी का लेखा के अन्तर्गत ८१,१२,२०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय ।

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह भी प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४९---राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों पर लागत---लेखा शीर्षक ८१---राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण---कार्यों का पूंजी लेखा के अन्तर्गत ९,७३,७२,५०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिए स्वीकार की जाय ।

अध्यक्ष महोदय, इन दोनों मांगों के सिलसिले में मुझे आज कोई विशेष बात नहीं कहनी है । जहां तक ग्रांट नम्बर ३५ का सम्बन्ध है, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि १९५९-६० का हमारा पूरा खर्च १४,३२,८८,००० रुपये है और इसमें जो इस्टैब्लिशमेंट पर खर्च होगा वह ८१,१४,१०० रुपये है जो पूरे खर्च का ५.६ प्रतिशत पड़ता है और बहुत ही कम है । मुझे उम्मीद है कि सदन इसे बहुत खुशी से स्वीकार करेगा ।

जहां तक ग्रांट नम्बर ४९ का ताल्लुक है, इसके विषय में बहुत कुछ कल कहा जा चुका है । इसमें दो खास मदें हैं, एक तो भवन निर्माण है जिसमें ४,०३,२९,००० रुपये तो उन कामों के लिये है जो काम चल रहे हैं और अभी अधूरे हैं । साथ ही कुछ नये काम भी हैं जिनके लिये ५२,११,००० रुपया रखा गया है । इसके अलावा यातायात के लिये २,९९,१६,००० रुपया चालू कामों के लिये रखा गया है और १५,३५,००० रुपया नये कामों के लिये रखा गया है । इसके अलावा टूल्स ऐंड प्लांट के लिये ८,३०,००० रुपया और सस्पेन्स स्टाक में १,९०,१५,७०० रुपया है ।

ये हमारे पूरे प्रान्त के निर्माण की मांगें हैं और इनको सदन सहर्ष स्वीकार करेगा । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं ।

श्री इन्दुभूषण गुप्त (जिला आजमगढ़)––माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके आदेश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३५––लेखा शीर्षक ५०––नागरिक निर्माण-कार्य और ८१––राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों की पूंजी के लेखा के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-नीति का व्योरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्य की स्थापना पर अनियन्त्रित व्यय किया जाना।

अनुदान संख्या ४९––लेखा शीर्षक ८१––राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों का पूंजी लेखा के विषय में मेरा प्रस्ताव है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य–नीति का व्योरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है––अनुदान से सम्बन्धित योजना का लक्ष्य समय से पूरा नहीं किया जा रहा है।

(इस समय १२ बज कर १९ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री बेचन-राम गुप्त पीठासीन हुये।)

मैं इस सम्बध में श्रीमन् के आदेश से पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के सामने जो तथ्य आये हैं उनको प्रस्तुत करना चाहूंगा और सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि जो सब से मुख्य बात हम लोगों के सामने उस कमेटी में आयी वह यह कि बहुत-सा रुपया प्रति वर्ष लैप्स हो जाता है और वह जनता के हित में खर्च नहीं हो पाता है। जवाब में उसका उत्तर यह दिया जाता है कि पी० डब्लू० डी० दूसरे विभागों का काम करता है और उनसे प्रशसकीय स्वीकृतियां समय से नहीं मिलती हैं। अगर लैंड एक्वीजीशन करनी है तो वह नहीं हो पाती जिसके कारण बहुत-सा रुपया लैप्स हो जाता है। उसके कारण बहुत से काम रुक जाते हैं और उधर जनता के ऊपर टैक्स लगाकर रुपया उगाह लिया जाता है। इसलिये ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि रुपया लैप्स न हुआ करे। इसके लिये मैं सुझाव देना चाहूंगा कि विभागों में नान-लैप्सेबिल फंड क्रियेट किया जाय कि जो रुपया मार्च में सैंक्शन होता है और आशा की जाती है कि वह ३१ मार्च से पहले यूटिलाइज हो जाय। वह रुपया यूटिलाइज नहीं हो पाता है और उसका दुरुपयोग न हो सके इसलिये ऐसा रुपया इस फंड में जमा हो जाया करे और दूसरे वर्ष उसका उपयोग कर लिया जाया करे। इससे बहुत-सा समय पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी का बच सकता है और रुपया भी लैप्स नहीं होगा और रुपये का दुरुपयोग भी नहीं होगा। बहुत से कार्य नहीं हो पाते हैं वह भी हो जाया करेंगे अगर सरकार उचित समझे तो इसके लिये एक नियम सदन के समक्ष प्रस्तुत करे।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी आपके द्वारा सरकार के सामने रखना चाहता हूं कि हम प्राय: देखा करते हैं कि जो एस्टीमेट बनाये जाते हैं उनको बड़े-बड़े टेक्नीकल एक्सपर्ट्स बनाते हैं और बहुत सोच-विचार के बाद सरकार को दिये जाते हैं। लेकिन जब काम होने लगता है तो एस्टी-मेट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और उनका कुछ हिसाब नहीं मालूम पड़ता है कि कितना रुपया खर्च होगा। इसके माने यह हैं कि एस्टीमेट्स इन्कम्पलीट होते हैं और विश्वास करने के योग्य नहीं होते हैं। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि सरकार इसके लिये एक एक्सपर्टस् की कमेटी बनाये और वह देखे कि किस तरह से एस्टीमेट्स बनने चाहिये। पहले भी कार्य होते थे और उनमें ऐसी बात नहीं होती थी कि घटती या बढ़ती हो। एस्टीमेट बनाने का मतलब ही यह है कि जो खर्च हो उसमें थोड़ा-बहुत ही अंतर पड़ना चाहिये। इसलिये जो एस्टीमेट्स बनाकर दिये जायं वह बहुत सोच-समझकर दिये जायं।

[श्री इन्दुभूषण गुप्त]

इसी सिलसिले में मैं यह भी सरकार के सामने रखना चाहता हूं कि एस्टीमेट्स देने के बाद जब टेंडर्स काल किये जाते हैं तो ठेकेदार एस्टीमेट से ४ या ५ प्रतिशत कम पर टेंडर देते हैं। टेंडरों के खुलने पर लोएस्ट एक्सेप्ट किया जाता है। यह मेरी समझ में नहीं आता है कि जब एस्टीमेट्स बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स बनाते हैं तो वह प्रिवेलिंग मजदूरी और सामानों के मार्केट वेल्यू को ध्यान में रखकर ही बनाते हैं तो ठेकेदार कैसे कम रेट पर टेंडर्स देते हैं। इसका क्या राज है, इस पर विचार होना चाहिये ? मेरा खयाल यह है कि या तो एस्टीमेट में गुंजायश रहती है कि उसमें कमीबेशी रखी जाय या जो मजदूरी इसके एस्टीमेट्स में लगाते हैं यानी अगर डेढ़ रुपये लगाते हैं तो मजदूरी ठेकेदार सवा रुपया या बारह आना देता है तो यह दोनों तरीके गलत हैं और जनता की हानि हो रही है। इसलिये इस पर गौर से विचार करें और जो पहले तरीका था वही रखा जाय कि एस्टीमेट खूब सोच-समझकर बनाये जायं। एस्टीमेट बनाने के बाद यह तरीका था कि जो एस्टीमेट होता था उसके १० फीसदी या १५ फीसदी मुनाफे पर ठेकेदार को काम दिया जाता था। उसमें काम की पायेदारी होती थी, चोरी और बेईमानी नहीं होती थी। आज अगर ठेकेदार ठेका लेता है और इंजीनियर साहब को खुश नहीं करता तो बिल पास नहीं होता। यह जो भ्रष्टाचार है वह शायद एस्टीमेट की गड़बड़ी से है। इसलिये मैं सरकार के सामने आपके द्वारा यह सुझाव रखूंगा कि वह एस्टीमेट ठीक से बनवाने के लिये एक कमेटी टेक्निकल लोगों की बनाये। उनके द्वारा सब एस्टीमेट्स स्वीकृत हों।

एक चीज हम और देखते हैं कि जो पुराने मकान बने हुए हैं तीन तीन सौ वर्ष पुराने हो गये हैं और वह खड़े हुए हैं अपनी जगह पर उनमें मरम्मत की जरूरत नहीं होती। आज दशा यह है कि आज लाखों रुपया खर्च करके कोई बिल्डिंग बनी और दूसरे ही साल जितना रुपया लगा उसका आधा या चौथाई रुपया, मरम्मत के नाम पर खर्च कर दिया जाता है और चूने लगता है। माननीय राजवेन्द्रप्रताप सिंह जी के प्रश्न के जवाब में गोंडा की एक बिल्डिंग के बारे में जवाब मिला था कि इधर वह बनी और उधर चूने लगी। यह बात दूसरी है कि वह इर्रीगेशन डिपार्टमेंट से बनी हो या पी० डब्लू० डी० से बनी हो। सभी विभागों के भवनों का निर्माण कार्य यदि एक विभाग के द्वारा हो तो इसमें पैसे की बहुत बचत होगी।

एक बात यह भी देखने को मिलती है कि जो बहुत जरूरी काम हैं उन पर दृष्टि नहीं डाली जाती और वह छोड़ दिये जाते हैं और जहां पर यातायात की कोई कठिनाई नहीं ह किसी तरह से काम हो रहा है उसको फिर से तोड़ कर नया बनाना शुरू कर देते हैं। हम अपने जिले का नक्शा सरकार के सामने रखना चाहते हैं। आजमगढ़ में टोंस नदी का जो पुल है उससे किसी न किसी प्रकार कार्य होता रहा है। काफी मजबूत पुल है लेकिन उसकी जगह पर लाखों रुपया खर्च करके नया पुल बनाया जा रहा है जब कि दोहरीघाट का पुल, जो ज्यादा जरूरी है उसके लिये स्वीकृति नहीं दी गई। जो किताब हम लोगों को बटी है, उसमें दोहरीघाट पुल के लिये अभी तक स्वीकृति भी नहीं है जो इतना महत्वपूर्ण है। उसका महत्व बताने में काफी समय लगेगा। उसके लिये बहुत वर्षों से मांग थी लेकिन उसको नेगलेक्ट किया जा रहा है। वहां पर व्यापार के बहुत बड़े केन्द्र हैं दोहरीघाट और बड़हलगंज। मैंने सरकार से एक प्रश्न भी किया था कि सरकार जब तक पुल नहीं बन जाता तब तक चह बनाने पर विचार करेगी, सरकार ने कहा नहीं। अब आप यह देखें कि जहां पर काम हो रहा है उसको आप तोड़कर के एक नया पुल बनायेंगे। जो पुल बनने जा रहा है उसका जो काम हो रहा है, हम लोग वहां जाकर देख चुके हैं। यह तो खैर, समय सिद्ध करेगा आपने क्या किया, जो पुल बना है वह कितने दिन टिका था और जो पुल बन रहा है वह कितने दिन टिकेगा ? उसकी चर्चा करना अभी तो समय से पहले होगा। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जो चीजें हैं उनको अगर वह सही ढंग से कायम रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। अभी हमको अपने प्रदेश का विकास करना है और अगर विकास हो जाता है तो सुविधा यह होगी कि हम अपने व्यापार को अच्छी तरह से बढ़ा सकेंगे। अपनी खेती की उपज को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाकर के अच्छा पैसा पैदा कर सकेंगे। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि जो भी काम किया जाय उस पर विचार

कर लिया जाय और खासकर उस जगह के जो जनप्रतिनिधि आते हैं उनसे भी विचार अगर विभाग कर लिया करे तो ज्यादा अच्छा होगा ।

आपके द्वारा मैं एक और जरूरी बात सरकार की जानकारी में लाना चाहता हूं । सरकार ने जो प्रादेशिक सड़कें हैं उनमें जितना हिस्सा उन सड़कों का बाजार के अन्दर पड़ता है, उनको सीमेंटेड कराने के लिये बहुत अच्छा कदम उठाया है । उसकी प्रशंसा करनी चाहिये । लेकिन बड़ी अजीब-सी बात है कि उनकी पटरियों को सरकार ने उसी तरह छोड़ दिया । उन पर खड़ंजे नहीं लगवाये और न उन पर पक्की नालियां ही बनवाईं । प्रत्येक बाजार में हर सप्ताह एक या दो बार हाट लगती है । बरसात में उनकी अवस्था इतनी खराब हो जाती है कि उसमें चलना बिलकुल नरक के बराबर हो जाता है । अगर ग्रामसभा या पंचायत या प्लानिंग डिपार्टमेंट से कहा जाय तो वह कहते हैं कि यह प्रार्विशियल रोडवेज है । इसलिये इसकी हद के अन्दर हम कुछ काम नहीं कर सकते और अगर डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर साहब से कहा जाय तो वह कहते हैं कि मेरे पास इसके लिये फंड नहीं है । आप सरकार से फंड दिलवाइए तो मैं करूं । मैंने अपने जिले की तीन बाजारों की ओर जिले के प्लानिंग आफिसर का ध्यान आकृष्ट किया । उनसे मैंने कहा कि कम से कम आप इसमें खड़ंजे लगवा दीजिये, नालियां बनवा दीजिए ताकि जो लोगों की हेल्थ पर बुरा असर पड़ रहा है, उससे बचें । मोटरों से जो छींटे पड़ते हैं उनसे बचाइए । तो उन्होंने उत्तर दिया कि साहब, मेरे पास फंड नहीं है । मैंने उनसे कहा कि आप एस्टीमेट्स बना दीजिये तो मैं सरकार के सामने रखूं । इस पर उन्होंने मनमाना हिसाब लगाकर २० हजार रुपये का एस्टीमेट बता दिया जो मेरे गले के नीचे नहीं उतरा । इसलिये मैं उसे सरकार को नहीं दे सका । मैंने उनसे कहा कि इसके डिटेल्स बताइए तो उन्होंने कहा कि आप कोई टेक्निकल आदमी तो हैं नहीं, आपको डीटेल्स देने से कोई लाभ नहीं होगा । अब श्रीमन्, आप विचार करें । हमने अपने यहां अजमतगढ़ एक गांव है वहां जो पक्की सड़क है उसके किनारे खड़ंजे लगवाये उसमें कुल तीन-चार हजार रुपये लगे । उससे दूना काम या तिगुना काम उस बाजार में होगा । उस हिसाब से ज्यादा से ज्यादा आठ-दस हजार रुपया उसमें लगना चाहिये था । लेकिन २० हजार रुपया उन्होंने रख दिया ताकि मैं सरकार से कहूं और सरकार मंजूर न करे । तो यह सब समस्यायें ऐसी हैं जिन पर विचार करना चाहिये ।

इसके बाद मैं आपका ध्यान एक दूसरी चीज की तरफ दिलाना चाहता हूं । पहले जो काम पी० डब्लू० डी० से होता था वह बड़े पायेदारी का होता था और जो जनता या ठेकेदार द्वारा काम होते थे उनसे कहीं ज्यादा अच्छा होता था । उनमें डिसेंसी होती थी और जो कार्य करने वाले होते थे उनमें एक शालीनता होती थी । वह दूसरों के साथ ज्यादा अच्छा बर्ताव करते थे, लेकिन आज हम दूसरा नक्शा देखते हैं । मैं आपके आदेश से यह चीज भी सरकार के नोटिस में ला देना चाहता हूं । अभी हमारे सामने सबसे बड़ी मुख्य घटना झूंसी की हुई है । झूंसी के पुल पर इलाहाबाद में जो दुर्घटना हुई वह केवल इस कारण हुई कि वह जो हिस्सा नदी ने काट दिया था उसमें जितना चह बनाया गया वह इतना कमजोर और खराब बनाया गया कि यह दुर्घटना हो गई । और अगर उसकी तरफ किसी माननीय सदस्य ने या किसी व्यक्ति ने सरकार के कर्मचारियों का ध्यान भी आकर्षित किया तो वह अनसुनी की गई । इसकी जितनी भी निन्दा की जाय वह थोड़ी है ।

इसी प्रकार गोरखपुर जिले की एक घटना के बारे में मैं माननीय मंत्री जी को एक पत्र भी लिख चुका हूं और शायद वह उस पर जांच-पड़ताल भी कर रहे हैं । वहां जो पुल है उस पर बरसात में चलना नरक में चलने के बराबर है । वहां पर न सीढ़ियां बनाई जाती हैं और न नाव और स्टीमर पर चढ़ने-उतरने के लिये कोई ठीक व्यवस्था की जाती है और श्रीमन् मैं

[श्री इन्दुभूषण गुप्त]

स्वयं उसमें घुटने-घुटने भर कीचड़ में घुस कर गया और जब मैंने उसकी शिकायत वहां के घाट दरोगा साहब से की तो उन्होंने जिन शब्दों में उसका उत्तर दिया उससे मुझे बहुत क्लेश हुआ और उसके बारे में मैंने शिकायत माननीय मंत्री जी को लिखकर भेजी। उन्होंने यह कहा कि आप सब एम० एल० एज० इस तरह गलत कानून बनाया करते हैं जो रोज अल्ट्रावायरस होते हैं, आपके कहने की परवाह क्या ? और वहां पर एक स्टीमर जिस गन्दे काम के लिये इस्तेमाल होता रहता है उसकी शिकायत माननीय लारी साहब ने भी विभाग को लिखकर भेजी। वह पब्लिक के लिये नहीं इस्तेमाल होता। मेरी ट्रेन छूट रही थी, मैंने कहा कि मुझको स्टीमर दे दिया जाय लेकिन नहीं मिला। वहां पर उसकी शिकायत मल्लाहों और वहां की जनता ने भी की।

श्री अधिष्ठाता--आपका समय समाप्त हो गया।

श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी (जिला गढ़वाल)--अधिष्ठाता महोदय, सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी ने जो अनुदान उपस्थित किया है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी को बधाई भी देता हूं कि उन्होंने विगत कुछ वर्षों में जब से यह विभाग उनके पास आया है उसकी जो त्रुटियां हैं, जो खराबियां हैं उनको दूर करने की कोशिश भी की है। यह सही है कि वह कोशिशें उनकी जो हैं वह उतनी सफल नहीं हो पाई हैं जितनी होनी चाहिये थी और यह भी सही है कि कुछ खराबियां अभी तक मौजूद हैं, भ्रष्टाचार भी है और जो काम होते हैं इस विभाग की ओर से उनमें त्रुटियां भी हैं, लेकिन कुछ इन विकृतियों का, इन खराबियों का कारण हमारा स्वभाव भी है। आखिर काम करने वाले भी हम हैं और काम कराने वाले भी हमी हैं। अगर हम में खराबियां न होतीं तो इस विभाग की ओर से जो कोशिशें की गई उससे वह त्रुटियां दूर हो सकती थीं। इसके अलावा इन त्रुटियों, इन खराबियों का एकमात्र कारण हमारा कंट्रैक्ट सिस्टम, ठेकेदारी प्रथा भी हो जाती है। जब तक ठेकेदारी प्रथा निर्माण-कार्यों में रहेगी तब-तक यह त्रुटियां, यह खराबियां दूर नहीं हो सकेंगी ?

मुझे खुशी है कि भारत सरकार ने सार्वजनिक निर्माण के कार्यों के लिये एक नेशनल कमीशन की स्थापना की है। मैं समझता हूं कि बड़े-बड़े इंजीनियरों के सहयोग से यह कमीशन जो काम करायेगा उन कामों में ये त्रुटियां मौजूद नहीं होंगी। मैं आपके द्वारा अधिष्ठाता महोदय, सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय का ध्यान भारत सरकार की इस तजवीज की ओर आकृष्ट करूंगा और उनसे प्रार्थना करूंगा कि इस विभाग में जो त्रुटियां हैं जिनका आदरणीय सदन में बार-बार जिक्र होता है और जिनको सुनकर शर्म भी होती है, संकोच भी होता है और दुख भी होता है, उनको दूर करने के लिये वह हमारे यहां भी इस विभाग के द्वारा जितने कार्य किये जाते हैं उनका ओवरआल कंट्रोल एक कमीशन के पास हो यह मेरी इल्तजा है।

अधिष्ठाता महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि हमारे सार्वजनिक निर्माण मंत्री का ध्यान हमारे पर्वतीय जिलों की तरफ विशेष रूप से है। यह बहुत पिछड़े हुये जिले हैं। सारे भारतवर्ष से हरसाल लाखों लोग वहां यात्रियों के रूप में या टूरिस्टों के रूप में जाया करते हैं। सब लोग जानते हैं कि हम पिछड़े हुये हैं लेकिन हमारा पिछड़ापन केवल हमारे लिये ही दुख की बात नहीं है बल्कि समूचे भारतवर्ष के लिये दुख की बात है। मैं यह चाहता हूं कि समूचे भारतवर्ष के लिये जो संकोच और दुख की बात है उस पर सरकार का अधिकाधिक ध्यान जाना चाहिये। यह प्लानिंग का सिद्धांत ही है कि जो सबसे पिछड़े हुये लोग हैं उनकी तरफ सबसे पहले सरकार का ध्यान जाय और उनके उत्थान के लिये सब से पहले सरकार चेष्टा करे। सोशलिज्म का भी यही सिद्धांत है कि सबसे नीचे के स्तर से उत्थान प्रारम्भ किया जाय। श्रीमन्, हम लोग कितने पिछड़े हुये हैं इसके सबूत में मैं स्वयं अपने प्रदेश के मुख्य

मंत्री का लेख पेश करना चाहता हूं जो उन्होंने कुछ महीने पूर्व केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा करने के बाद स्टेट्समैन में लिखा था। उसके कुछ अंश मैं आपके सामने आपकी आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं। "

"This is one of the poorest areas in Uttar Pradesh. There is practically only one crop, kharif, and the terrain being what it is, it seems to me that there is not much room for increased wealth from agriculture, but horticulture holds out great hopes."

मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि यह उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ हिस्सा है। यहां पर खरीफ की सीढ़ियोंनुमा खेती होती है। उसमें मुझे लगता है कि कृषि का इस जिले में कोई भविष्य नहीं है। अगर भविष्य है तो वह केवल बागवानी का है। यह उन्होंने लिखा है श्रीमन्, बागवानी ऐसी चीज है जिसका भविष्य गढ़वाल में है तो सही लेकिन केवल बागवानी से वहां के इंसान जिन्दा नहीं रह सकते क्योंकि बागवानी से जो फल-फूल होगा वह बाहर नहीं जा सकता। हमें बागीचे लगाना है लेकिन वहां पर हम केवल इसके सहारे जिन्दा नहीं रह सकते हैं। इसलिये आवागमन यानी यातायात की सुविधा सबसे अधिक जरूरी है। जब वहां पर आप सड़क ज्यादा बनायेंगे तो उन पर मोटर जायंगी। इससे यातायात की सुविधा बढ़ेगी। तब बागवानी का भविष्य भी बढ़ सकता है। तब इसकी तरफ और लोगों की रुचि होगी और लोग बगीचे लगायेंगे। लेकिन अभी तक वहां पर जो बगीचों में फल-फूल पैदा होता है वह सब वहीं पर सड़ जाता है। इससे उस जिले का हित नहीं है बल्कि सारे प्रदेश का अहित हो रहा है। इसलिये मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारा भविष्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के हाथ में है। अगर सार्वजनिक निर्माण विभाग हमारी ओर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे और हमारे लिये ज्यादा से ज्यादा यातायात की सुविधा उपलब्ध करे तो हम लोग ऊपर उठ सकते हैं।

मैं आपके द्वारा सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि मैं बराबर दो वर्ष से उनसे कहता आया हूं कि चाहे आप हमें स्कूल न दें, चाहे आप हमें अस्पताल न दें और आप हमको अन्य सुविधाएं न दें, लेकिन आप हमें सड़क जरूर दें और हमारे मुल्क में पुल अवश्य बनावें। हमारे लिये जो प्लानिंग से रुपया दिया जाता है उसको आप लैप्स न होने दें तो हम सोचते हैं कि हम तरक्की करेंगे। हमको सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने आश्वासन दिया था और मैं सोचता हूं कि वह अब भी उस आश्वासन पर दृढ़ हैं। वह यह कि अगर उनके सामने कोई योजना हम रखें या कोई ऐसी सड़क की ऐसी योजना रखें जिससे प्रदेश का हित हो सकता हो, या उससे औद्योगिक विकास वहां पर हो सकता हो तो उस पर वह जरूर ध्यान देंगे। यह भी उन्होंने कहा था कि अगर पंचवर्षीय योजना में उन सड़कों को शामिल न किया गया हो तब भी हम कोशिश करेंगे कि कंटिन्जेंसी फंड इत्यादि से उन सड़कों को बनवाने की व्यवस्था करें। मुझे खेद है कि मैंने ऐसे प्रस्ताव निर्माण मंत्री के सामने और विभाग के अन्य अफसरों के सामने रखे, लेकिन कोई भी सड़क बजट में नहीं आई। स्वयं मंत्री जी के सामने मैं कई बार लिख कर भी दे चुका हूं कि मेरे इलाके के लिये जरूरी है कि खिरसू से श्रीनगर तक मोटर मार्ग निर्माण कराया जाय तथा खिरसू से रुद्रप्रयाग तक सड़क बनायी जाय। यह इलाका एकदम अलग पड़ा हुआ है। मैंने प्रार्थना की थी कि समूचे गढ़वाल के उत्कर्ष के लिये तथा पर्यटकों के लिये आप ऊखीमठ से चमोली तक मोटर मार्ग बनवायें। लेकिन मुझे खेद है कि अभी दो-तीन दिन पहले विभाग से मेरे पास जवाब आया है कि चूंकि इनका द्वितीय पंचवर्षीय योजना में समावेश नहीं किया गया है इसलिये यह कार्य नहीं हो सकते। मुझे दिलासा दिलाया गया था कि यह पंचवर्षीय योजना में शामिल हों या न हों, यह कार्य होगा, लेकिन जबाब [illegible]ी

[श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी]

डिपार्टमेंट से आया है कि चूंकि योजना में नहीं है इसलिये नहीं हो सकता। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से फिर प्रार्थना करूंगा कि यह तरीका हमारी उन्नति का साधक नहीं बाधक है और यह छोड़ा जाना चाहिये और हम लोग जो सुझाव देते हैं वे देश की, प्रदेश की तथा उस क्षेत्र की जनता की भलाई का ध्यान रखते हुये देते हैं, इसलिये उन पर विचार किये जायं तथा उन पर अमल किया जाय।

श्री अधिष्ठाता---अब जो कटमोशन्स आये हैं उनमें से जिनके प्रस्तावक उपस्थित हैं वे प्रस्तुत किये गये माने जायेंगे।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---मैं एक व्यवस्था के बारे में कहना चाहता हूं। मान्यवर, विरोधी दलों की तरफ से जो आपस में समझौते के बाद नाम आये हैं मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप उस नाम की लिस्ट के अनुसार ही बुलाने की कृपा करें क्योंकि यह तय हो चुका है कि कटौती का प्रस्ताव नेता विरोधी दल के नाम से आता है और जिसको हम चाहते हैं उनको बोलने के लिये आप बुलाते हैं।

श्री अधिष्ठाता---वही तो मैं करूंगा।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला बेवरिया)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, किसी पिछड़े देश के लिये दो दृष्टिकोणों से आवश्यक है कि उसके यातायात के साधन सुदृढ़ हों---एक तो आंतरिक युद्धों से बचने के लिये और दूसरे वाह्य आक्रमण से अपनी रक्षा करने के लिये। श्रीमन्, मैं और कोई बात करने के पहले अपने माननीय मंत्री जी का ध्यान एक ओर ले जाना चाहता हूं। वह पहाड़ी इलाका जो तिब्बत की सीमा पर पड़ता है, अधिष्ठाता महोदय, मुझे और माननीय सदस्यों को कुछ ऐसी खबर मिली है कि वहां पर कुछ भागों पर चीनी फौजों ने बहुत पहले से कब्जा कर लिया है और इसकी जानकारी भी माननीय सदस्यों और सरकार को संभवतः नहीं है। उसका मुख्य कारण केवल यह है कि मैदानी इलाकों में रेलवे, रोडवेज, जल-वे और अन्य साधन हैं, साथ ही हवाई जहाज से भी आने-जाने की सुविधा है, लेकिन पहाड़ी इलाके हैं वहां पैदल आने-जाने की सुविधा भी नहीं है, जो हमारे कर्मचारी हैं, मैं उनको कोसना नहीं चाहता क्योंकि बार-बार इस सदन में इस प्रकार का प्रश्न उठाया जाता है भ्रष्टाचार के सिलसिले में, कम काम करने के सिलसिले में या अन्य शिकायतों के सिलसिले में, तो माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अधिकारियों को कोसना नहीं चाहता बल्कि केवल उनसे निवेदन करूंगा कि देश अपना है और जो कुछ उनको पैसा मिल रहा है किसी विभाग पर खर्च करने के लिये वह एक गरीब मुल्क के लिये बड़ी मेहनत और परेशानी का पैसा है। उसको जहां तक हो ईमानदारी और सच्चाई से खर्च किया जाय और ऐसा काम किया जाय जिससे इस देश की गाड़ी आगे बढ़ सके। मैं उनसे वही आशा करता हूं और निवेदन करता हूं कि हम लोग इस देश के साधारण नागरिक हैं लेकिन उनके पास डबल पोर्टफोलियो है क्योंकि वह साधारण नागरिक होने के साथ-साथ अधिकारी भी हैं इसलिये मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे ऐसा काम करें जिससे उनको कभी भ्रष्टाचार के सिलसिले में न सुनना पड़े। वे इसपर गम्भीरता-पूर्वक विचार करें और ऐसा निर्माण-कार्य करें जो स्थायी हो और उनके खिलाफ शिकायत करने की आवश्यकता न पड़े।

इसके अतिरिक्त मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर एक समय के लिये मैदानी इलाके के काम को बन्द कर दें और कुछ दिनों के लिये पूरा पैसा पहाड़ी इलाके के लिये खर्च करें तो वह हमारे प्रदेश के गौरव और उसकी रक्षा के हित में होगा। तिब्बत के बार्डर तक पहुंचने के लिये यातायात के साधन दुरुस्त हो जायं ताकि आसानी से उस जगह तक पहुंचा जा सके क्योंकि मैं आपको संकेत देना चाहता हूं कि इस प्रदेश में विदेशियों के घुसने के लिये केवल वही एक मार्ग है। उत्तरी भाग का एक-चौथाई बफर स्टेट के तौर पर नेपाल भी है लेकिन उसकी स्थिति बड़ी पिछड़ी हुई है। इसलिये उधर ध्यान जरूर जाना चाहिये और अगर अधिक पैसा भी वहां पर खर्च करना पड़े तो उसे करना चाहिये।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो अनुदान पेश किया गया है यह बहुत कम है और इसको बढ़ाना चाहिये। इसके साथ ही साथ जो शिकायतें हैं उन पर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। देवरिया जिले के दौरे के सिलसिले में मैं आपका ध्यान दो-तीन चीजों की ओर दिलाना चाहता हूं। एक तो मुझे यह कहना है कि एक अन्तर्प्रांतीय मार्ग जो नम्बर २८ निर्धारित है जो कि कसिया होते हुये तमकुही रोड से आगे बिहार को जाने वाला मार्ग है, उसके बारे में एक सुझाव माननीय मंत्री जी को और अधिकारियों को भी मैंने भेजा था और उस पर मेरी राय अब भी दृढ़ है और मैं चाहता हूं कि मंत्री जी और अधिकारी उस पर पुनः विचार करें। उसमें मेरा जो तर्क है, और जो सही है, वह यह है कि कसिया कस्बे से पार होकर जहां पार करना पड़ता है, वहां पर सड़क अंग्रेजी का जेड बनाती है, वह हाटा कस्बे को पार करने के लिये कस्बे से बाहर बनाई गई है, यह बात समझ में नहीं आती है जब कि पैरेलेल कसिया से तमकुही को दो सड़कें जाती हैं और उनकी दूरी अधिक से अधिक ४–५ मील की है। जो सड़क निर्धारित की गई है, फाजिलनगर वाली वह टेढ़ी है और उसपर २०–३० मील की रफ्तार से ज्यादा नहीं जा सकता है। यह कंक्रीट की सड़क है, उसपर रोडवेज भी चलती हैं इसलिये कोई कारण नहीं है कि जो मार्ग पहले से तैयार है उस मार्ग के बिना बनाये कोई और मार्ग बनाया जाय। उसमें किसानों की जमीन भी लेनी पड़ेगी और उसमें भी दिक्कत पड़ेगी और उसके बाद फिर मिट्टी की भराई में अधिक पैसा खर्च होगा। श्रीमन्, मैं एक सुझाव देता हूं कि घाघी नदी पर काठ के पुल के निर्माण में ६ लाख रुपये से कम खर्च नहीं होगा और जब कुछ अधिक और रुपया खर्च करके और एक नया मार्ग तैयार हो जाय तो उसमें सरकार को क्या कठिनाई है? मैं तो यही समझता हूं कि अगर उससे थोड़ा पैसा और खर्च करके एक मार्ग के बजाय दो मार्ग तैयार हो जायं तो कोई बुरा न होगा। इसमें सरकार का भी हित है और जनता का भी हित है। इसलिये मैं पुनः यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय निर्माण मंत्री जी इस पर विचार कर लें और संभव हो तो खुद चल कर देख लेने का कष्ट करें या जो नक्शा उनके पास है उसी में देख लें कि जिस सड़क के बारे में मैंने सुझाव दिया है वह सड़क अच्छी होगी या जो सड़क पहले से बनी हुई है और जिस पर और अधिक पैसा खर्च किया जा रहा है वह अच्छी होगी। मैं आशा करता हूं कि उस पर वे जरूर ध्यान देंगे।

दूसरी बात यह है कि सलेमपुर से मंझौली जाने वाली सड़क पर के एक पुल को मैंने देखा जिसके बारे में मैंने एक प्रश्न के जरिये सरकार से जानकारी हासिल करने की कोशिश की थी कि किस विभाग के द्वारा उस पुल का निर्माण हुआ है? वह ईंटों का पुल है जो बिल्कुल एक साल के पश्चात् ही बरसात में आधा टूट गया। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इसकी इन्क्वायरी करावें कि किस इंजीनियर द्वारा तथा किस विभाग द्वारा इस पुल का निर्माण हुआ? उस पुल के टूट जाने से यातायात भी नहीं हो रहा है और सारा पैसा भी बर्बाद हो गया। इसलिये सरकार को चाहिये कि वह इसकी इन्क्वायरी करावे।

नेगुआ नौरंगिया के बीच में खड्डा-पडरौना सड़क पर बने पुलों को भी मैंने देखा। उस सड़क पर बने हुए तीन पुल भी उसी तरह से धराशायी हो गये हैं और ज्यों की त्यों उस सड़क की हालत है जिससे यातायात तमाम बन्द है। इस देश की गरीब जनता आधा-आधा पेट खाकर, उपवास रह कर, नंगी रह कर टैक्स देती जाय और सरकारी खजाने में आकर उस पैसे का इस तरह से दुरुपयोग न हो, उस पैसे का अपव्यय न हो, इस तरफ सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये और काम ऐसा करना चाहिये कि जो पक्का और स्थिर हो।

[श्री ब्रजनारायण तिवारी]

जो पिछड़े क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर निर्माण-कार्य इसलिये ठीक से नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि निगरानी करने के समय, जो हमारे आफिसर्स हैं वे पैदल चलने में कठिनाई महसूस करते हैं और जो सरकार ने उनको साधन दिये हैं उनका वे सही इस्तेमाल नहीं कर पाते।

श्री अधिष्ठाता—आपका समय समाप्त हो गया ।

(कुछ ठहर कर)

अब मैं अन्य कटौती के प्रस्तावों को लिये लेता हूं।

अनुदान संख्या ३५

क्रम-सं० प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
[१—श्री राजनारायण, श्री उग्रसेन तथा श्री रामस्वरूप वर्मा।	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में १०० रुपये की कमी कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है।
	प्रस्तावित योजनाओं पर प्राक्कलित व्यय का न होना।
२—श्री ब्रजनारायण तिवारी	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में १०० रुपये की कमी कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है। सरकारी लेबर आर्मी द्वारा निर्माण-कार्य न करा कर केवल ठेके पर कार्य कराना जिसके फलस्वरूप अधिक व्यय, तथा कार्य कमजोर होता है।

अनुदान संख्या ४९

१—श्री राजनारायण, श्री उग्रसेन तथा श्री रामस्वरूप वर्मा।	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि को घटा कर १ रुपया कर दिया जाय। कमी करने का उद्देश्य—नीति का व्योरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है। राजकीय निर्माण-कार्यों में अपव्यय ।
२—श्री ताराचन्द माहेश्वरी	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—नीति का व्योरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है। विधान भवन के नये पार्श्व (विंग) में दो उत्थानकों (लिफ्टों) के अधिष्ठापन की अनावश्यकता पर चर्चा।

[ ] ये कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किये गये, किन्तु श्री अधिष्ठाता की आज्ञा से प्रस्तुत किये गये माने गये।

३––श्री जगदीशप्रसाद — सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में २७५ हजार रुपये की कमी कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य––विशेष विषय जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है।

विधान भवन की सजावट की अनावश्यकता।

४––श्री ताराचन्द माहेश्वरी — सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में १०० रुपये की कमी कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य––विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है।

अत्यधिक गमनागमन वाली सड़क सिधौली से महमूदाबाद और सिधौली से बिसवां का आधुनीकरण न कराये जाने की ओर ध्यान आकर्षित करना।]

*श्री तिरमल सिंह (जिला एटा)––आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, जो अनुदान माननीय मंत्री जी ने सदन के सामने उपस्थित किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस विभाग द्वारा जो कार्य अब तक हुए हैं वे सब सराहने के योग्य हैं। इतना ही नहीं, वैसे तो इधर के बैठने वाले और उधर के बैठने वाले सभी निर्माण की मांग करते हैं किन्तु इस सरकार द्वारा जो निर्माण-कार्य हुए हैं उसकी रूपरेखा इस पुस्तिका में भी हैं। १५ अगस्त, १९४७ के बाद से जो निर्माण-कार्य सरकार द्वारा हुआ है उसका एक ब्यौरा पुस्तिका में है जिसको सभी सदन के सदस्यों ने देखा होगा।

वैसे तो जितने भी कार्य यातायात की सुविधा के लिये सड़कों के सम्बन्ध में किये जांय उतना ही अच्छा है क्योंकि सड़कें आर्थिक अवस्था से भी ताल्लुक रखती हैं, लेकिन चूंकि सरकार के साधन सीमित हैं इसलिये इन सीमित साधनों को देखते हुए जितना भी विकास सरकार ने किया है वह सब प्रशंसनीय है। स्वतंत्रता के उपरान्त प्रत्येक जिले में पक्की सड़कों की प्रगति हुई। उसके विषय में मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे जिले के अन्दर स्वतंत्रता से पहले २०९ मील सड़क थी लेकिन स्वतंत्रता के बाद केवल २३७ मील तक बन कर तैयार हुई, सिर्फ २८ मील का विकास एटा जिले के अन्दर हुआ।

यह तो मैं नहीं कहता कि कहीं और विकास न हो। अल्मोड़ा को ले लीजिये इसमें १३५ मील सड़कें थीं लेकिन अब ३८० मील और ज्यादा बनी स्वतंत्रता के बाद। और भी जिलों में, खास कर पहाड़ी जिलों में ज्यादा बनी हैं। उनका विकास होना भी चाहिये क्योंकि वे बहुत पिछड़े हुए हैं। लेकिन और भी अन्य जिले ऐसे हैं मसलन झांसी और इलाहाबाद जिनमें सड़कों का निर्माण इस पुस्तिका के आधार पर बहुत ज्यादा हुआ है। मुझे यह शिकायत नहीं है कि उनका विकास क्यों हुआ? शिकायत यह जरूर है कि हमारे यहां कम हुआ।

जहां तक पुलों का विवरण है हमारे जिले एटा के अन्दर एक भी पुल नहीं है। एक धुमरी का पुल अलबत्ता आया है जिसको प्लानिंग विभाग ने, पी० डब्लू० डी० ने नहीं, बनवाया है। इस पुस्तिका में पुलों की संख्या भी दी हुई है। कुल ५५४ पुल बने हैं। उनका विवरण

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री तिरमल सिंह]

इस प्रकार है—डेंकिंग के १२, बड़े पुल २९३, छोटे पुल ५६, झूले के पुल ११३, पीपों के पुल ५६, फैरी का सुधार २४, कुल संख्या इस प्रकार ५५४ है द्वित्तीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत। लेकिन हमारे जिले के अन्दर एक भी पुल नहीं बना। मुझे आशा है कि सरकार अब जिले एटा में काली नदी पर पुल अवश्य बनाने का प्रयत्न करेगी ताकि वहां भी यातायात के साधन सुलभ हो सकें। काली नदी ऐसी नदी है जिसको पार करने में जनता को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और जो एरिया काली नदी और बूढ़ी गंगा और गंगा के बीच में हैं इसमें ऐडमिनिस्ट्रेशन की बड़ी दिक्कत रहती है। मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एटा से अमापुर–सहावर सड़क निर्माण करने के लिये आज्ञा प्रदान की है और पिछले बजट में भी रुपया दिया है और इस बजट में भी इसका प्रावीजन है। तो इसी सड़क पर काली नदी पर मुहारे के घाट पर अभयपुरा की सीध में एक पुल पड़ता है उसके बनवाने के लिये भी मंत्री जी शीघ्र आदेश देंगे।

इसके अलावा जहां तक सड़कों का ताल्लुक है एटा जिले में सड़कें कम दी हैं अन्य जिलों के मुकाबले में। वैसे तो मुझे मालूम है कि २१,००,००,००० रुपये का प्लान था जिसमें से १६,००,००,००० रुपये के लगभग सड़कों पर खर्च होना था। लेकिन इस प्लान को प्लानिंग कमीशन ने काट दिया और अब बहुत कम हो गया है। चूंकि मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थायी समिति में पहले मेम्बर था मुझे मालूम है कि जो टार्गेट यहां की सड़कों के मुताल्लिक था.....

श्री अधिष्ठाता—आपका समय समाप्त हो गया।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—अधिष्ठाता महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं। इस विभाग के सम्बन्ध में कुछ थोड़ी सी बातें आपके सामने रखूंगा और विशेष कर मेरा जो कुछ कथन है उसको मैं दो, तीन हेडिंग में रखूंगा। प्रथम तो यह है कि इस विभाग में धन का बड़ा दुरुपयोग होता रहता है, या यों कहें कि कहीं तो जरूरत से ज्यादा रुपये का व्यय है और कहीं जितनी जरूरत है उतना भी नहीं। इस बजट में ही २,१७,००० रुपये की एक मद है जिसमें दिल्ली में प्रान्त के मंत्रियों के निवास-स्थान बनाने का आयोजन है, जब भी यहां के मंत्री दिल्ली जायेंगे वहां सुविधा से रह सकें। श्रीमन्, कोई रंज की बात नहीं है, अच्छा है मंत्रियों को स्थान मिला करे, लेकिन इसी क्षेत्र में हमारे सचिवालय में कुछ निम्न कर्मचारी रहते हैं जिनकी तादाद एक हजार है और उनमें से अभी तक केवल ३०० के लिये निवास-स्थान दिया जा चुका है और ४०० वेटिंग लिस्ट में हैं। इन ४०० में से ६० के लिये इस बजट में प्रावीजन है। १,५१,००० रुपये की लागत से क्वार्टर्स बनाये जा रहे हैं। तो यह भी जीव हैं इनके निरंतर साल भर रहने के लिये स्थान नहीं बन रहा है।

इसके अलावा विधान भवन, यह अभी कम सुन्दर है। इसको और अधिक सुन्दर बनाया जायगा, इसकी सजावट में व्यय करना बड़ा आवश्यक है जिसके लिये ८,००,००० रुपये व्यय किया जायगा। ११,५०,००० रुपये से तो इसकी वृद्धि की ही जा रही है। उसके अलावा ८,००,००० रुपये सजावट में, गैलरीज में कुछ भित्ति चित्र बनेंगे, मूर्तियां बनेंगी। एक ऐसा निर्माण भी है जिनका पहले होना जरूरी है, ५०० सीनियर बेसिक स्कूल्स जिनके बनवाने के लिये सरकार ने कहा था और उनके बनने में अभी तक केवल २१,००,००० रुपये में से ८२,००० रुपये १९५७–५८ में खर्च किया जा चुका है और ३,००,००० रु० १९५८–५९ में खर्च किया और ४,००,००० रु० इस साल में रखा गया है। यों कहूं कि शुरू से ८ लाख रुपया ही खर्च किया जा सका है जब कि २१ लाख मंजूर था। तो सीनियर बेसिक स्कूल पर जितनी रकम मंजूर है उसका एक तिहाई भाग भी खर्च नहीं हुआ जब कि विधान भवन की सजावट पर कहीं ज्यादा खर्च किया जा रहा है। विधायक लोगों के लिये भी रहने के लिये ७ लाख का प्रावीजन है जिससे कमरों की कमी पूरी की

जायगी। आजकल जो हमारे विभाग की ओर से इमारतें बन रही हैं वह सभी विदेशी प्रकार की होती हैं। सामान भले ही ज्यादा लगता हो लेकिन वह हमारे गरीब देश के लिये कितनी उपयुक्त होंगी, इसमें मुझे संदेह है।

हमारे कानपुर जिले में एक विचनू जगह है। वहां ७१ हजार रुपये के एस्टीमेट में कुछ क्वार्टर पुलिस के बने हैं। मुझे वहां यह देखने को मिला कि ७१ हजार रुपये में ८ क्वार्टर्स कांस्टेबिल्स के लिये और ३ हेड कांस्टेबिल और थानेदारों के लिये बनाये गये। कांस्टेबिल का एक एक क्वार्टर ५ हजार रुपये में पड़ा और १२ हजार में पड़ा थानेदारों और हेड कांस्टेबिलों का। इतने रुपये में एक कमरा बैठने के लिये और एक कमरा सामान रखने के लिये बन पाया है जब कि इस रुपये से एक पूरी इमारत बन सकती है। थानेदार ने बताया कि उनका जो शौचालय है उसका दरवाजा ३० इंच चौड़ा है जब कि ३३ इंच का सीना एक थानेदार के लिये होना जरूरी है। थानेदार सीधा उसमें घुस भी नहीं सकता है। जो स्वीपर वहां पर जाय और अगर सीधी सीधी टोकरी वहां ले जाना चाहे तो वह नहीं लेजा सकेगा। यह इसलिये है कि अमेरिकन डिजाइन होती है उसी के मुताबिक ठेकेदार को बनाना होता है। चाहे वह भारतीय परिस्थितियों में उपयुक्त हो या नहीं।

हारकोर्ट बटलर इंस्टीट्यूट के सम्बन्ध में कहा गया कि २,५२,९०० रुपया इसलिये खर्च किया जाएगा कि विशेष मरम्मत की जाएगी। उसी के नीचे लिखा है कि छत दोबारा बनाई जा रही है। छत दोबारा बनाये जाने से सरकार की बहुत सी बातों का उद्घाटन होता है, इसलिये उस धन को विशेष मरम्मत में डाल दिया गया। हुआ यह कि छत बनाई गई और वह नुक्सदार निकली। यह नुक्स न पकड़ी जाय इसलिये दूसरे रूप में उसे लाकर यहां पर दिखाया गया। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में ६,६६,००० रुपया इसलिये खर्च किया जायगा कि एक गहरी जमीन को भरा जायगा। एक गहरी जमीन को भरने के लिये इतना रुपया खर्च किया जा रहा है। इसी प्रकार कानपुर में श्रमायुक्त के निवास स्थान के लिये ६०,००० रुपया रक्खा गया है जिसमें से २०,००० की सिर्फ भूमि ली गई है। लेकिन वहीं पर औद्योगिक गृह निर्माण में ९५० आवासों के लिये २५,००,००० रुपया है। एक आदमी के लिये ढाई हजार का बनकर तैयार होगा। औद्योगिक जो कर्मचारी है इसका मकान ढाई हजार में बनकर सुविधाजनक रह सकता है लेकिन श्रमायुक्त के लिये ६०,००० से कम में नहीं बनेगा।

मैं कुछ सड़कों के बारे में भी कह देना चाहता हूं। ग्रान्ट ट्रंक रोड के बारे में चर्चा है। हमारे कानपुर की तरफ ४ मील तैयार हुई और ५,००,००० रुपया खर्च हुआ। यानी एक मील में सवा लाख रुपया। श्रमदान की बनी हुई जो सड़के हैं उनके सम्बन्ध में कहा गया। पक्का करने के लिये डेढ़ लाख रुपया सरकार ने किसी समय मंजूर किया। अगर श्रमदान की सड़क को जल्दी पक्का न करेंगे तो हो सकता है कि वह बरसात में बह जाय। यह डेढ़ लाख रुपया आज तक खर्च न हो सका क्योंकि पिछले साल १,००,००० रुपया खर्च करने का प्रोवीजन था, लेकिन उस में से एक पाई भी व्यय न हो सका। इस साल फिर २५,००० रुपये खर्च होने की बात है और ३ साल से बराबर टाला जा रहा है। यह सड़कें जो श्रमदान से बनी हैं अगर उन को पक्का न किया गया तो उन का नामोनिशान भी न रह जायगा और जो कच्ची सड़कें श्रमदान से बनी हैं वह सब बह कर, उड़ कर गायब हो जायेंगी। कानपुर में केवल एक सेंगुर नदी का काम हुआ है और उस के अलावा कोई काम नहीं हुआ है। जिले में जहां जहां पुलों की आवश्यकता है उन के न बनने से बड़ी दिक्कत होती है। हमारे यहां जी० टी० रोड से एक रोड सरसौल से साढ को जाती है उस पर सुचौली घाट का पुल बनाना बहुत जरूरी

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

हैं इस के बगैर बड़ी असुविधा होती है । यह काम ५० हजार या एक लाख में पूरा हो सकता है । जनता की इस के लिये बड़ी जबरदस्त मांग है, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई ध्यान इसकी तरफ नहीं दिया है । आप वाराणसी क घाटों के लिये ५५ लाख के व्यय की बात सोचते हैं, और जैन मन्दिर के लिये ५ लाख रुपया व्यय कर सकते हैं इस तरह से ६० लाख का यह व्यय है और नेशनल स्टेडियम के लिये आप १३ लाख रुपये का खर्च कर सकते हैं, यह चीजें भी जैसे जैसे धन की सुविधा को जरूरी हो सकती हैं, लेकिन अगर कुछ जरूरी सड़कों और पुलों पर भी सरकार का ध्यान जाय तो अच्छा है ।

हारकोर्ट बटलर टेकनालाजिकल इन्स्टीट्यूट को आपने ३ लाख ६१ हजार रुपया एक बार दिया और ४ लाख ९० हजार की रकम एक बार उस के इक्विपमेंट के लिय दिया उस से मुझ कोई एतराज नहीं है, लेकिन जो यह काम होते ह जो बड़ बड़ अस्पताल हैं उन में चार चार सौ बेड हैं उनमें निर्धनों को स्थान नहीं मिलता । जिन को मेडिकल एड की वाकई जरूरत होती है जिन के पास पैसा नहीं है और जो सरकार के सहारे ही इलाज करा सकते हैं उन को स्थान नहीं मिलता। मैंने एक सवाल पिछले शुक्रवार को किया था कि इस तरह से डाक्टरों ने निर्धन व्यक्तियों की भरती बन्द कर रखी है और वह इसलिये गरीबों को भरती करना उचित नहीं समझते क्योंकि वे निर्धन हैं । आज ऐसी स्थिति है तो अस्पतालों में चाहे ६ लाख रुपया आप रोज खर्च करें लेकिन अगर वहां गरीबों को स्थान नहीं मिलेगा तो उन का सही लाभ जनता को नहीं मिलेगा इसलिये बड़ी बड़ी योजनाओं के अतिरिक्त छोटी छोटी आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाय ।

श्री हरिश्चन्द्र सिंह (जिला बदायूं)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो अनुदान माननीय निर्माण मंत्री जी ने सदन क सम्मुख उपस्थित किया ह म उसका समथन करन क लिय खड़ा हुआ हूं । किसी भी देश में सड़कों की उतनी ही ज्यादा आवश्यकता है जितनी कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिये नसों की आवश्यकता है । जिस देश में सड़कों की कमी हो वह देश तरक्की नहीं कर सकता, इसलिये में मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि हमारे यहां सड़कों की बहुत आवश्यकता है और जितना अधिक से अधिक ध्यान सड़कों की ओर आकर्षित किया जा सके उतना ही अच्छा है । यातायात के साधनों के बगैर उत्पादन में भी वृद्धि नहीं हो सकती और न देश उन्नत हो सकता है और जो उत्पादन होगा भी उस के वितरण में कठिनाई उपस्थित हो जायगी। बहुत सी चीजें जरूरी हैं, सुन्दर भवनों की भी जरूरत है, चौड़ी चौड़ी सड़कों की भी जरूरत ह, वह सीमेन्टेड हों उन के दोनों तरफ गमले हों। लेकिन देखना यह है कि किस चीज की ज्यादा आवश्यकता है और यदि बजट बनाते वक्त सब से पहले उन का ध्यान हम न रखेंगे तो जिस लक्ष्य पर हम पहुंचना चाहते है उस तक पहुंचने में उतनी ही देर लगेगी जितनी कि एक ऐसी सड़क पर जिसमें गड्ढे वगैरह हों, जिसमें ठीक रास्ता बना हुआ न हो तो जैसे बैलगाड़ी पर या घोड़िया पर चढ़कर पहुंचने में देर लगती है उतनी ही देर लक्ष्य तक पहुंचने में लगेगी। अगर सड़कें ज्यादा होंगी तो मोटरों के जरिये जैसे २-३ घंटे में पहुंच गये और बैलगाड़ी से ३-४ दिन में भी मुश्किल होता है । तो मालूम पड़ता है कि सबसे ज्यादा जरूरत सड़कों के बनाने की है । जो संग्रहालय, जो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं और भवन बनाये जा रहे हैं अगर उनको ४, ६, १० वर्ष के लिये स्थगित कर दिया जाय और सड़कों पर जोर दिया जाय तो मैं समझता हूं कि हम बहुत जल्दी तरक्की कर सकेंगे । अट्टालिकाएं, म्यूजियम्स, ये चीजें जो हम बना रहे हैं मैं समझता हूं कि इनमें धन व्यर्थ जा रहा है, वह हमको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में दर कर देगा । मैं नहीं कहता कि इन चीजों की जरूरत नहीं है, जरूरत है, लेकिन यह जरूरत उस वक्त होगी जबकि अपनी और जो बड़ी जरूरतें हैं उनको हम पूरा कर लें ।

मैं आपको मिसाल के तौर पर अपने इलाके की बात बतलाना चाहता हूं । जब मैं अपन इलाके में घूमता हूं, या जब जाता हूं तो वहां पर मोटरों की पहुंच तो है नहीं । १८९५ या ९४ के करीब साढ़े ६–७ मील सड़क बनी थी उस इलाके में, अंग्रेजों का राज्य व्यतीत हो गया ११–१२ वर्ष हमने अपने स्वराज्य के व्यतीत कर लिये, लेकिन वहां पर उस साढ़े ६–७ मील

सड़क के बाद अबतक एक कंकड़ भी नहीं रखा गया। आबादी २ लाख के करीब है। जब मैं जाता हूं तो लोग मुझसे प्रश्न किया करते हैं जिनका मैं जवाब नहीं दे पाता और माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वह मुझे जवाब बतलायें वह मैं कह दूं। हर डिपार्टमेंट के वह अलग-अलग बतलाया करते हैं, लेकिन इस पी० डब्लू० डी० में ही ले लीजिये कोई इलाके में काम हुआ हो तो मुझे बतला दीजिये? मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जिस वक्त धन की बांट करें, जिस वक्त कि वह सड़कों का बटवारा करें, तो उन पिछड़े हुए अभागे इलाकों का भी ध्यान रखें जिनके अन्दर कोई भी आज तक चीज नहीं हुई है। मैंने अपने जिले में जो अधिकारी वर्ग हैं उनसे पूछा कि भाई, इस जिले में सड़कें बहुत कम आ रही हैं, क्या कारण है कि इस इलाके में तो सड़क बनी ही नहीं है? तो उन्होंने एक कारण बतलाया कि यह इलाका बदायूं का बड़ा बदकिस्मत है, जिस वक्त स्टार और ग्रिड का फ़ारमूला लगाया गया तो तकसीम और जरब करने में १०० मील सड़क यहां कम लिख गयी, इसलिये यहां सड़क नहीं आ रही है। मैंने कहा कि कुछ लिखा पढ़ी करो, तो कहा कि कर रहे हैं। हो रही होगी, लेकिन उसका पता कुछ नहीं चलता।

जिस इलाके में मैं रहता हूं वह इलाका बैकवर्ड है। उसमें अक्सर सैलाब आया करते हैं। सैलाब के जमानें में जानें बचाना मुश्किल है फसल को बचाने का क्या सवाल है? तो जानें कैसे बचावें जब कि सड़क तक उस इलाके में नहीं हैं। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि यह इलाका, दातागंज परगना सलैमपुर जोकि शायद इस गवर्नमेंट के लगान और मालगुजारी के वसूल करने के हिसाब में तो है, लेकिन कोई चीज उसको मिले, उसका पन्ना या तो किसी दूसरे पन्ने के साथ चिपट गया है या उसका पन्ना लिखा ही नहीं गया है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से फिर एक बार प्रार्थना करूंगा कि जरा उस इलाके की ओर भी ध्यान दें नहीं तो देहाती लोग तो यही कहा करते हैं कि साहब, अब की तो हमने तुमको भेजो है, तुम हूं कुछ नहीं कर पाये।

एक चीज और हमारे बीच में बड़ी बाधा डालती है और वह यह है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड तो खत्म हो गये, लेकिन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रोड अब भी चली आती हैं। जब बोर्ड ही नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रोड भी नहीं रहना चाहिये। हमारे यहां सादुल्लागंज के पास नरहा का एक पुल है जो सन् १९२४-२५ में बना था और मिट्टी से इधर उधर बांध कर खड़ा कर दिया गया था। वह मिट्टी बह गयी। २४ वर्ष से वह पुल वैसे ही खड़ा है, कोई यातायात उस पर नहीं होता और आदमी उसके पास डूबते रहते हैं। जब मैं उस इलाके में जाता हूं तो वहां के आदमी कहते हैं कि बाबूजी चंडोल खड़ा देखा है आपने? मैंने कहा क्या है वह, तो कहते हैं कि उसमें १-२ आदमी हर साल डूब कर मर जाते हैं और वही नरहा का पुल मुझे दिखाया जाता है। वे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, प्राविंशियल बोर्ड और प्राविंशियल स्टेट वगैरह नहीं जानते। वे तो यह जानते हैं कि सरकार का राज्य यहां भी है और उसमें ऐसा काम होता है। इसलिये मंत्री जी जरा परगना सलेमपुर, तहसील दातागंज का ख्याल करें। यदि सरकार उधर ध्यान नहीं करती तो वहां के लोग मुझे और सरकार को सिवाय गाली देने के और कुछ नहीं दे सकते।

श्री रघुरनतेज बहादुर सिंह (जिला गोंडा)--श्रीमन्, जो कटौती का प्रस्ताव गुप्त जी ने पेश किया है मैं उनके समर्थन हेतु खड़ा हुआ हूं। आजकल अधिकारियों के भ्रष्टाचार की बड़ी चर्चा हो रही है परन्तु भ्रष्टाचार किस कारण होता है, उसके निराकरण का क्या उपाय है यह मैं आपके सामने बताना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता--यह तो जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन पर आप बता देंगे।

श्री रघुरनतेज बहादुर सिंह---बात जनरल ही है। श्रीमन्, आज आप देखते हैं कि १२० रुपये पर ओवरसियर रखे जाते हैं और उनसे यह आशा की जाती है कि वे सब काम ठीक से करें। और जब कोई नौकरी का विज्ञापन निकलता है तो हम एम० एल० एज०, मंत्री लोग और दूसरे लोग सिफारिशों द्वारा अपने अपने आदमियों को चुनवा देते हैं और नतीजा यह होता है कि इंडिपेंडेंट और ईमानदार आदमी को चुनने में बड़ी दिक्कत पड़ती है। बाद में जब वही आदमी काम करने लगते हैं तो उनके खिलाफ हाउस में शिकायतें की जाती हैं। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि कोई भी ओवरसियर २५० रुपये से कम की तनख्वाह पर न रखा जाय। आप शुरू में कम तनख्वाह देते हैं और बाद में बढ़ाते हैं उससे कोई नतीजा नहीं निकलता। जब इकाई करप्ट रहेगी तो कैसे काम चलेगा? इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि अच्छे आदमियों को लेने के लिये हम उन्हें उचित तनख्वाह दें तब उनसे इस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि वे सही काम कर सकेंगे। इस पर सरकार यह कहेगी कि अगर हम तनख्वाह बढ़ायें तो हमारे पास धन नहीं है। इसके लिये मैं निवेदन करूंगा कि बड़ी बड़ी कास्टली इमारतें जो बन रही हैं वह रोक दी जायं। क्या हम लोग एम० एल० एज० और मिनिस्टर होकर यह भूल जाते हैं कि हम उसी छप्पर में रहते थे, उसी गांव में रहते थे जिनमें ८६ प्रतिशत लोग रह रहे हैं? क्या कारण है कि हम आज शान शौकत से रहें, अच्छा आराम चाहें और बड़े बड़े बंगलों में रहें? क्या छोटे कमरों, तखत और चारपाई से हम गुजर नहीं कर सकते हैं? बड़ी बड़ी मेज और सोफे सैट से काम चलाने की क्या जरूरत है? इन चीजों पर जनता का अपार धन व्यय होता है उससे हमारे अन्य कामों की प्रगति में बाधा उत्पन्न हो जाती है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि हमें हमेशा इस बात को ध्यान में रखना चाहिये कि हम गरीब किसान के लड़के हैं और गरीब देश के लड़के हैं और मिनिस्टर होने से पहले या एम०एल०एज० होने से पहले जैसे हम रहते थे उसी तरह से रहें। जब हम सादगी से रहेंगे तो जो हमारे अधिकारी और कर्मचारिवर्ग हैं, वह देखेंगे कि हम किस तरह से रह रहे हैं तो उन पर भी उसका असर पड़ेगा। यदि हम बनावटी ढंग से रहें, यदि हम ऐश्वर्य में रहें और दूसरों से यह तवक्को करें कि वह सीधी सादी हालत में रहें तो यह नामुमकिन है।

आज हर जगह कम्पेटीशन आफ लाइफ है। हम लोगों को चाहिये कि हम एलेक्शन की तरफ ध्यान न देकर सेवा भाव ही की तरफ ध्यान दें। यह भावना हमारी नहीं होनी चाहिये कि अगर हम मेम्बर हो गये तो हमें अच्छी तरह से रहने को मिलेगा और हम मिनिस्टर हो जायंगे तो और अच्छे ढंग से रहेंगे, बल्कि हम में सेवा भाव ही रहना चाहिये। इसलिये श्रीमन्, मैं निवेदन करूंगा कि आज इस बात की आवश्यकता है कि हम पहले अपने आपको बनायें और तब दूसरों से कुछ आशा करें। जब हम अपने आप को इस तरह बना लेंगे तो हमारे देश में जो आज व्यापक भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसका हम निराकरण कर सकेंगे।

एक और खास बात यह है कि पी०डब्लू० डी० का शिड्यूल रेट अलग है, म्युनिसिपैलिटी का अलग है और डिस्ट्रिक्ट कौंसिल का अलग है। पी०डब्लू०डी० का शिड्यूल रेट ज्यादा है तो क्या मैं यह जानूं और इस पर विश्वास करूं कि अन्य विभाग के जो इंजीनियर्स हैं वह कमजोर इमारतें बनाते हैं और केवल पी०डब्लू०डी० के इंजीनियर्स ही अच्छी इमारतें बनाते हैं? लिहाजा सबके शिड्यूल रेट्स में समानता होनी चाहिये। यह कहना कि पी०डब्लू०डी० की ही इमारतें मजबूत बनती हैं और दूसरे विभाग की इमारतें कमजोर बनती हैं तो मैं इसको मानने के लिये तैयार नहीं हूं।

दूसरी बात यह कि शहरों में जो बड़ी बड़ी सड़कों के निर्माण पर इस समय अपार धन व्यय किया जा रहा है उसको एक दम रोक दिया जाय और इन सड़कों के निर्माण को भी रोक दिया जाय क्योंकि देहात की सड़कें बहुत जीर्णशीर्ण दशा में हैं। मेरे क्षेत्र सादुल्ला नगर, बूढापार, जिला गोंडा में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक इंच भी पक्की सड़क अब तक नहीं बनाई गई है हालांकि माननीय गोविन्द बल्लभ पंत और माननीय हुकुम सिंह जो दस गुना

लगान के प्रचार के सिलसिले में जब वहां गये थे तो उन्होंने वायदा किया था कि इस क्षेत्र को हर किस्म की सुविधा दी जायगी। मैं भी उस समय कांग्रेस का सदस्य था और मैंने १०/१२ लाख रुपया जमा कराकर दिलवाये। उसके बदले में आज तक वहां एक गैंग हट भी नहीं बना। अगर एक गैंग हट का बनना वहां के लिये साबित हो जाय तो मैं माननीय मंत्री जी का बड़ा आभारी होऊंगा।

श्रीमन्, पुलों की हालत भी बड़ी जीर्णशीर्ण दशा में है। मैं आपके द्वारा प्रार्थना करूंगा कि सिंगारघाट और अमघटी पुल को बनाने के लिये विशेष अनुदान दिया जाय। वहां पर की ग्राम पंचायतें और डिस्ट्रिक्ट कौंसिल ने भी धन दिया है, लेकिन वह अपर्याप्त है और अधिक धन की आवश्यकता है। आज हालत यह है कि सड़कें ले ली जाती हैं, लेकिन जिला स्तर पर सलाह नहीं ली जाती है। इसलिये मैं आपके द्वारा मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जब कभी सड़कों के बनाने का प्रपोजल हो तो जिला स्तर पर और प्रदेशीय स्तर पर नान-आफिशियल्स की भी राय ले ली जाय कि कौन-कौन सी सड़कें लेने के काबिल हैं। केवल कैबिनेट का फैसला ही सारे प्रांत का फैसला नहीं माना जाना चाहिये। एक और आदेश सरकार द्वारा यह हुआ है कि जिन पुलों पर टोल टैक्स लिया जाता है वह एम०एल०एज० और एम०पीज० से भी लिया जाय चाहे वह ड्यूटी पर ही जाते हों। क्या कारण है कि गवर्नमेंट के काम से जब कि मंत्रीगण या अधिकारीगण जायं तो उनसे कोई टोल टैक्स न लिया जाय और अगर जनसेवक जाय और निजी कार्य के लिए नहीं जाता बल्कि सरकारी और जनता के काम से जाते हैं तो उनसे लिया जाय। इसलिये मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह यह आदेश दें कि गवर्नमेंट ड्यूटी पर अगर जनता के काम के लिये एम० एल० एज० और एम० पीज० जायं तो टैक्स न लिया जाय भले ही जब वह शिकार या अपनी तफरीह के लिये जायं तो टैक्स लिया जाय। मैंने एक सुझाव मुख्य मंत्री को गत वर्ष में भेजा था कि मेरे क्षेत्र की मुख्य सड़कें ले लें। मैंने यह निवेदन किया था कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में रेहरा से बभनान और चन्द्रदीप घाट से मसकनवा तक की सड़कें ले लें। उसका मुझे उत्तर मिला कि इन सड़कों को आइन्दा रखा जायगा। तो मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि उपरोक्त सड़कों को ले लिया जाय। मेरा क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है। वहां पर बरसात के दिनों में सड़कों की इतनी दुर्दशा रहती है कि अगर कोई बीमार हो तो अस्पताल तक नहीं पहुंच सकता। पक्की सड़क बीस, पच्चीस मील की दूरी पर है और स्टेशन के रास्ते में पानी भरा रहता है। इसलिये भूत-पूर्व डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की यह जो सड़कें हैं, जिन पर यातायात अधिक है उनको लेना चाहिये। हमारे क्षेत्र की उपरोक्त सड़कों पर बहुत अधिक यातायात होता है और उनको लेना बहुत आवश्यक है, कारण कि इस क्षेत्र में यातायात के साधन न होने के कारण तथा कोई रोजगार न होने के कारण बहुत गरीब हो रहा है। अतः मैं आपके द्वारा फिर माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह बड़े बड़े खर्चों को घटा कर देहात की तरफ काफी ध्यान दें। मैं तो कहूं कि सड़कों के निर्माण पर प्रान्त की टोटल आमदनी का १/४ खर्चा होना चाहिये। अन्त में मैं इस विभाग के उच्चाधिकारियों की सराहना किये बिना नहीं रह सकता ?

श्री अधिष्ठाता—आपका समय समाप्त हो गया।

श्री जगदीश प्रसाद (जिला मुरादाबाद)—अधिष्ठाता महोदय, इस अनुदान के दो आइटम्स पर विशेषकर मैं कहने को हूं और अधिक समय आप का नहीं लूंगा। पहली मद है इस विधान भवन की सजावट जिस के संबंध में मुझ से पूर्व वक्ता माननीय अवस्थी जी ने काफी कह दिया। इस विधान भवन की सजावट के लिये ८ लाख रुपया स्वीकार

[श्री जगदीश प्रसाद]

किया गया है और उसमें से सवा लाख रुपया इस वर्ष के बजट में है। अधिष्ठाता महोदय, बजट साहित्य में इसका जो कुछ कारण दिया गया है वह इस प्रकार है—

"उन्नत देशों के संसद भवनों एवं राज्य की राजधानियों की सजावट जनता के सामाजिक जीवन तथा अपने देश की स्वतंत्रता के लिये लड़े गये संग्राम के इतिहास से संबंधित विशाल भित्ति चित्रों एवं मूर्त्तियों से की जाती है। ये चित्र उन बहुतेरे व्यक्तियों के लिये जो राज्य विधान सभा देखने आते हैं, शिक्षाप्रद होते हैं, आगे कहा गया है कि तदनुसार १,२५,००० रुपये की धनराशि सम्मिलित की गई है।"

अधिष्ठाता महोदय, मैं नहीं समझता कि दूसरे देशों का जो इसमें हवाला दिया है उनकी जो मिसाल दी गई है, यहां इस बात को सामने रखना चाहिये, इसमें अगर बहुत सारा समय लिया जाय कि आस्ट्रेलिया का पार्लियामेंट हाउस, कनाडा का पार्लियामेंट हाउस, इंग्लैंड का पार्लियामेंट हाउस कैसा है तो यह व्यर्थ होगा। एक मोटी बात रख देना काफी होगा। हम सब जानते हैं कि इंग्लैंड एक तरीके से डेमोक्रेसी की जननी है, वहां के पार्लियामेंट हाउस की यह दशा है कि उसमें हाउस आफ लार्ड्स और कामंस में लोग खड़े रहते हैं। उनको बैठने की पूर्ण जगह नहीं। यही नहीं अगर हिसाब लगाया जाय तो शायद उनको परसीट पर हमारी परसीट से कम हमारी आय के अन्तर को लगाकर खर्चा पड़ेगा। हम यह सोचें कि क्या हमारी आमदनी उन देशों के बराबर है क्या हमारी पर कैपिटा आय उनके बराबर है? क्या हमारा जीवन स्तर उनके बराबर है? हमारे पास देश के निर्माण के लिये रुपया नहीं है। हमने दूसरे देशों से कर्जा लिया। हमारे मिनिस्टर्स वहां गये, लेकिन हमें जितने रुपये की आवश्यकता थी वह नहीं मिला, जिससे हम अपने देश का निर्माण कर पर कैपिटा इनकम बढ़ा सकते थे। ऐसी दशा में विधान भवन की सजावट के लिये रुपया रखना कहां तक वांछित है? किस को अच्छा नहीं लगता कि खूबसूरत बिल्डिंग में बैठें? कौन इस बात को पसन्द नहीं करता कि आरामदेह कुरसी पर बैठें? परन्तु यह सब हम अपने साधन व आय को देखकर ही करेंगे। मेरी यह बात समझ में नहीं आई कि अब तक विधान भवन में बैठकर हमने जो कुछ कानून बनाये उसमें हमारी बुद्धि ने अच्छी तरह से काम नहीं किया और कुछ कानून खराब बनाये, लेकिन अब इसकी सजावट हो जायगी इसमें सुन्दर चित्र लगा दिये जायेंगे तो हमारी बुद्धि कुछ तीक्ष्ण हो जायगी और हम अच्छे कानून बनायेंगे। हमने अब तक भी अच्छे कानून बनाये हैं, और आशा है कि आगे भी ऐसे ही बनायेंगे। जहां तक इसका संबंध है कि जो लोग देखने आते हैं उन पर प्रभाव पड़ता है तो माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री के सामने रखूंगा कि देखने वाले जब यहां पर आते हैं तो उन पर प्रभाव पड़ता है हमारी सादगी का। उन पर हमारे आराम का प्रभाव नहीं पड़ता। अगर वह देखें कि हम खूबसूरत हाल में बैठे हैं, अच्छे-अच्छे पंखे लगे हैं तो उन पर इसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। वह यह देखते हैं कि हम उनकी यहां कैसी नुमाइंदगी करते हैं। अतएव यह मद ऐसी है जिसको टाला जा सकता है। मैंने जैसा पहले कहा किसी को बुरा नहीं लगता कि हम अच्छे सजे भवन में बैठें। यदि हम इसको पांचवीं योजना में लें, यदि हम इसको छठी योजना में ले लें तो कोई अनुचित बात नहीं होगी। मैं उसके लिये माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इसके ऊपर सोचें और इस मद को कम से कम इस वर्ष के लिये जब कि देश में अन्न की कमी है, हमारे देश में दूसरी-दूसरी जगह से अन्न मंगाने की परेशानी है, यह कठिनाई है कि कैसे उसकी पूर्ति करें, तो इस वर्ष के लिए उसको अवश्य छोड़ दें।

दूसरी मद जो इसमें है वह है म्यूजियम के लिए। विकास संग्रहालय जो बन रहा है उसमें डेढ़ लाख रुपया लगने वाला है श्रोतालय के निर्माण के लिए। अधिष्ठाता महोदय, इस म्यूजियम के ऊपर कितना खर्चा किया जाना है मैंने उसको जोड़ा। ७ लाख ६८ हजार रुपया कुल पड़ा है इसकी इमारत पर। जैसा अभी माननीय हरिश्चन्द्र सिंह जी कह रहे थे

क्या इस पैलेशियल बिल्डिंग की आज जरूरत है? मैं तो उसमें गया। मैं और कई और माननीय सदस्य उसको देखकर लौट रहे थे। तो एक सदस्य तो यह कहने लगे कि इसमें जितने बड़े-बड़े कमरे बने हुये हैं उसके एक चौथाई कमरे में एक-एक घर के दो-दो बेटे और दो-दो बहुएं सो रही हैं, मां बाप हैं उसी में दो सुअर भी बंधे हुये हैं और कहीं-कहीं दो बकरियां भी बंधी हुई हैं। उनके घरों को बनाने के लिये सहायता देने की बात जब हम सोचते हैं और कोशिश करते हैं कि लो इनकम ग्रूप के लिये रुपया निकालें तो हमारे पास रुपया नहीं है। उनके घरों को बनाने के लिए रुपया नहीं है, लेकिन इस प्रकार की इमारत के लिये लाखों रुपया खर्च हो चुका है। वह एक अच्छी चीज है। बने। मगर पहले पेट भर जाय तब वह बने। उसको देखकर आने के बाद मेरे ऊपर तो यह प्रभाव पड़ा कि यह बिल्कुल व्यर्थ है। इसको रोक दिया जाय और जब हमारे देश की मुख्य आवश्यकतायें पूरी हो जायं तब इनको लिया जाय।

दूसरी चीज, आज हम लोग इस बात के लिए परेशान हैं, अभी ऐडजर्नमेंट मोशन था दो रोज पहले। उसमें जिक्र हुआ था कि औरतों का मैच था और उसमें अर्द्ध नग्न-स्त्रियां थीं इसलिये नवजवान उसको देखने आये। इसी तरह से यहां भी कभी कोई ऐक्ट्रेस आयेगी, कभी कोई संगीत होगा, कभी कोई ड्रामा होगा, ठीक है किसी को बुरा नहीं मालूम होता, ड्रामा देखना, गाना सुनना, मुझे भी अच्छा मालूम होता है, आपको भी अच्छा मालूम होता है। लेकिन इस विकास संग्रहालय में जो श्रोत्रालय बनेगा उसमें सुनने वाले कौन होंगे? लखनऊ के रहने वाले, उच्च पदाधिकारी, मंत्रि-मंडल के सदस्य और कभी-कभी इस विधान सभा के सदस्यों को भी निमंत्रण होगा, उनके बच्चे, बीबियां और बच्चों को खिलाने वाले नौकर। क्या इसमें कभी कोई किसान आयेगा देखने के लिए? जो मनोरंजन का इंतजाम आप कर रहे हैं वह उस शख्स के लिये कर रहे हैं जिसको अगर देखना हो तो पांच रुपये खर्च करके, दस रुपये खर्च करके महंगे से महंगा टिकट लेकर जाकर देख सकता है। जनता के टैक्स से आप उसके मनोरंजन का प्रबन्ध कर रहे हैं जिसकी बड़ी-बड़ी आमदनी हैं और जनता का पेट न भरे, उसका पेट भरने का इंतजाम न करें। तो यह किसी तरह से हमारी परिस्थिति को देखते हुए उसका बनना उचित नहीं है।

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री से फिर एक बार बहुत जोर के साथ कहूंगा कि इन दोनों मदों के ऊपर वह सोचें और यदि किसी प्रकार संभव हो इन रकमों को निकाल सकें, तो इस साल अवश्य इस रकम को इसमें से निकाल दें।

अब मैं इस अवसर का उपयोग करके एक स्थानीय परिस्थिति के बारे में बतलाना चाहता हूं। दो वर्षों से जब बहुत बाढ़ आई तो उसमें हमारा अनुभव यह हुआ कि हम कार्यकर्त्ताओं ने जिस विभाग से सहायता मांगी उस विभाग ने फौरन सहायता दी, परन्तु मैं माननीय निर्माण मंत्री के सामने यह रखना चाहता हूं कि पी० डब्ल्यू० डी० से सहायता नहीं मिली और इस हद तक नहीं मिली कि जिले के ऊंचे अधिकारियों को परेशान होना पड़ा। एक बार जिलाधीश ने कहा कि मुझे खुद जाना पड़ा पी० डब्ल्यू० डी० इंजीनियर के आफिस में। एक पुल टूट गया था और वह ऐसा टूटा, हसनपुर, चकरौला रोड पर कि उसके टूटने के बाद वह इलाका बिलकुल बन्द हो जाता है, कोई अप्रोच नहीं रह जाती। जब वह टूटने वाला था उसके दो तीन रोज पहले मैंने कहा था कि उसके बचाने का इन्तजाम कर दिया जाय तो वह नहीं टूटेगा। कुछ बैरियर्स लगा दिये जायं। उसके बाद मैं चला गया। यहां मुझे मालूम हुआ कि पुल टूट गया, लेकिन वहां कोई नहीं गया। डी० एम० ने कई बार कहा, एस० डी०एम० ने कहा, जनता ने शोर मचाया,

[श्री जगदीशप्रसाद]

लेकिन पी०डब्ल्यू०डी० के अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसके टूट जाने के बाद बहुत दौड़ धूप की और कहा कि इसको ठीक करवा दिया जाय तो यह वायदा किया गया कि अगली बरसात के पहले अवश्य ठीक कर दिया जायगा। काम जिस प्रगति से चल रहा था उसको देखते हुये हमने कहा कि नहीं पूरा हो सकेगा और वह एरिया फिर कट आफ हो जायगा। एस्टीमेट के मंजूर होने में इतनी देर लगी कि जब तक यहां चीफ इंजीनियर को कांटैक्ट नहीं किया तब तक एस्टीमेट्स मंजूर नहीं हुए। उसके बाद किसी तरह काम चला। एक जगह पर आकर काम रुक गया। ठेकेदार ने यह कहा कि बरसात पंद्रह दिन देर से हो गई तो पुल पूरा बन जायगा, लेकिन पूरे १ महीने के बाद पानी बरसा, फिर भी पुल नहीं बन सका। रास्ता बन्द हो गया। कोई नाव भी वहां नहीं थी। कढ़ाव, लोहे का कढ़ाव जो होता है जिसमें रस पकाया जाता है उसमें बैठकर लोग पानी में उतरे। एक बार तो वह डूब गया। उसमें तीन चार महिलायें भी बैठी थीं। कुशल यही हुई कि वह डूबी नहीं। लेकिन वह पुल बना नहीं। छोटा सा पुल है। डेढ़ साल हो गया। अब भी मैं वहां देख कर आया हूं। जिस प्रगति से काम हो रहा है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि अब की फिर हमें कढ़ाव में बैठकर पार होना पड़ेगा।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)-----माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय जगदीशप्रसाद जी ने अपने जजबात अभी यहां पर पेश किए कि ८ लाख रुपया यहां पर भित्तचित्रों पर, ७५ हजार लिफ्ट पर खर्च किया जा रहा है और इस तरह के अन्य अखराजात हैं या दिल्ली में जो ऐशोइशरत की चीजों पर जो खर्च किया जा रहा है यह न किया जाय। मैं समझता हूं कि चाहे इधर के सदस्य हों या उधर के हों मन किसी का नहीं कहता कि ऐसी फिजूलखर्ची की जाय चाहे पार्टी डिसिप्लिन की वजह से वोट के समय कोई किसी ओर जायं। मैं समझता हूं पी० डब्ल्यू० डी० यह खर्चा नहीं कर रहा है यह तो दूसरे डिपार्टमेंट करवा रहे हैं। पी०डब्लू०डी० एक इग्क्जीक्यूटिंग एजेंसी है जिस किसी डिपार्टमेंट का काम होता है वह एक्जीक्यूट करवाता है। किसी ने कहा मेरी तस्वीर बना दो, किसी ने कहा हमारा म्यूजियम बना दो, किसी ने कहा हमारा महल बना दो और किसी ने कहा पार्क बना दो तो पी० डब्ल्यू० डी० उसे बनाता है। रुपया तो सरकार का संबंधित विभाग देता है। इसको मद्देनजर रखते हुए इस विषय में पी० डब्ल्यू० डी० का कोई कसूर नहीं है। उनको तो कैबिनेट का निर्णय (decision) पूरा करना पड़ता है। यह पी० डब्ल्यू० डी० की अकेली जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि सारी कैबिनेट की जिम्मेदारी है; अभी तक के माननीय सदस्यों की बातों को ध्यान में रखते हुए यह खयाल किया जाना चाहिये।

अभी मैं माननीय ब्रजनारायण जी की बात सुन रहा था। उन्होंने बहुत ठीक कहा कि दुर्गम पहाड़ी इलाकों में कोई आने जाने के साधन नहीं हैं। श्रीमन्, यहां ठोकर लगती है पांव में वहां पहाड़ में तो रास्ते ऐसे हैं कि ठोकर लगती है सर में। इस समय चीन की फौजें हमारे बार्डर पर भरी पड़ी हैं और किसी भी वक्त यह हमला कर सकती हैं। तो जरूरत के वक्त हमारी फौजें कैसे रश करेंगी और कैसे वहां पर पहुंचेगी? हमने कहा कि दानपुर में तहसील बनाई जाय मगर वहां पर बिल्डिंग बनाने के लिये सरकार ने कह दिया कि रुपया नहीं है मगर यहां ८ लाख रुपया की बेकार पेंटिंग होगी। सीमावर्ती पहाड़ी जिलों में हमारे आला अफसरों और फौज के लिये पहुंचने के लिये रास्ता बनाने के लिये पैसा नहीं है। मगर लखनऊ में वाजिद अली शाह के जमाने का नमूना उतारा जा रहा है ताकि हमारा भी नाम उनके या अन्य ऐशोइशरत वाले राजा जैसे शाहजहां के साथ लिया जाय। वहां पर ऐसी जरूरी सड़कें हैं जिनकी तरफ मैं माननीय मंत्री जी और उनके विभाग का ध्यान दिलाऊं कि लाखों का खर्चा नहीं है सिर्फ कुछ हजार का ही है। माननीय मंत्री जी ने उसके लिये कह दिया कि हम मजबूर हैं पैसा नहीं है।

ऐसा ही एक और महत्वपूर्ण मार्ग है। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी बद्रीनाथ की यात्रा करते हैं और शायद कैलाश भी जाना चाहें, लेकिन वहां का रास्ता अच्छा नहीं है तो अब वहां

कैलाश की यात्रा के लिये टनकपुर-पिथौरागढ़ होकर जाते हैं लेकिन मानस खंड में द्वादश ज्योतिर्लिग की बात कही जाती है। तो उसके मुताबिक यह ज्योतिर्लिग जागेश्वर में है। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि कैलाश की यात्रा के लिये जागेश्वर होकर जाना जरूरी है। यह रास्ता कम लम्बा है। वहां पर बाड़े छीना-बेरीनाग मोटर सड़क को यह सड़क जोड़ती है जिसका बनना जरूरी है। इसके अलावा कपकोट कर्मी होकर पिंडारी ग्लेशियर तक की सड़क बनाई जाय। इस सड़क का निर्माण होना चाहिये, क्योंकि इस की मांग बहुत दिनों से चली आरही है। हमको विधान भवन के इन लिफ्टों से कोई लाभ होने वाला नहीं है जिनके लिये लाखों रुपया खर्च किया जा रहा है। जब यहां पर पहले से चिकनी संगमरमर की सीढ़ियां हैं और हाथ रखने के लिये रेलिंग हैं, तो हमारे लिये इन लिफ्टों की क्या जरूरत है। यह तो एक प्रकार का नखरा है। हमें इसकी जरूरत नहीं है। पहले से एक लिफ्ट यहां पर थी ही अब और लिफ्ट लगाने के लिये रुपये का इन्तजाम किया जा रहा है। यह असल में पी० डब्ल्यू० डी० का दोष नहीं है, बल्कि सारी सरकार का दोष है। हम लोग इतने आरामतलब हो गये हैं कि हमको बेचारे गरीब किसानों की याद ही नहीं रह गई है। हमारे अन्दर सिम्पलीसिटी होनी चाहिये।

पुराने विविध निवासों के लिये ९० हजार रुपये का फर्नीचर और लिया गया है जब कि वहां पर पुराना फर्नीचर पड़ा हुआ है। अभी विधान परिषद् के लिये ४३ हजार रुपये का नया फर्नीचर लिया गया। नई फिटिंग वहां पर हुई, लेकिन पुराना फर्नीचर निकाल कर इधर उधर डाल दिया गया है जो बरबाद हो रहा है। मेरा निवेदन यह है कि इस विभाग के काम पूरा करने में अक्सर देर हो जाती है। मैं समझता हूं कि इस साल का एस्टीमेट अगर अगले साल के बजट में आये तो अच्छा रहे। एक बारगी देर में sanction होने से काम भी एकदम करना पड़ता है जिससे काम खराब होता है। हमने देखा है कि हर साल मार्च में एक दम जल्दी जल्दी विभागों का काम करना पड़ता है।

दूसरी बात यह है कि टेक्निकल और एक्जिक्यूटिव स्टाफ का सेपरेशन होना चाहिये। टेक्निकल आदमियों से आफिस का काम लिया जाता है तो वे हिसाब लगाते लगाते क्लर्क रह जाते हैं। मैं यह उचित समझता हूं कि इंजीनियरों से बिलकुल टेक्निकल काम लिया जाय। उन्होंने बड़ी बड़ी टेक्निकल की डिग्रियां लीं, लेकिन आप उनसे क्लर्क का काम लेते हैं तो कुछ मुनासिब नहीं मालूम होता है।

श्री अधिष्ठाता---आपका समय समाप्त हो गया।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---अधिष्ठाता महोदय, मैं कल से सार्वजनिक निर्माण विभाग के काम के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों के विचार सुनता रहा और मुझे ऐसा लगा कि सार्वजनिक निर्माण के कार्यों के बारे में जान बूझकर कोई टिप्पणी की जाती है या ऐसा है कि उसके बारे में उनको ज्ञान नहीं है...

श्री अधिष्ठाता---आप ऐसा न कहें जिससे माननीय सदस्यों के ऊपर रिफलेक्शन होता हो कि उनको ज्ञान नहीं है।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी---मैंने तो जान बूझकर कहा है। मैं समझता हूं कि बहुत लोगों को ज्ञान होता है, लेकिन वे छिपाकर रखते हैं। जो यहां पर सूची बंटी है उसमें लिखा हुआ है कि "मानव जाति के साथ ही सड़कों का भी विकास होता है और समाज व्यवस्था के ह्रास के साथ ही इसका भी ह्रास होता है। बिना सड़कों के मनुष्य का बहिर्जगत से और फलतः सभ्यता से सम्बन्ध विच्छेद हो जाता है। अतएव सड़कों के निर्माता

[श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी]

मनुष्य से सभ्यता के निर्माता मनुष्य को अलग नहीं किया जा सकता।" यह एक सर्वविदित वाक्य है कि ज्यों ज्यों हम विकास की ओर बढ़ते हैं त्यों त्यों हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं। आज हम एक विज्ञान के युग में चल रहे हैं। आज मनुष्य हवाई जहाज पर चढ़ना चाहता है। तुरन्त ही वह अपना काम करना चाहता है। विधान सभा की घंटी बजती है तो हम यह सोचते हैं कि तुरन्त ही वहां पर पहुंच जायं। जैसे जैसे हम तरक्की करेंगे वैसे वैसे हमारा समाज विज्ञान की तरफ बढ़ेगा। आज हम १०० वर्ष पुरानी बैलगाड़ी को इस्तेमाल करना नहीं चाहते हैं। जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे ही वैज्ञानिक साधनों का उपयोग करने की सोची जाती है। पुराने तरीकों को हम इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। यही हमारी प्रगति का द्योतक है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तैसे तैसे हमारी आवश्यकता बढ़ेगी। मैं समझता हूं कि इस तरह के कटौती के सुझाव छोटे स्तर के हैं और उनका कोई महत्व नहीं है। श्रीमन्, हमें देखना चाहिये कि जो धन है उसका सदुपयोग हुआ है या नहीं। इस ओर माननीय सदस्यों का ध्यान जाना चाहिये क्योंकि हमारी सीमा और बजट निर्धारित है। इसलिये जो टीका टिप्पणी हुई उसका कोई महत्व नहीं है और मैं समझता हूं कि जानबूझ कर ऐसी बात कही जाती है। मैं किसी पर आपत्ति नहीं करता, न किसी पर शंका करता हूं, किसी की बुद्धि पर शंका नहीं करता, लेकिन सत्य को एक ऐसे ढंग से रखा जाता है कि उस पर परदा पड़ जाता है।

बजट के सम्बन्ध में मेरे दो एक और निवेदन हैं। इस पुस्तिका में कुछ आंकड़े दिये हुए हैं विभिन्न देशों की सड़कों की तालिका के हेडिंग में। इसमें दिया है कि भारतवर्ष में प्रति १०० मील पर २४.९ मील पक्की सड़क है, इंग्लैंड में ३२४.२ मील है, फ्रान्स में ३०३.५ मील है, बेलजियम में २३२.८ मील है, पश्चिमी जर्मनी में १५९.४ मील है। श्रीमन्, यहां मेज की पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस का जिक्र किया जाता है, लेकिन जब हम विकास की बात करते हैं तो उसका बाहरी देशों से मुकाबला करने पर पाते हैं कि वह बहुत कम है। विकास का काफी काम बाकी है और अगर हम सड़कों को विकसित नहीं कर पायेंगे तो गांव की बात करने का अर्थ क्या? शहरों में सभी को सुविधा है, लेकिन गांव वालों के लिये सड़क नहीं बन सकती। दारुलशफा आदि की जो बात कही गयी उससे वस्तुस्थिति का पूरा ज्ञान नहीं होता। इस चार्ट से स्पष्ट है कि कितना कम काम हो गया है और इसलिये हमें क्रमशः इस विभाग के कामों को प्रोत्साहन देना चाहिये और इसके लिये ज्यादा रुपया मांगना चाहिये ताकि और अधिक प्रगति हो सके।

दूसरे, इसमें उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता के उपरांत बनी सड़कों की प्रगति के लिये एक नकशा बना हुआ है। अंग्रेजी शासन काल में जो मिलिटरी के अड्डे थे अथवा जहां शासन की दृष्टि से आवश्यक था वहीं सड़कें बनायी गयी थीं। ऐसे जिले भी हैं कि जहां इस प्रकार के विकास का काम बहुत कम हुआ है। लेकिन उस के बाद इन १० सालों में जो विकास का काम हुआ है वह भी बहुत थोड़ा है क्योंकि हमारे पास साधन कम हैं। आगरा में प्रिइंडिपेंडेंस में प्रति-शत सड़कें २५५ थीं जो ३१६ हुई हैं, गोरखपुर में १६० मील थी जो २७० मील हुई है १० सालों में। और देवरिया जो मेरा जिला है, में पहले १०८ मील थी और अब २६९ हुई है.....

श्री अधिष्ठाता--बहुत ज्यादा सड़क बनी है वहां पर।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी--यही मैं कह रहा था। १० वर्षों में करीब दूना पड़ता है यानी १४ मील फी साल हमारे यहां सड़क बनी है। तो वह क्षेत्र जो अवि-कसित माना जाता है वहां १४ मील प्रतिवर्ष के हिसाब से सड़क बनी है। वह बहुत कम बनी है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि भटनी में एक चीनी मिल बनी है। वहां से आपको लाखों रुपया सेस से मिलता है, लेकिन अभी तक ५ मील की सड़क तुलसी वाड़ा से भटनी तक नहीं बन पायी है और बार बार लेने के बाद भी नहीं बन पायी है तो प्रार्थना है कि उसको भी इस योजना में चलाइये। इस के अतिरिक्त लाहिलपार से सोनघाट

तक की ३ मील सड़क है । इस समय इसके न होने से लोगों को यातायात की असुविधा होती है और इसलिये इसको बनवाना आवश्यक है । एक पुल के बारे में प्लानिंग कमेटी ने देवरिया से सिफारिश भेजी थी छोटी गंडक पर वरियारपुर पर, वह क्षेत्र बिहार की सीमा से दो मील दूर है । उस पर तीन लाख का पुल अंतरिम परिषद् से स्वीकार होकर आया वह क्यों नहीं लिया जा रहा है ? छपरा से सड़क बनाई गई है तो क्या देवरिया से ५–७ मील और सड़क नहीं बन सकती ? आज बड़ी दिक्कत हो रही है अगर कोई बैलों की चोरी या डकैती हो जाय तो वहां पुलिस पहुंच नहीं पाती है । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि ये दो सड़कें और एक पुल जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं इनको बनाया जाना चाहिये ।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं और वह यह कि निर्माण विभाग का जो काम होता है उसमें जनप्रतिनिधियों का सहयोग नहीं लिया जाता है । मैं चाहता हूं कि स्थानीय स्तर पर, जो एक दो लाख रुपये से ऊपर के काम हों उनके लिये एक समिति होनी चाहिये जो यह देखे कि वस्तुओं का ठीक ठीक उपयोग हो और काम अच्छी तरह से हो । वह समिति इंजीनियरों को सलाह दे सकेगी और उससे काम में उत्तमता आयेगी । इसका एक कारण यह भी है कि चूंकि अधिकारी वहां काम पर पहुंच नहीं पाते हैं इसलिये यह सम्भावना हो सकती है कि ओवरसियर वगैरह ठेकेदारों से मिलकर कुछ गड़बड़ी भी कर लें । इसलिये मेरा यह सुझाव है कि स्थानीय समिति होने से काम ज्यादा हो सकेगा और उसमें गड़बड़ी होने की गुंजायश नहीं रहेगी। इस डिपार्टमेंट में एक आध काम ऐसे हुये हैं जिनसे भ्रान्त भावनायें पैदा हुई हैं इसलिये यह आवश्यक है कि नान-आफिशियल एजेन्सी से अगर सहायता मिल सके तो उनका सहयोग अवश्य लिया जाय ताकि जहां थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो सकती है ठेकेदारों से मिलकर---इससे प्रशासन का सम्बन्ध नहीं है---लेकिन छोटे कर्मचारी जैसे ओवरसियर वगैरह वह ज्यादा पैसे के काम में सीमेन्ट कम लगाकर या किसी और प्रकार से जो गड़बड़ी कर सकते हैं वह न होने पाये । इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं ।

*श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव पेश हुआ है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं । जैसा कि अभी माननीय गोविन्द सिंह जी ने कहा मैं उसकी सफाई दे देना चाहता हूं । उन्होंने कहा कि पहाड़ की सीमा पर चीन के जो लोग हैं वह हमारे दुश्मन हैं और चढ़े आ रहे हैं । मैं उनसे कहना चाहता हूं कि चीन से हमारी दोस्ती है और उनका यह कहना हमारी विदेशी नीति के बिलकुल खिलाफ है । हमारे देश की और चीन की बहुत बड़ी दोस्ती है । न कोई हमारे ऊपर चढ़ रहा है और न कोई हमारा दुश्मन है, हमारे सब दोस्त हैं और दुनिया में सबके साथ हम दोस्ती का व्यवहार करना चाहते हैं ।

इसके बाद जगदीशप्रसाद जी ने कहा कि हमारी सरकार का ध्यान देहातों की रतफ न होकर शहरों में आलीशान बिल्डिंग्ज की तरफ है । इस सम्बन्ध में मैं मंत्री जी का ध्यान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो कहा था उसकी तरफ दिलाना चाहता हूं । उन्होंने कहा था कि हमारा ध्यान ज्यादातर सड़कों की तरफ होना चाहिये क्योंकि ज्यादातर जनता देहातों में ब सती है । बच्चों के सम्बन्ध में भाषण देते हुये पंडित जी ने कहा था कि बच्चों को पेड़ों के नीचे पढ़ाया जाय, बिल्डिगों की कोई जरूरत नहीं है । लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू, जोकि हमारे नेता हैं, हमारे प्रधान मंत्री हैं उनकी बातों का यह सरकार अनुकरण नहीं करती है। यद्यपि इस पुस्तिका में मंत्री जी ने एक जगह ऐसा लिखा है "हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि हमें सड़कों को उच्चतम प्राथमिकता देनी चाहिये" । लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में वे क्या कर रहे हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता---शायद माननीय सदस्य को मालूम नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही रुपया काट दिया है ।

श्री ऊदल---तो पंडितजी से उन्हें कहना चाहिये कि हमें देहात की सड़कों और पुलों के लिये रुपया चाहिये । अभी ५, ७ महीने पहले पंडित जी ने कहा था कि मेरा मकान बहुत बड़ा है और मेरा खयाल है कि छोटे मकान का नक्शा बन गया है और वह बनने भी जा रहा है । इसलिये सरकार को चाहिये कि आलीशान इमारतों से हटकर देहात की ओर जावें ।

मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि देहात की जनता के कल्याण के लिये कालिकाधाम में वरूणा नदी पर और नाद नदी में रौना स्थान पर अवश्य पुल बनवाने की कृपा करें । श्रीमन्, आपके क्षेत्र में मुड़बा नदी में कांवर पर भी पुल की बहुत आवश्यकता है । बहुत से लोग इन जगहों में हर साल बह जाते हैं, लेकिन कौन सुनने वाला है ? इसी प्रकार हमीरपुर में बेतवा और जमुना पर भी पुल की आवश्यकता है । वहां लाखों रुपया सरकार को ठेकों से मिलता है । त्रिपाठी जी ने भी कहा कि इन सब चीजों की जरूरत है ।

(इस समय २ बजकर १२ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री नेकराम शर्मा पीठासीन हुये ।)

श्रीमन्, एक मकान का चित्र इस पुस्तिका में दिया हुआ है जिसका नाम लिखा है "राजकीय संग्रहालय" लखनऊ । अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने एम० पी० लोगों के सम्मेलन में कहा था कि हमारे लिये सेंटर से रुपया लेने की कोशिश करें क्योंकि वह हमको उपेक्षा की दृष्टि से देखती है । मैं भी एम० पीज० के साथ इस इमारत में गया, वे लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे कि इतना रुपया इस पर बरबाद करने की क्या जरूरत थी । भले ही ये चीजें अच्छी हों, लेकिन आज इनके बजाय पुलों और सड़कों की जरूरत अधिक है । जैसा जगदीशप्रसाद जी ने कहा, कहीं ५, ६ पंचवर्षीय योजनायें पूरी होने पर ऐसे भवनों की आवश्यकता हो सकती है । दर्शक गैलरी में बहुत लोग बैठे हैं, वे सोचते हैं कि ये लोग आरामतलब होगये हैं और देहात में भी लोग यही कहते हैं । इसलिये मैं चाहता हूं कि जनता के पैसे का दुरुपयोग न होकर सदुपयोग हो ।

अभी मंत्री जी नें अपने भाषण में बड़ी लम्बी चौड़ी बातें कहीं कि विभाग बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे अच्छे काम उसने किये हैं । मैं उनका ध्यान लेखा रिपोर्ट, पहला भाग, सन् ५८ की ओर दिलाऊंगा जिसमें लिखा है कि ९ करोड़ ७३ लाख रुपये का पता ही नहीं है, जिसका हिसाब इस विभाग ने नहीं दिया । उसका क्या हुआ ? यह सरकारी रिपोर्ट है ।

मैंने कल भी कहा था कि मंत्री जी कमजोर हैं, अपने विभाग पर और कैबिनेट में लड़ने में भी । इसलिये वह चाहते हुये भी जनता की आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाते हैं । उनकी और मेरी दोनों की लाचारी है ।

इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि मंत्री जी सड़कों और पुलों की ओर अधिक ध्यान देने की कोशिश करें और रुपय के लिये लड़ें ।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत मांग का हृदय से समर्थन और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

हमारे देश में सड़कों की निर्माण योजना की भी उतनी आवश्यकता है जितनी और वस्तुओं की है । यातायात के साधनों की अधिक जरूरत वहां है जहां गांवों को एक दूसरे से सामान पहुंचाने के लिये और देहाती क्षेत्रों की पैदावार शहरों में लाने के लिये सड़क नहीं है । इसलिये व्यापार और सर्वसाधारण के आने जाने के नाते से आवश्यक है कि देहात में अधिक सड़कें बनें ।

यह कहा गया कि बड़े बड़े भवन बन रहे हैं । आवश्यकता तो देश में ऐसे भवनों की भी है जहां हम लोग जिलों से आकर बैठते हैं । उसके ऊपर टिप्पणी हुई कि उन पर अधिक धन खर्च किया जा रहा है । मेरा निवेदन है कि दूसरे विभागों से अलग-अलग योजनायें इस विभाग

में आती हैं भवनों के निर्माण की, और उनको यह विभाग बनाता है। एक तो ये सामूहिक योजनायें होती हैं जिन्हें यह विभाग बनाता है और दूसरे जैसे हमारे अन्तरिम जिला परिषद् हैं, जिनमें जिला बोर्डों के कार्य आ गये हैं, वे सारे इस विभाग को बनाने के लिये देते हैं और कोशिश करते हैं कि इस विभाग द्वारा वह कार्य हो। तो यह मानना ही होगा कि इस विभाग में काम करने की क्षमता है तभी उसे ये कार्य सौंपे जा रहे हैं। इस विभाग में कुछ कमियां होने पर भी कुछ कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है। श्रमदान की सड़कों पर भी कार्य होने की जरूरत है। प्रदेश की योजनाओं में केंद्र भी कुछ धन देता है। जब केंद्र से रुपये की मंजूरी में देर हो जाती है या मंजूर नहीं हो पाता है तो प्रदेश की योजनायें अधूरी रह जाती हैं और शिकायत होने लगती है कि सड़कों पर आम तौर से सामान पड़ा बरबाद हो रहा है। तो यह कारण भी हो जाता है। तो जहां इस कार्य से कुछ आशा होने की गुंजाइश है वहां उसकी कुछ कठिनाइयां भी जरूर हमारे सामने आ सकती हैं, उस पर भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है। हां, कुछ ऐसे काम भी इस विभाग द्वारा जरूर हो जाते हैं जिनकी वजह से विभाग की कुछ बदनामी हो जाती है इसलिये ओवरसियरों द्वारा जो काम होते हैं उनकी तरफ काफी ध्यान दिया जाय। श्रीमन्, जो मिट्टी के कार्य हैं वे सहकारी संस्थाओं को दिये जायं जो कि लेबर का काम करती हैं। अगर उन सहकारी संस्थाओं के द्वारा काम कराया जायगा तो हमारे प्रदेश की बेरोजगारी दूर होगी तथा लोगों को कुछ काम मिल जायगा, लेकिन ऐसी संस्थाओं को काम न दिया जाय जो उसे अपना खानदानी काम बना लें और जिस तरह से ठेकेदारों को ठेका दिया जाता है उसी तरह से वे भी ठेका लेने लगें। कोशिश हमारी यह होनी चाहिये कि ऐसी सहकारी संस्थायें जो लेबर का कार्य कर सकें उनको इस काम के लिये प्रोत्साहन दिया जाय।

इसके अलावा माननीय मंत्री जी का ध्यान मुजफ्फरनगर के एक पिछड़े हुये इलाके की तरफ दिलाना चाहता हूं जहां पर पुरकाजी से लक्सर को सड़क बन रही है लेकिन खानपुर खादर और गोरधनपुर के बीच का हिस्सा जो करीब ६ मील का पड़ता है वह रह जायगा। इस पर तीन चार पुलों का होना भी बहुत आवश्यक है। अगर वे पुल नहीं बनेंगे तो फिर यह सड़क अधूरी रह जायगी। इसलिये इस तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान जरूर जाना चाहिये। अगर इसके ऊपर पुल बन जायं और वह हिस्सा पूरा हो जाय द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्दर तो वह सड़क हरिद्वार सहारनपुर तक मिल जायगी। यही नहीं, बल्कि देहली तक का सीधा रास्ता हो जायगा और यातायात के साधन होने पर व्यापार की दृष्टि से भी यह काम हो जायगा तो जनता को भी बड़ी आसानी होगी। वहां रास्ता न होने की वजह से ही कोई अस्पताल भी नहीं है। उस इलाके की तरफ की पी०डबल्यू० डी० की बड़ी २ सड़कें मुतवातिर तीन साल तक बाढ़ आने की वजह से खराब हो गयी हैं। उस तरफ भी ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है जो सड़कें पानी से कट गयी हैं। खतौली की जो सड़क है उस तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। खतौली मिल का पानी पास की सड़क पर भरा है। खतौली मिल से चूंकि वहां की सड़क बहुत नीची है, उसे बहुत नुक्सान पहुंचता है जिससे वहां की जनता को आने जाने में बड़ी भारी दिक्कत होती है। सरकार को चाहिये कि उस सड़क को नुकसान होने से बचावे। मुजफ्फरनगर जिले की और भी सड़कें ह जिनकी तरफ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं लेकिन इस वक्त उन छोटी छोटी बातों का जिक्र करना मैं उचित नहीं समझता हूं।

इस विभाग में करप्शन की भी बड़ी शिकायत है। मुझे खुशी है कि इस विभाग ने बड़ी कोशिश की कि करप्शन में कमी हो और वह काफी हद तक कम हुई। इस बात की कोशिश की गयी कि सहकारी श्रम उद्योग के जरिये कार्य हो और

[श्री रामदास आर्य]

ठेकेदारी को खत्म करने की चेष्टा की जाय। कुछ भाइयों ने यह सुझाव दिया कि यह बात बहुत आवश्यक है कि इसमें ईमानदारी से कार्य होना चाहिये और इसमें दूसरों से सहयोग मिलना बहुत आवश्यक है। मैं भी चाहता हूं कि इस कार्य को प्रोत्साहन दिया जाय और प्रदेश में पुल के कार्य को सर्वप्रथम स्थान दिया जाय। ऐसे तो आजकल देश में अन्नोत्पादन की तरफ ही ध्यान देने की विशेष जरूरत है और उस पर अधिक खर्च होना चाहिये, लेकिन जहां तक इस विभाग का संबंध है, इसमें रुपया बहुत कम रखा गया है। आइन्दा केंद्रीय सरकार का ध्यान भी हमारा यह सदन जरूर दिलायेगा कि इस विभाग के लिये और ज्यादा रुपया रखा जाय। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी की इस मांग का समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता---माननीय टीकाराम जी पुजारी, आपको ५ मिनट का समय मिलेगा, ५ मिनट ही आपने मांगे हैं।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---अधिष्ठाता महोदय, निर्माण पर ५ मिनट काफी होते हैं, नया निर्माण होगा। नया निर्माण तब हो सकता है जब नीचे से ऊपर तक नया निर्माण हो, सड़कों का भी नया निर्माण होगा, महलों का भी नया निर्माण होगा, सरकार का भी निर्माण होगा तभी नया निर्माण होगा। सबका ही नया निर्माण होगा लेकिन इस तरह से नया निर्माण नहीं होगा। वह दूसरा तरीका है। सब नौजवानों, माताओं और बहिनों को इसमें कुछ त्याग करना होगा। जापान को देखें, जर्मनी को देखें युद्ध में उनकी कैसी हालत हो गयी थी वहां की माताओं, बहिनों व नौजवानों ने तथा विद्यार्थियों ने वह निर्माण करके दिखलाया कि आज वे मुल्क दिन प्रति दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। उनके अन्दर देश से प्रेम है। जब देश से प्रेम होगा तब हमारा भी नया निर्माण हो सकेगा। भारत माता आवाज दे रही है कि देश के नौजवानो, आओ और निर्माण करो ताकि यह देश ऊंचा उठ सके। इस तरह से निर्माण होता है।

निर्माण होता क्या है? हम लोग विरोधी दल के हैं। टीकाटिप्पणी करते हैं। कोई कहता है कि इन गद्दियों पर बैठना चाहते हैं। तो हम तो गद्दियों पर बैठे हुए ही हैं। उधर भी गद्दियों पर बैठे हुये हैं और इधर भी गद्दियों पर बैठे हुए हैं। एक चीज जरूर है कि उधर गद्दी बड़ी है। उधर के नेता भी आगे बैठे हैं और इधर के नेता भी आगे बैठे हैं। उधर भी लोग पीछे बैठे हैं और इधर भी लोग पीछे बैठे हैं। इस सदन में दो बिरादरियां हैं। एक बड़ों की एक छोटों की। पहले उनका ही निर्माण कर दिया जाय। कटौती का प्रस्ताव लाया जाता है कि १ रुपये की कमी कर दी जायगी। बोलने की आदत है चाहे कोई भी विषय हो चाहे कुछ जाने या न जाने, लेकिन बोलेंगे जरूर। अंग्रेजी की टाँग तोड़ देंगे। चार बातें अंग्रेजी में कही और ३ बातें हिन्दी में कही। हिन्दी वाले को कोई पूछता नहीं है। पहले अपना तो निर्माण कर लो, मुल्क का निर्माण तो बाद में होगा।

इसलिये पहले नीचे से ले कर ऊपर तक निर्माण करो। २०० रुपया आप लेते हैं, २०० रुपया हम लेते हैं। १० रुपये रोज आप लेते हैं और १० रुपया रोज हम लेते हैं। फर्स्ट क्लास का भत्ता लेते हैं। १०० रुपया तनख्वाह लीजिये, ३५ रुपया महंगाई लीजिये, थर्ड क्लास का किराया लीजिये, ५ रुपया भत्ता लीजिये तब हम त्यागी कहलायेंगे, तब निर्माण होगा, यह प्रस्ताव कल मैं रखूंगा। विरोधी पक्ष के इतने सदस्य हैं अगर वे पहले ऐसा करें तब उनका मुंह होगा सत्ताधारियों से त्याग करने के लिये कहने का। यह नहीं कि कड़ुवा कड़ुवा तेरा और मीठा मीठा मेरा। इस तरह से काम कभी चलेगा नहीं और न निर्माण हो सकेगा। पहले हमें अपना निर्माण करना होगा तभी देश का निर्माण होगा।

श्री शिवराजबलीसिंह (जिला फतेहपुर)---अधिष्ठाता महोदय, जो अनुदान मंत्री जी ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। सार्वजनिक निर्माण विभाग के जितने भी कार्य हैं मैं समझता हूं कि सभी महत्वपूर्ण हैं। परन्तु मेरा विचार है कि सड़कों का विषय उन सभी कार्यों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताऊं मेरा जिला फतेहपुर छोटा जिला है जो

इलाहाबाद और कानपुर के बीच में है। उसकी हालत वही है जो कि चक्की के बीच में दाने की होती है, वह बराबर पिसता रहता है। बजट हमेशा आता है, यह मेरा आठवां बजट है। बजट के विषय में और इस बीच में मैं ८ साल बाद आज बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं, क्योंकि फतेहपुर जिले में आज से नहीं सालों से एक इंच भी नई सड़क नहीं ली गई है। बल्कि इस समय हमारे यहां एक बाई पास बन रहा है जिस पर १,००,००० रु० से ऊपर रुपया खर्च किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि बनना चाहिये, लेकिन देखना तो यह है कि आखिरकार जरूरत किन सड़कों की पहले है। फतेहपुर जिले में बिन्दकी एक कस्बा है, जो तहसील भी बन चुका है, शायद हापुड़ के बाद बिन्दकी ही गल्ले की बड़ी मंडी है और उसमें बांदा और हमीरपुर तथा उन्नाव और रायबरेली तक का गल्ला आता है। तो यदि सरकार गंगा और जमुना के बीच में, जमुना के बीच में चिल्ला घाट और ललौली है अगर एक पुल बन जाता तो बांदा का सब गल्ला आसानी से आ सकता है। आता तो अब भी है, लेकिन बड़ी कठिनाई के साथ आता है और गंगा के किनारे भिटौरा, बक्सर, इन दोनों जगह पुल बन जाता तो उससे उन्नाव और रायबरली का संबंध हमारे जिले से बहुत हो सकता है।

(इस समय २ बजकर ३० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुये।)

उधर तो एक इंच सड़क नहीं ली गई। पिछली बार ऐसा हुआ प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुछ सड़कें ली गईं, लेकिन कोई नहीं बनी। इस तरह से सड़कें ले कर यदि छोड़ दी जायं, संभव है कि कुछ कारण हों, हो सकता है जहां वे सड़कें ली गई थीं वहां बीच में एक नदी है इसलिये उस पर पुल भी बनना आवश्यक था जिसमें और ज्यादा रुपया लगता, इसलिये छोड़ दी गई हों। मैं जानना चाहता हूं कि आखिरकार जो नदी के उस पार हैं, जो बरसात में ४ महीने कुछ गांव ऐसे हैं, जिनका संबंध टूट जाता है जिले से, अगर कोई बीमार हो जाय या जिनको कचेहरी का काम है वे ४ महीने किसी तरह नहीं आ सकते। इसलिये वहां सड़क अवश्य बननी चाहिये। जिला फतेहपुर गंगा और जमुना के बीच है, तो गंगा और जमुना के गांव, गांव की आबादी, और पानी के बहाव से जिस प्रकार वहां के रास्ते, गलियां बिगड़ जाती हैं वहां अगर कोई सामान लाना ले जाना हो, चाहे, किसान की ओर से गल्ले की ज्यादा उपज हो जाय तो भी मार्गों की समुचित व्यवस्था न होने के कारण बनिये उनका गल्ला सदा कम भाव पर लेते हैं। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि आपको चाहिये यानी, मंत्री जी को चाहिये, सरकार को चाहिये कि जब बजट बनायें तो सूबे के जितने जिले हैं उनको सामने रखकर, उनका भी हिस्सा लगाकर वहां पर कुछ न कुछ काम होना चाहिये। फतेहपुर जिला टैक्स न देता हो या मालगुजारी न देता हो, ऐसी कोई बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि वहां पर एक इंच भी सड़क नहीं बनी है। हुसेनगंज से लगाकर हदगांव तक एक कच्ची सड़क ऐसी है जिसमें आठ महीने प्राइवेट लारियां चलती हैं और चार महीने बरसात की वजह से वह बन्द हो जाती हैं। उसका यातायात बहुत महत्वपूर्ण है। फतेहपुर कचेहरी के काम को या और दूसरे कामों को जाना मुश्किल हो जाता है। इलाहाबाद के जिले से लेकर सरहद तक सड़क बनाई गई है। चार मील सड़क फतेहपुर में ली गई है, यह मैंने सुना है। लेकिन वह कहां पर और कैसे ली गई है? जिस इलाके में सड़क ली गई है वह हमारे प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का इलाका है। मैं समझता हूं कि संभव है कि उनके नाम से ही वह सड़क ली गई है। यह बात तो अच्छी है, लेकिन दूसरी जगहों का भी खयाल रखना चाहिए और दूसरे प्रतिनिधि भी हैं, उन्हें भी जनता के सामने जाना है। तो एक सड़क हुसेनगंज से हदगांव और दूसरी जुनिहा शाहबाजपुर फतेहपुर १२ मील का टुकड़ा है, इसे भी यदि ले लिया जाता तो बहुत अच्छा था।

श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)---उपाध्यक्ष महोदय, यह जो विरोधी दल की तरफ से कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, कटौती के प्रस्ताव के समर्थन की कम से कम मुझमें आदत नहीं है और न कटौती करने से कोई विरोधी दल की मंशा ही हल होती है किन्तु यह आवश्यक है कि उस कटौती के प्रस्ताव के द्वारा सरकार का ध्यान कुछ आवश्यकताओं की ओर, कुछ उनकी कमियों की ओर दिलाया जाय। मैं भी इसी प्रयोजन से इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये मजबूर हुआ हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, सम्पूर्ण अनुदान की राशि को देखने के बाद यह मालूम होता है कि इस कल्याणकारी सरकार के बजट में सबसे कम सार्वजनिक निर्माण की ओर खर्च किया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, यह भी बजट को पूरा पढ़ने से मालूम होता है कि बजट के कम से कम ५/६ हिस्सा का देहात की जनता के सिर पर भार पड़ता है, किन्तु इतना बड़ा हिस्सा होते हुये भी ऐसे कार्यों पर जिससे ग्रामीण जनता को लाभ हो, बहुत कम खर्च किया जाता है। यह बजट ऐसा मालूम पड़ता है जैसे कि ब्रिटिश जमाने में केवल जो उत्पादक कार्य हुआ करते थे उन्हीं पर सरकार ज्यादा ध्यान देती थी। वास्तव में, कम से कम सार्वजनिक निर्माण विभाग की तो ऐसी मंशा नहीं होनी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, यह भी बड़े खेद की बात है कि जहां ग्रामीण जनता के ऊपर इस बजट का इतना भार है उस जनता के प्रति जो किये गये निर्माण कार्य हैं उनसे जो लाभ होता है, उस पर भी तकाजा है। उस पर भी उसे टैक्स देना पड़े, मिसाल के तौर पर टोलटैक्स है वह भी उन पर पड़ता है, जो रिक्शा वाले हैं या जो साइकिल वाले हैं, मेरे दोस्त प्रतापसिंह जी कह रहे हैं कि वह बैलगाड़ी तक पर पड़ता है। चाहे कोई अपनी बहू को रुखसत कराने जाता हो या नदी के पार गल्ला खाने के लिये लेने गया हो, एक बार किसी काम से भी कोई पुल पार करे तो टोल टैक्स देना होगा। अगर कोई अनाज वगैरह लाभ की दृष्टि से ले जाय तब तो ठीक ही है टैक्स लिया जा सकता है, लेकिन यह जो सरकार की नीति है कि डायरेक्ट टैक्स न लगाया जाय और इंडायरेक्ट टैक्स लगाया जाय यह पालिसी सरकार को उचित नहीं है। हमारे पूरे बजट की ही न केवल सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट की पालिसी एक प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पालिसी होनी चाहिये, लेकिन हमारे यहां अभी तक पी० डब्ल्यू०डी० का बजट रिग्रेसिव टैक्सेशन पालिसी पर आधारित है। यह बड़े दुख की बात है। सरकार यह न समझती होगी कि अब जनता बेपढ़ी लिखी है और वह कुछ समझती नहीं होगी लेकिन वह अब बुद्धू नहीं है, वह कलम से भले ही न लिख सकती हो, लेकिन वह सरकार के कारनामों को समझती है और वह जो विकास आदि के काम होते हैं उन्हीं के नुक्तेनजर से चलती है और उस सबका फल एलेक्शन के वक्त मालूम हो जाता है। यह मैं केवल मौजूदा सरकार के विषय में ही नहीं कहता, बल्कि जो भी सरकार आयेगी उस के बारे में जनता इसी प्रकार जज करेगी। इस वास्ते पी०डब्ल्यू० डी० में रिग्रेसिव टेक्सेशन पालिसी न अख्तियार की जाय और उसको अविलम्ब छोड़ दिया जाय।

समय बहुत कम है और किस्सा है तूलानी, इसलिये मैं सरकार का ध्यान एक तरफ और दिलाऊंगा। जहां तक सड़कों के निर्माण की बात है, मैंने सरकार के द्वारा छापी गई २ साल की पुस्तकें देखीं। उनसे ऐसा मालूम होता है कि जो सड़कें ली गई हैं वह इस नुक्तेनिगाह से ली गई हैं कि जिन से सरकार को कुछ लाभ होता है वह रखी गई हैं और जिनसे लाभ नहीं होता उनको नहीं लिया जाता। सीधा सम्बन्ध नहीं होता तो टेढा ही होता है मसलन अगर रोडवेज विभाग की बसों को कहीं चलाना है तो वह सड़क ली गई है भले ही उसके बनने से जनता को या वहां के सामाजिक जीवन को कोई लाभ न होता हो, वहां का विकास या उद्योग न बढ़ता हो। यह पालिसी बड़ी खतरनाक पालिसी है, होना यह चाहिये कि अगर रोडवेज को लाभ है तो वह पैसा लगावे, परन्तु यह ठीक नहीं है कि रोडवेज के लाभ के लिये पी० डब्ल्यू० डी० अपना पैसा लगावे।

मैं आपका ध्यान लखनऊ जिले की तहसील मोहनलाल गंज की एक १८ मील की सड़क गंगागंज नगराम निगोंहा रोड की तरफ दिलाना चाहता हूं। इस सड़क का

बनना बहुत जरूरी है और इस सम्बन्ध में दरख्वास्तें भी ४,५०० दस्तखत करा के दी गई, इसकी सिफारिश जिला प्लानिंग कमेटी ने की और अन्तरिम जिला परिषद् ने भी इसके लिये प्रस्ताव पास किया, लेकिन इस सड़क को नहीं लिया गया और यू० पी० रोड डेवलपमेंट बोर्ड ने इस सड़क को यह कह कर निकाल दिया कि सारे सूबे में लखनऊ जिले का सड़कों का क्षेत्र सबसे अधिक है, इतना और कहीं नहीं है। जब मैंने सवाल किया तो उस का जवाब मेरे पास है और जब अन्तरिम जिला परिषद् से प्रस्ताव सरकार के पास भिजवाया गया तो कहा गया कि पैसे की कमी के कारण वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नहीं आ सकती। तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस पर विचार किया जा सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह स्पष्टीकरण चाहूंगा कि इन दो में से कौन सा जवाब सही था, रुपये की कमी थी या उस सड़क की आवश्यकता नहीं थी।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार से यह भी निवेदन कर दूं कि यह सड़क अगर उत्पादन की दृष्टि से सोचें तो बहुत जरूरी थी, क्योंकि इस पर सिटी बस चलायी जा सकती थी और सैकड़ों रुपये रोज की आमदनी हो सकती थी। तो अपने नुक्तेनजर से भी, जो आपने आम तौर से रखा है, यह बहुत आवश्यक है और मैं फिर आपके द्वारा स्पष्टीकरण चाहता हूं कि इस निगराम रोड को लेने के बाद क्यों निकाला गया।

मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करूंगा कि मुझे.....

श्री उपाध्यक्ष––अभी आपके २ मिनट हैं।

श्री रामशरण यादव––मुझे ४ मिनट दिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष––आजकल रिआयत बन्द है, २ मिनट ही बोलिये।

श्री रामशरण यादव––उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने थोड़े से समय में ही, जैसी की आपकी आज्ञा है कानपुर जिले की तरफ मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कानपुर की दो तहसीलों ने जिनमें एक बिल्हौर है आधा रकबा घेर रखा है और वह इटावा और बिधूना तक मिली हुई हैं। तो वहां पर बिल्हौर और रसूलाबाद सड़क अभी तक नहीं बन पायी है। इंटेरिम जिला बोर्ड ने मिट्टी डाल रखी है। गवर्नमेंट की नीति होनी चाहिए कि अगर वह पूरे देहात की सड़कें नहीं ले सकती है तो जो कम से कम कच्ची है उसको पक्की करे और पहले उसको कम्प्लीट करें। उसमें ज्यादा खर्चा नहीं होगा। वहां मकनपुर का मेला लगता है, बहुत दूर कोने में वह इलाका पड़ता है और बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार लिखा गया, लेकिन सरकार की तरफ से कहा गया कि इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नहीं ली जा सकती है। ताज्जुब तो इस बात का है कि जवाब यह मिला कि कानपुर की कोई सड़क नहीं ली जायगी और फिर भी मालूम हुआ कि ३ सड़कें मेरे जवाब के मिलने के बाद ले ली गयीं। पता नहीं, मैं तो कह सकता हूं––वैसे आक्षेप करने की मेरी नीयत नहीं है, लेकिन यह बात सही है कि वह उन क्षेत्रों में है जहां के कांग्रेसी एम० एल० एज० हैं और उस क्षेत्र में जहां जनता का ज्यादा जागरण है वहां पर आश्वासन के बाद भी वह सड़क नहीं ली गयी, तो इसको जल्द से जल्द बनवाने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष––श्री अहमद बख्श....

श्री प्रतापसिंह––मैं एक प्रस्ताव लाना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। चूंकि इस अनुदान को आज ही समाप्त होना है, मैं समझता हूं अधिक सुझाव विरोधी दल की तरफ से आते हैं तो मेरा प्रस्ताव है कि दो यहां के और एक वहां के माननीय सदस्य बोलें तो अधिक से अधिक समय विरोधी दलों को मिल सकेगा।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य का प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं है। चेयर से व्यवस्था हो चुकी है कि विरोधी दलों को टोटल समय कांग्रेस पार्टी से ज्यादा मिलेगा, तो यह व्यवस्था नहीं हो सकती है कि दो उधर के और एक इधर के बोलें, यह हो सकता है कि काफी सदस्य बोलने वाले ह, १० के बजाय ७ मिनट समय कर दिया जाय और विशेष निवेदन पर ३ मिनट बढ़ाकर समय १० मिनट दे दिया जाय, तो कुछ और लोग बोल सकेंगे। अब से जो माननीय सदस्य कायदे का भाषण देंगे और आवश्यकता होगी तो उनको ७ मिनट के बाद ३ मिनट और दे दिये जायेंगे।

श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर)—उपाध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था तो मेरे बोलने के बाद होगी? क्योंकि मेरा नाम तो आप पुकार चुके थे?

श्री उपाध्यक्ष—जी हां।

श्री अहमद बख्श—उपाध्यक्ष महोदय, अगर मैं आपका शुक्रियां अदा न करूं तो ज्यादती होगी, क्योंकि कई बार उठने के बाद आपने मुझे मौका दिया और वजीर मुताल्लिका का शुक्रिया अदा न करूं जिन्होंने यह अनुदान पेश किया है तो उनके साथ भी एक किस्म की बेइंसाफी होगी क्योंकि इसमें शक नहीं कि यह अनुदान प्रदेश की तरक्की में एक बुनियादी स्थिति रखता है। हर किस्म की बुनियादी तरक्की, चाहे तिजारत की, खेती की, दस्तकारी की वगैरह इस बुनियादी मसले के बगैर कामयाबी की हद तक नहीं पहुंच सकती। इसमें भी कोई शक नहीं कि गवर्नमेंट की जो आर्थिक हालत है वह भी ऐसी है कि अगर हम तमाम चीजों को एक वक्त बना देना चाहें तो हमारे लिये नामुमकिन चीज है। इसमें कोई शक नहीं कि इन्सान की खुदगरजी इस पर मजबूर करती है कि उसके क्षेत्र में जितने भी काम हों वे जितनी जल्दी बन जायं उतना ही अच्छा है। इसके साथ अगर यह कहा जाय तो बेजा न होगा कि जब सरकार इस बात की कोशिश करती है कि उसकी माली हालत कुछ ठीक हो, यानी टैक्स वगैरह लगाने की कोशिश करती है तो उस वक्त यह एतराज होता है कि सरकार बहुत टैक्स लगाती है। लेकिन जब यह ख्वाहिश होती है कि सड़कें और पुल बन जायं तो उस वक्त न जाने यह ख्वाहिश कहां से आ जाती है कि सब काम एक साथ हो जायं। हालांकि सरकार की यह ख्वाहिश रहती है कि जितनी जल्दी देश और प्रदेश की तरक्की हो सके उतना ही अच्छा है, लेकिन जितनी चादर होती है उतने ही पैर फैलाये जा सकते हैं। इसके बावजूद कोशिश इस बात की हो रही है और कोई शख्स इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि पिछले ९–१० सालों में हजारहा मील लम्बी सड़कें और सैकड़ों पुल बनाये जा चुके हैं। मगर जब चादर छोटी होती है तो सिर ढका जाता है तो पैर खुल जाते हैं और पैर ढके जाते हैं तो सिर खुल जाता है, लेकिन इसके साथ ही साथ मैं यह अर्ज कर दूं कि अगर थोड़ा सा एहतियात बरता जाय तो ज्यादा खूबी और उमदगी के साथ वह काम किया जा सकता है। मसलन् मैं यह किसी आलोचना के बिना पर नहीं अर्ज कर रहा हूं, बल्कि हकीकत के तौर पर अर्ज करूंगा कि अगर हम बजट बनाते वक्त या ऐसे मौके पर जबकि हमारे पास रुपया काफी होता है या जब हम कोई नयी स्कीम बनाने चलते हैं उस वक्त उस जिले के तमाम एम० एल० एज० को इस बात की दावत दें कि उनके जिले की क्या-क्या जरूरतें हैं तो जाहिर है कि वे इस बात का फैसला कर सकते हैं कि उन जरूरतों में प्रायोरिटी किस को दी जाय। मुझे यह भी यकीन है कि आज जितने एतराजात या सुझाव भेजे जाते हैं वे शायद अगले साल तक याद भी न रहें और उन पर कोई अमल भी न हो, लेकिन चूंकि एक तरीका हो गया है कि उठना और उठ कर बोलना, नहीं तो कोई यह न कहे कि फलाना मेम्बर बिल्कुल गूंगा गया, तो इस लिहाज से भी कुछ बोलने की कोशिश की जाती है और रिवाज ऐसी पड़ गयी है कि कोई सुने या न सुने मगर बोलने से मतलब। हम तो यहां पर तामीर करने आये हैं महज इसलिये नहीं कि रिवाज के तौर पर खड़े होकर बोले और उससे कोई फायदा न हो। अगर उस बोलने के मुकाबले में हम सोचने पर ज्यादा अमल करें तो ज्यादा

फायदा हो, इसलिये कि गांधी जी ने एक मर्तबा फरमाया था कि मांग छोटी हो, ताकत उसके पीछे ज्यादा हो तो वह जल्दी पूरी हो सकती है बजाय इसके कि मांग बहुत बड़ी हो लेकिन ताकत उसके पीछे कम हो। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि गवर्नमेंट साल के किसी हिस्से में एम० एल० एज० को इकट्ठा करे और उनसे जाती मालूमात हासिल करे और इसके साथ-साथ उनसे यह भी मालूम करे कि उनमें कौन से जरूरी काम हैं।

इसके साथ ही साथ इस टेक्निकल डिपार्टमेंट के नुक्ते निगाह में भी थोड़ा सा फर्क होना चाहिये। आज जितना गरीब हमारा मुल्क है उसी हिसाब से साधन भी इस्तेमाल होने चाहिये ताकि कम से कम लागत में उनका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जा सके। इस चीज की रिसर्च होनी चाहिये और यह रिसर्च वही टेक्निकल हैंड्स (Hands) कर सकते हैं जो इसमें इसकी तामील पाये हुये हैं।

इसके अलावा जो काम शुरू किया जाय वह उसी ढंग से शुरू किया जाय कि उसी एक काम को खत्म किया जाय। यह न हो कि आज काम यहां से शुरू किया और दूसरे दिन दूसरी जगह से शुरू किया और बीच में वह चीज पड़ी रह जाय। मिसाल के तौर पर मैं अपने जिले की बाबत कहता हूं कि हमारे यहां एक सड़क बन रही है और काफी दिनों से वह काम चल रहा है। इधर पुरकाजी, जिला मुजफ्फरनगर से वह सड़क शुरू हुई और उधर सहारनपुर जिले में लक्सर स्टेशन से गोर्धनपुर तक शुरू हुई, लेकिन पुरकाजी से लेकर खानपुर गोर्धनपुर के बीच में जो तीन चार मील का फासला है वह बाकी रह गया। काश कि वह एक ही तरफ से बनाया जाता और जो बाकी रह जाता वह बाद में वहां से आगे बनाया जा सकता था।

तीसरा सुझाव मुझे जनाब की मारफत यह रखना है कि आम तौर से यह भी है बाज जिलों में कि कुछ हिस्सा तो एक जिले के इंजीनियर के आधीन है और उसी जिले का बाकी हिस्सा दूसरे जिले के इंजीनियर के आधीन है। तो ऐसे मौकों पर काम बनने के बजाय बिगड़ता ज्यादा है और इसकी वजह यह है कि हमारे नुक्ते निगाह में कुछ फर्क है। हमें सोचना यह चाहिये कि हमें इस देश की खिदमत करनी है, इसका निर्माण करना है। हर वह शख्स जो मुलाजमत में है या उससे बाहर है उसे इस देश को अपना देश समझ कर ऊपर उठाने में मदद देनी चाहिये, उसके लिये कोशिश करनी चाहिये। तनख्वाह के लिये उसे यह नहीं सोचना चाहिये कि वह बहुत कम है, बल्कि यह सोचना चाहिये कि यह हमारे और हमारे बीबी बच्चों की गुजर बसर के लिये दी जा रही है और हमें देश की सेवा करना है। उन्हें यह सोचना चाहिये कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको हमसे कम तनख्वाह मिलती है। जाहिर है कि अगर मुकाबला जिन्दगी में इस बात का किया जाय कि हर शख्स हमारे ऊपर है तो टोपी उतरेगी, हमेशा नीचे देखने से फायदा होता है।

इसके बाद मुझे मंत्री जी को इस बात पर मुबारकबाद देना है और मैं उनका बहुत मशकूर हूं कि हमारे यहां यमुना के पुल का जो मामला चल रहा था वह अब तय हो गया है, लेकिन कई साल हो गये अभी यह निश्चय नहीं हो सका कि आया वह उत्तर प्रदेश की सरकार बनवायेगी या पंजाब सरकार बनवायेगी। उसके लिये इस बजट में २२ लाख रुपया भी आ गया है। वह पुल इतना जरूरी है कि वह पंजाब के सूबे को यू० पी० के सूबे से मिलाता है और वहां आलू मिर्चा वगैरह की बहुत काफी खेती होती है। तो यह पुल जल्द से जल्द बनना चाहिये।

इसके अलावा मुझे यह कहना है कि अगर हमारी यातायात की जरूरतें पूरी हो जायं तो जितनी जल्द हम चाहें किसी इलाके को मदद पहुंचा सकते हैं। आज यह यातायात का ही करम है कि एक मुल्क दूसरे मुल्क का पड़ोसी बन गया है। आप जिन्दगी की तरक्की के हर शोबे को देखिये, चाहे वह तालीम है के मुताल्लिक हो, चाहे वह तिजारत के मुताल्लिक

[श्री अहमद बख्श]

हो, चाहे वह सेहत के मुताल्लिक हो जब तक यातायात की पूरी सुविधाएं नहीं होंगी तब तक कोई चीज अपनी पूरी सफलता तक नहीं पहुंच सकती है । मिसाल के लिये मैं बताता हूं कि हमारे यहां एक सोलानी नदी का पुल है । वहां मुजफ्फरनगर जिले के गोर्धनपुर का पूरा इलाका हर साल बारिश में कट जाता है और ४–५ महीने तक वह एक जजीरे की तरह हो जाता है और कोई आमदरफ्त वहां नहीं हो पाती । ग्राम सादपुर के पुल में दरार आ गयी है और अगर वह किसी वक्त बैठ गया तो हो सकता है कि वहां आने जाने वालों का जानी और माली नुकसान भी हो जाय । इसी के साथ साथ मैं गुजारिश करूंगा कि मंसूरपुर से शाहपुर को जो सड़क जाती है उस पर पुलवालियान नदी है । उस पर अगर जल्दी से जल्दी पुल बन जाय तो जनता को बहुत आराम मिल सकता है । इसी तरह से गोर्धनपुर का इलाका है वहां पर एक धूधू नदी है अगर उस पर भी जल्दी पुल बन जाय तो लोगों को बड़ा आराम हो जाय और तिजारत का भी मौका मिल सकता है । शाहपुर एक इलाका है वहां मंडी भी बन गई है, लेकिन वह तरक्की नहीं कर रही है क्योंकि वहां यातायात के जराये नहीं हैं । अगर इसको बनाया जाय तो यह सड़क दिल्ली से मिल सकती है और तिजारत की भी काफी तरक्की हो सकती है । आखिर में मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और अनुदान का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी को मुबारकबाद देता हूं ।

श्री शिवशंकरसिंह (जिला रायबरेली)––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया । जो विरोधी दल की ओर से कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मुझे अपने जिले के संबंध में कुछ सुझाव देने हैं । हमारा जिला भी दुर्भाग्यवश एक ऐसा जिला है जो कानपुर, लखनऊ और इलाहाबाद के बीच में आता है । इसी वजह से अभी तक यहां पर बहुत कम प्रगति हुई है जैसे कि हमारे मित्र श्री शिवराजबलीसिंह जी ने अपने जिले फतेहपुर के लिये कहा है । हमने पारसाल मंत्री जी को दरख्वास्त दी थी कि रायबरेली से जो फतेहपुर सड़क जाती है उस पर गंगा में डलमऊ के पास पीपे का पुल बना दिया जाय । बांदा से फतेहपुर और रायबरेली का जो यातायात का साधन था और खासकर जो धान वगैरह आता था उसमें भी इससे सुविधा हो जायगी और साथ ही साथ लोगों को जो नाव से पार करने में कठिनाई होती है वह भी खत्म हो जायगी ।

मान्यवर, पारसाल लालगंज-रालपुर की ९ मील लम्बी सड़क को बनाने के लिये बजट में रखा गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश उस पर पारसाल काम शुरू नहीं हो सका । इस साल फिर बजट में आया है और हम उम्मीद करते हैं कि इस पर काफी काम होगा और इसके लिये हम माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं । अभी पारसाल मंत्री जी लालगंज-बेहटा-सरैनी के इलाके में गये थे और उन्होंने वहां की दुर्दशा को देखा था और हम उम्मीद करते हैं जल्दी ही लालगंज से बेहटा और सरैनी को सड़क बन जायगी और सौरैया नदी पर सरकार पुल बनाने की कृपा करेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय, हम एक सुझाव और देंगे कि अगर कोई नई सड़क बनाई जाती है तो वह पंचायत को दे दी जाय और बतौर ऐक्सपेरीमेंट के देखा जाय कि क्या परिणाम निकलता है । इससे लाभ यह होगा कि जिन पंचायतों को आमदनी नहीं है तो इस जरिये से जो पैसा ठेकेदार को जाता है वह पंचायतों को मिल जायगा ।

दूसरी बात यह कि हमारे जिले में केवल एक बिल्डिंग कही जा सकती है जो बनाई गई है वह आपका अस्पताल है । जो राजकीय स्कूल है वह १९०४ से है और तब से उसमें कोई प्रगति नहीं हुई है जब कि लड़कों की तादाद पंच गुनी हो गई है और इंटर भी खुल गया है मगर लोगों को एडमीशन नहीं मिलता है क्योंकि लड़कों को बैठने के लिये जगह ही नहीं है । इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि मंत्री जी अगर हो सके तो इधर भी खयाल करेंगे ।

*श्री रघुनाथ सहाय यादव (जिला फतेहपुर)---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय निर्माण मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान के समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं । यों तो निर्माण कार्य जैसा भी हो, जहां भी हो जनता को कुछ न कुछ उससे सुविधा ही प्रदान होती है । यह निर्माण कार्य नियोजित ढंग से करने के लिए हमारी वर्तमान सरकार ने योजनाएं बनायी हैं । इन योजनाओं पर हमारी सरकार का करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है । बड़े बड़े विशेषज्ञ अपना मस्तिष्क खर्च करके विचार करके, इस तथ्य पर पहुंचत हैं कि इस योजना के अधीन हम सभी विकसित और अविकसित क्षत्रों को समान स्तर पर लाने का प्रयास करेंगे । किन्तु उन योजनाओं के अन्तर्गत जसा कार्य चल रहा ह उससे हमको एक बड़ी निराशा की झलक आ रही है । जैसा कि हमारे माननीय मित्रों ने कहा कुछ जिलों में निर्माण कार्य दो-दो योजनाएं समाप्त हो गयी लेकिन एक भी कार्य नहीं हो सका है । फतेहपुर जिले के सम्बन्ध में मैं कह सकता हूं कि दो योजनाएं समाप्त हो गयीं लेकिन एक मील सड़क नहीं बनी है । दस साल के निर्माण काल में एक मील सड़क का निर्माण न होना और दूसरे जिलों में सैकड़ों मील सड़कों का बन जाना मैं नहीं समझता कि यह निर्माण कैसे होने वाला है और कैसे अविकसित क्षेत्रों का विकास होगा ? या तो हमारी उस योजना में ही कुछ त्रुटि है या हमारे उन अधिकारियों में जो इन योजनाओं को कार्यान्वयन कर रहे हैं उनमें कोई कमी है । यदि हम यह मान लें कि अर्थ संकोच के कारण यह हमारी योजनायें काट दी जाती हैं तो ऐसी भी बात नहीं है । यदि योजनाएं काटी जायं तो जहां पर दस दस सड़कें ली गयी हैं वहां पर काट दी जातीं लेकिन जिन जिलों में एक ही सड़क ली गयी है ४-६ मील सड़क ही ली गयी है उसको काट देना यह मैं नहीं जानता कि कौन सा औचित्य ह ।

हमारे जिले में जुनिहा से फतेहपुर तक जो सड़क है उसको पहली योजना में रखा गया था लेकिन आज तक उसमें एक मील सड़क नहीं बन पायी । वह यह कह कर काट दी गयी कि केन्द्रीय सरकार से हमारी ग्रांट कट गयी है । लेकिन दूसरी ओर जो जी० टी० और दूसरी रोड्स हैं उनके कर्व सीधे किये जा रहे हैं । उनमें लाखों रुपया पानी की तरह फेंका जा रहा है । मैं अपने जिले की बात बताऊं । वहां पर फतेहपुर और गाजीपुर के दो कर्व सीधे किये जा रहे हैं । सारी जनता प्रस्ताव करके चिल्ला रही है कि लाखों रुपया इस पर नष्ट किया जा रहा है । एक सड़क गयी है, उसके कर्व को दूसरी सड़क बना कर सीधा किया जा रहा है और कर्व सीधा भी नहीं होता, इतना ही कोण बनता है, एक दो अंश छोड़ कर, वैसा ही, उसमें भी कोण बन रहा है जो नया बाईपास बन रहा है उसमें कितने ही बाग और खेत लिये जायंगे । उनका मुआविजा दिया जायगा लेकिन फिर भी राजहठ है । उसके सामने किसी का कुछ वश नहीं । यही नहीं पैसे का दुरुपयोग इस प्रकार भी हो रहा है---उसमें रखे हुए करीब ९६ पीपे डामर के थे उसमें ६० पीपे गायब हैं । खाली वह पीपे रखे हुए हैं । अब इनके स्थान पर अन्य कोई मेटीरियल लगाया जायगा और सड़क साल दो साल के बाद फिर ज्यों की त्यों हो जायगी ।

दूसरी चीज मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश में जो योजनायें चल रही हैं, श्रमदान चल रहे हैं, और दूसरी चीजें चल रही हैं उनमें भी हमको एक निश्चित योजना बनाने की बात है । सड़कें कहीं है, श्रमदान कहीं हो रहा है, हमको चाहिए कि हम एक सुनिश्चित योजना बनायें, जनमार्ग, राजमार्ग, सबको सीधा करके एक योजना प्रस्तुत कर दें और उस पर जो भी कार्य हो वह एक सुनिश्चित योजना के अनुसार हो । तभी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रघुनाथ सहाय यादव]

हम कुछ आगे बढ़ सकेंगे अन्यथा करोड़ों रुपया इन छोटे-छोटे जनमार्गों को भी सीधा करने के लिए लगाना पड़ेगा। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री जी के अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री रघुवीर सिंह (जिला एटा)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, हमारी सरकार हमारे प्रदेश के विकास के लिए प्रयत्नशील है। हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई। दूसरी योजना के बीच में हम चल रहे हैं, परन्तु अब तक मैं यह नहीं समझ पाया कि ये योजनायें किस आधार को मान कर बनायी जाती हैं। मेरी समझ में आया है ये योजनायें उन्हीं क्षेत्रों के लिए बनायी जाती हैं जो पहले से विकसित हैं उनके लिये नहीं जो क्षेत्र बहुत पिछड़े हुए हैं और जहां पचास-पचास मील तक कोई यातायात के साधन नहीं हैं। मेरी अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार मैं यह समझ पाया हूं कि ये योजनायें उन्हीं क्षेत्रों के लिये बनायी जाती हैं जहां से या तो मन्त्रिगण आते हैं या बड़े-बड़े अधिकारी लोग आते हैं क्योंकि इस पुस्तिका से यह स्पष्ट होता है कि कुछ जिले ऐसे छांट लिये गये हैं जहां पर विकास के कार्य बड़ी तीव्रता से चलाये जा रहे हैं और कुछ जिले जो कि वास्तव में पिछड़े हुए हैं वहां पर कोई विकास या निर्माण का कार्य नहीं हो रहा है।

जैसा कि अभी उधर के बैठने वाले माननीय सदस्य तिरमल सिंह जी ने कहा था लेकिन उन्होंने एक दबी जवान से कहा कि हमारे एटा जिले में स्वतंत्रता के बाद आज तक कोई भी निर्माण का कार्य नहीं हुआ। वास्तव में यह बात ठीक है। मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि ११ साल के अरसे में एटा जिले के अन्दर कोई भी पुल या सड़क या अन्य निर्माण का कार्य क्यों नहीं कराया गया? पिछले वर्ष भी जब इस विभाग की अपने आप नजर नहीं पहुंची तो मैंने एक प्रार्थना-पत्र भी दिया कि अरिन्द नदी का पुल और वह सड़क पक्की कर दी जाय। उस पर मन्त्री महोदय ने उत्तर दिया कि धनाभाव है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसी जिले के लिए धन का अभाव है या कि दूसरे स्थानों के लिए भी। मैं तो आज देख रहा हूं कि स्टेडियम बनाये जा रहे हैं, बड़े-बड़े भवनों का निर्माण हो रहा है। बनारस जैसे स्थानों पर और दूसरे तीर्थ स्थानों पर बड़े बड़े घाट बनाये जा रहे हैं। मैं कहे बिना नहीं रह सकता कि अगर हमारे जिले से भी कोई मन्त्री महोदय आये होते या कोई बड़ा अधिकारी होता या कोई बड़ा चमकता हुआ नेता होता तो हमारे जिले का यह हाल न होता जो आज हम देख रहे हैं।

कुछ ऐसी भी योजनायें बनाई गईं कि जहां किसी कच्ची सड़क पर मिट्टी डलवा के ठीक करा दिया जावेगा उसको पहले ले लिया जायगा। उसके अनुसार मैंने निधौली-जलेसर सड़क पर कई मील तक मिट्टी डलवायी, १८ फुट चौड़ी और २,३ फुट की ऊंचाई तक मिट्टी डलवा कर श्रमदान द्वारा उसको ठीक किया। आज तीन साल हो गए कोई प्रबन्ध नहीं किया गया। कई स्थानों पर मिट्टी इतनी बह गई है कि नाले बन गये हैं। इससे स्पष्ट है कि इस जिले की तरफ सरकार का बिलकुल ध्यान नहीं है। यह मैं सिर्फ अपना जिला समझकर उसके लिए नहीं कह रहा हूं। ऐसे और भी बहुत से जिले हैं जिनकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। हमारे एटा जिले में जो कुछ थोड़ी बहुत सड़कें हैं बरसात में उन पर नाले बहते हैं। किसी किसी सड़क पर बरसात में नावों द्वारा उतराई होती है और यातायात बिल्कुल बन्द हो जाता है। रेल ज्यादा है नहीं, पक्की सड़कों की यह स्थिति है। पिछले अगस्त के महीने में जबकि हमारे जिले में पानी के प्रभाव से दुर्दशा हो रही थी, हमारे माननीय डिप्टी मिनिस्टर श्री रामस्वरूप जी यादव जलेसर तहसील के नारकीय जीवन को देखने के लिये गये। उनके साथ मैं भी गया। कहीं पैदल, कहीं कीचड़ में चलकर जलेसर तहसील तक पहुंचने के बाद हमको यातायात के न होने की वजह से उसके दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए कोई सवारी या साधन नहीं मिल

सका जिससे वहां की जनता को देख सकते और उनको आश्वासन दे सकते कि तुम्हारा कष्ट दूर करने का प्रबन्ध किया जायगा। इसलिए मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह सड़क जिसमें हमने श्रमदान के द्वारा मिट्टी डलवाई है और अरिन्द नदी पर पुल को, इस साल नहीं तो अगले साल, बनवाने की कृपा की जाय।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि आवागढ़-टुंडला सड़क जिसका स्तर बहुत नीचा हो गया है उसका स्तर ऊंचा किया जाय। जब सिरसा नदी में बाढ़ आती है तो इस सड़क पर मीलों पानी भर जाता है। दूसरी सड़क ईसन नदी पर है। इसका भी स्तर ऊंचा कराया जाय। एक बात मुझे और भी आवश्यक कहनी है कि अगर यह अरिन्द नदी का पुल और यह निधौली सड़क पक्की हो जायंगी तो हमारे तीन एन० ई० एस० ब्लाक इससे संबद्ध हो जांयगे और इन तीनों स्थानों निधौली-आवागढ़-जलेसर पर पुलिस स्टेशन भी हैं। बरसात के दिनों में अरिन्द, सिरसा और ईसन नदी जब जोर करती है तो वहां के प्रबन्ध में बड़ी दिक्कत पड़ती है। वहां चाहे कोई भूखों मरता हो या डाका पड़ता हो कोई किसी को पूंछने वाला नहीं है। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि निधौली-जलेसर सड़क पक्की कराई जाय और अरिन्द नदी का पुल बनाया जाय। एक सदस्य ने काली नदी के पुल के बारे में कहा। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह वही पुल है जो इस साल बना था या कोई और दूसरा है? श्रीमन्, मैं आपके द्वारा प्रकाश डालना चाहता हूं कि इस पुल में जो रुपया लगा है हमारे प्लानिंग में जो रुपया था वह ड्रा करके लगा दिया गया है यह पुल निर्माण विभाग द्वारा नहीं लिया गया है। क्या वह इसी पुल के लिए कह रहे थे? अगर दूसरा पुल बनाने की बात है तो मैं उचित समझता हूं कि वह पुल जो एटा से अमापुर के रास्त पर है बना दिया जाय। जलेसर और अलीगंज तहसील बहुत पिछड़ी हुई हैं वहां पर सड़कें बहुत कम हैं। यहां जनता को आने जाने में जो दिक्कत पड़ती है वह जनता ही जानती है। यहां जब गल्ले का संकट पड़ा था तो बहुत से ऐसे स्थान थे जहां पर सरकार गल्ला नहीं पहुंचा पाई। इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री बुलाकी राम (जिला हरदोई)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं जिन्होंने आज मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया। श्रीमान् जी, आज हमारा सब का ध्यान गांवों की ओर लगा हुआ है क्योंकि गांवों के उत्थान से ही हमारे देश का उत्थान सम्भव है। आज हम अपने गांवों में अस्पताल बनवा रहे हैं, स्कूल बनवा रहे हैं, बीज भण्डार बनवा रहे हैं, वेयर हाउसेज बनवा रहे हैं और विभिन्न प्रकार की कोआपरेटिव सोसाइटीज का निर्माण करवा रहे हैं परन्तु हमारा ध्यान जिस प्रकार सड़कों की देहातों की ओर जाना चाहिए था नहीं जा पाया है। यह भी निर्विवाद है कि सड़कों के निर्माण के संबंध में आशातीत प्रगति हुई है परन्तु जिस प्रगति की हम अपेक्षा कर रहे थे उतनी प्रगति अभी हम सड़कों की ओर नहीं कर पाये हैं। यदि हम इसके कारणों की ओर ध्यान दे तो जो कारण दृष्टिगोचर होता है वह यह है कि हमारी सड़कों के संबंध में जो प्लानिंग है वह दोषपूर्ण है। जिन गांवों में सड़कों की आवश्यकता है उन गांवों में सड़कें नहीं बनाई जाती हैं और जहां पर आवश्यकता नहीं है वहां सड़कों का निर्माण होता है। यदि आज गांवों में सड़कों का निर्माण हो गया होता और तेजी से होता, तो हमारे गांव बहुत तेजी के साथ प्रगति करते और उत्थान की तरफ अग्रसर होते। मैं एक मिसाल अपने जिले की देना चाहता हूं। मेरे हरदोई जिले में नीलमयी नदी का पुल मन्जूर हुआ था और दूसरी पंचवर्षीय योजना में उसके बनने की बात थी, परन्तु अभी तक उसके ऊपर

[श्री बुलाकी राम]

कोई कार्य नहीं शुरू किया जा सका । इसका कारण केवल एक ही है और वह यह है कि गर्रा नदी पर पुल का निर्माण नहीं हुआ है जिसकी वजह से नीलमयी नदी का पुल का निर्माण असम्भव सा प्रतीत होता है क्योंकि जबतक गर्रा नदी पर पुल नहीं बनाया जाता तब तक नीलमयी नदी के पुल के लिये सामग्री नहीं पहुंचाई जा सकती। वह पुल पहले बनना चाहिये लेकिन उसकी कहीं चर्चा भी नहीं है ।

इसी प्रकार से जहां तक सड़कों का सवाल है, हमारा जिला हरदोई बहुत पिछड़ा हुआ है । उस जिले में एक बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है जिसको हम कटियारी कहते हैं। इस कटियारी इलाके से ५, ६ नदियां आकर गुजरती हैं जिनको हम गंगा, रामगंगा, नीलमयी, कुंडा और गर्रा नदी कहते हैं । इस इलाके में कोई भी सड़क नहीं है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में एक सड़क बिलग्राम से सवाईजपुर तक स्वीकृत हुई थी लेकिन आज तक उसका निर्माण नहीं हुआ । मुझे आशा है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में वह जरूर बना दी जायेगी । आज हम देखते हैं कि शहरों की तरफ ही हमारी सरकार का ध्यान है । कहीं पर स्टैडियम बन रहा है, कहीं पर अजायब घर बन रहा है, कहीं पर नाचघर बन रहा है, कहीं पर नुमायश घर बन रहा है और कहीं पर चिड़ियाघर बन रहा है । आज देहात के लोग आवागमन के साधन न होने के कारण तबाह हो रहे हैं । बरसात के दिनों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना असम्भव हो गया है । ऐसे समय में यह चिड़िया घर बनाना, नाच घर बनाना, स्टैडियम बनाना कहां तक शोभा देता है । उपाध्यक्ष महोदय, अगर एक स्टैडियम की लागत से सड़कें बनाई जायं तो गांवों में कई सड़कें बन सकती हैं । एक चिड़ियाघर की लागत से कई गांवों में कई पक्की सड़कें बन सकती हैं। इसी प्रकार नाचघर की लागत से अगर सड़कें बनाई जायें तो बहुत-सी सड़कें बन सकती हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आज हमें देश का नवनिर्माण करना है, गांवों का उत्थान करना है तो हमें गांवों की सड़कों की तरफ अधिक ध्यान देना होगा। बगैर इस तरफ ध्यान दिये हमारे देश का नवनिर्माण सम्भव नहीं हो सकता । इसलिये हम माननीय मन्त्री जी से यह आशा करते हैं कि वे गांवों के गलियारों को, गांवों की सड़कों को, जो बहुत ज्यादा खराब है, बनाने के लिये शीघ्र ध्यान दें।

हमारे से पेश्तर एक माननीय सदस्य श्री रघुरतनजेबहादुर सिंह ने भाषण दिया है । उनके भाषण को सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि एक ताल्लुकेदार होते हुये उन्होंने किसानों की बात की और मजदूरों की बात की । अगर आज से कुछ दिन पहले उन्होंने इस प्रकार से किसान, मजदूर और झोंपड़ी की बात की होती तो शायद आज यह नतीजा न होता और उनकी ताल्लुकेदारी समाप्त न हुई होती । आज वह कहते हैं कि मिनिस्टर और माननीय सदस्य ऊंचे ऊंचे घरों में रहते हैं, कोच पर बैठते हैं, सोफे पर बैठते हैं। मैं कहता हूं कि अगर वह अपनी तरफ देखें तो अधिक अच्छा हो उन्होंने एक कुत्ता पाल रखा है अगर उसके खर्च को देखा जाय तो उससे ४ आदमी खा सकते हैं । ऐसे ऐसे ताल्लुकेदार आज भी ऊंची-ऊंची हवेलियों और कोठियों में रहते हैं, परन्तु यहां पर बैठकर दिखाने के लिए मजदूर, झोपड़ी और किसानों की बात कहते हैं तो मैं समझता हूं कि यह भी समय का परिवर्तन है और हमारे पूज्य बापू का आशीर्वाद है ।

श्री उपाध्यक्ष---आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री रामकुमार वैद्य (जिला मुरादाबाद)---उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग की मांगों पर विरोधी पक्ष के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने खड़ा हुआ हूं । श्रीमन्, इस सदन के सभी माननीय सदस्य जो अब तक बोले हैं उनके भाषणों से प्रकट होता है कि सब सहमत है कि हमारे प्रदेश में और देश में भी सब से अधिक महत्व निर्माण कार्यों में सड़कों के निर्माण करने की है । ठीक है, आवश्यकता के

अनुसार लोग अस्पतालों और स्कूलों और दूसरी बहुत-सी चीजों के निर्माण की मांग करते हैं, लेकिन श्रीमन्, मेरा तो यह विश्वास है कि अगर हम किसी क्षेत्र की उन्नति करना चाहते हैं, और वहां नवजागरण उत्पन्न करना चाहते हैं और आयोजना को कार्यान्वित करना चाहते हैं तो वहां सड़कें बनवा दीजिये । शेष कार्य स्वतः होने लगेगा । लेकिन दुख है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की नीति इस प्रकार की नहीं है । सड़कें प्रतिवर्ष बनती हैं और निश्चय ही जब से यह सरकार आयी है सड़कों की लम्बाई में कुछ वृद्धि भी हुई है, लेकिन वह संतोषजनक नहीं है और उसमें भी सब से बड़ा असंतोष यह है कि जहां की आवश्यकता को प्राथमिकता देना चाहिये उन उन क्षेत्रों पर इस विभाग ने सर्वथा उपेक्षा की नीति बरती है ।

बहुत से आदरणीय सदस्यों ने कहा है और मैं भी अपने जिले के अनेक उदाहरण उपस्थित कर सकता हूं । अनेक जिले हैं कि जो बाढ़ग्रस्त हैं और दुर्भाग्य से हमारे पश्चिमी जिलों में भी पिछले ५ सालों से बराबर बाढ़ आती रही है और जो कष्ट उस समय लोगों को होता है वह अधिक बढ़ जाता है कि जब कोई मार्ग न हो आने-जाने के लिये । पानी में भी हम किसी प्रकार पक्की सड़क पर चल सकते हैं लेकिन कच्चे रास्ते पर या वहां जहां रास्ते नहीं हैं, चलने में जीवन सुरक्षित नहीं रहता और इससे जनता को बहुत अधिक कष्ट होता है । मेरे जिले में भी पिछले ५ वर्षों से बाढ़ आती है और अमरोहा में ६ प्राकृतिक बहाव हैं । ३ उत्तर की ओर हैं और ३ वर्षा ऋतु में बहने वाली नदियां दक्षिण की ओर हैं उस तहसील में एक सड़क को छोड़ कर, जो मुरादाबाद से बिजनौर जाने वाली है और जो लगभग २० साल पहले बनी थी, कोई दूसरा पक्का मार्ग नहीं है । स्थिति यह है कि अमरोहा और आस-पास की जनता ने अनेक बार और अनेक प्रकार से मांग की सरकारी अधिकारियों से, जलूस निकाले, जलसे किये गये, प्रतीक धन एकत्रित किया गया मार्ग निर्माण के लिये, लेकिन दुर्भाग्यवश बहुत दिन के बाद वह बात गवर्नमेंट के कान में आयी और हमारे एरिया में ३ सड़कों पर कुछ काम हुआ लेकिन अधूरा रह गया और पता नहीं कि भविष्य में वह कब तक पूरा होगा ।

एक और विशेष स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित करूं । अमरोहा तहसील में लगभग ६०० कुछ गांव हैं और उसके पास ही एक कस्बा है कांठ, जहां से एक दूसरे आदरणीय सदस्य यहां आते हैं शासकीय पक्ष के । श्रीमन्, कांठ की दूरी अमरोहा से साढ़े १३ मील है, लेकिन कांठ के लोगों को अपने तहसील के काम से, चिकित्सा के काम से या अन्य जीवनोपयोगी कामों से जब अमरोहा आना पड़ता है तो वह ३७, ३८ मील की दूरी तय कर के आते हैं, कांठ से मुरादाबाद और फिर वहां से अमरोहा । इस साढ़े १३ मील की यह सड़क बना देने से लगभग २४० ग्राम के निवासियों का बहुत बड़ा संकट दूर हो सकता है । बरसात में तो यह स्थिति होती है कि वहां के लोग अपने को सारे देश से अलग समझते हैं । ३ वर्ष पूर्व उस सड़क का एक ३ मील का टुकड़ा बना था लेकिन पुलों के न होने की वजह से उसकी कोई उपयोगिता नहीं रही और वह टूटने लगा है । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जहां सार्वजनिक निर्माण विभाग एक सामञ्जस्य और समन्वय की नीति बरते वहां साथ-साथ यह भी विचार करे कि विभाग को कहां-कहां, किस-किस कार्य को प्राथमिकता देनी चाहिये । जहां बाढ़ आती है, कोई साधन नहीं हैं आने जाने के, वहां अगर सड़कें बनाई जायं और उनको प्राथमिकता दी जाय तो श्रेयस्कर होगा । लेकिन स्थिति यह है जैसा कि पूर्ववक्ताओं ने भी कहा है, सरकार के कामों में कोई निश्चित नियोजन नहीं है । एक ओर हम लाखों रुपया खर्च करते हैं कुछ ऐसे कामों पर जिनसे हमारा जन-साधारण संतुष्ट नहीं होता । हम उनकी आवश्यकता से इन्कार नहीं कर सकते, लेकिन आवश्यकताओं में भी प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्तर हैं । हमको श्रेणी विभाजन तो करना ही होगा ।

[श्री रामकुमार वैद्य]

एक कम उन्नत देश में जनोपयोगी साधनों का होना मेरे विचार में अत्यन्त आवश्यक है। अतः कच्ची और पक्की दोनों प्रकार की सड़कों के निर्माण को प्राथमिकता दी जाय। इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री शीतलाप्रसाद (जिला गोंडा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। हमारी जनप्रिय सरकार ने जो भी आज तक निर्माण किये हैं उनके लिये मैं बधाई देता हूं। हमारे जिले में नदी और नालों का जाल बिछा हुआ है लेकिन सड़कें बहुत ही कम हैं। एक राजमार्ग जो यहां लखनऊ से होकर हमारे गोंडा जिले को पार करता हुआ, जिसे आसाम रोड कहते हैं, वह गया है। इसके बीच में दो दरिया घाघरा और सरजू पड़ते हैं जिन पर पुल नहीं है। यह मार्ग बहुत ही उपयोगी है, लेकिन इस पर पुल न होने की वजह से लोगों को काफी कठिनाई होती है और राज्य के प्रबन्ध में भी कठिनाई होती है। मेरा सुझाव है कि इस पुल को तृतीय पंचवर्षीय योजना में ले लिया जाय। वैसे तो हमारे जिले में सरकार ने एक पुल बहुत ही महत्वपूर्ण गत वर्ष में बनाया है जिससे काफी लोगों को टेढ़ी नदी पार करने में फायदा पहुंचा है, लेकिन बहुत से नाले नदी ऐसे हैं जिन पर पुल बनाने की नितान्त आवश्यकता है।

हमारे गोंडा जिले में तहसील तरबगंज एक बहुत ही बैकवर्ड तहसील है और उस इलाके में सिर्फ मक्का, गन्ना और थोड़ी शकरकन्दी पैदा होती है। रबी की फसल तो नाममात्र को ही होती है। तहसील तरबगंज लगभग ६० मील लम्बी और १५–२० मील चौड़ी है और पूरी तहसील को ६० मील घाघरा क्रास करती है। वहां पर घाघरा और सरजू की बाढ़ से लोग तबाह रहते हैं और फसल के नाम पर सिर्फ गन्ना बच जाता है। लेकिन गन्ने को ले जाने के लिये कोई साधन नहीं है। अगर उस इलाके में कोई सड़क बना दी जाय तो वहां की हालत बहुत सुधर सकती है। वहां पर गरीबी चरम सीमा तक पहुंच चुकी है। वैसे तो कहने के लिये सभी पूर्वी जिलों में गरीबी है लेकिन तहसील तरबगंज में इतनी गरीबी है जिसको कहने में दुःख होता है। मैं प्रमाण के लिये एक दृष्टान्त देना चाहता हूं। थाना तरबगंज में एक गांव दोहरीजीत है— जब मैं दौरे पर गया तो मुझे बताया गया उसमें एक मजदूर चार आने रोज पर एक किसान के यहां काम करता था। उसे आधा सेर सत्तू दोपहर में मिलता था और खाने वाले ६ थे, एक अंधी मां, बीबी, वह खुद और बच्चे। इसी में वह निर्वाह करता था। एक दिन इत्तिफाक से शाम को वह काम करके वापस आ रहा था तो उसने एक गन्ना किसी के खेत में तोड़ लिया। किसान पहुंचा तो उसने उसे १–२ डंडे मारे और वह १८ वर्ष का युवक गिर कर मर गया। तो यह वहां की स्थिति है। वहां पर सैलाब आते हैं और खरीफ की फसल मारी जाती है। अगर वहां पर सड़क बना दी जाय तो वहां की मुख्य पैदावार जो गन्ना है उसे लोग ठीक ढंग से बोकर अपना निर्वाह कर सकते हैं। लेकिन यातायात न होने की वजह से फैक्टरी तक गन्ना पहुंचा न सकने के कारण उसे लोग कम बोते हैं। अगर बेलसर–उमरी-बेगमगंज रोड पसिका होते हुये कर्नेलगंज रोड से मिला दी जाय तो गन्ना जरवल फैक्टरी को आसानी से पहुंचाया जा सकता है। उमरी–बेगमगंज से बुरजनपुर घाट तक सड़क बन जाय तो नवाबगंज मिल एरिया के किसानों का गन्ना मिल तक आसानी से पहुंच सकता है और उनकी हालत बहुत कुछ सुधर सकती है।

इसके अतिरिक्त एक सड़क गोंडा दक्षिणी में बनायी जा रही है जो बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है। उस सड़क पर एक पुल टेढ़ी नदी में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का बना हुआ है जो इतना कमजोर है कि उस पर लारियां और ट्रक्स नहीं पार कर सकते हैं। वह पुल अगर बनवा दिया जाय तो जो कुछ कांटे उस एरिया में मिलों के हैं, जिन पर गन्ना गाड़ियों के द्वारा इतना घुमा फिरा कर लाया जाता है कि बजाय १८ मील के उनको ४०, ४६ मील का चक्कर पड़ता है। इसका नतीजा यह होता है कि किसानों को गन्ने का किराया ५, ६ आने मन देना पड़ता है जिससे उनको १ रु० मन ही गन्ने की कीमत मिल पाती है। अगर पुल हो जाय तो किसानों को दो ढाई आने मन ही गन्ने का भाड़ा देना पड़ेगा और इस तरह किसानों को गन्ने का दाम १ रु० ४ आने, ५ आने मन मिल सकता है। इससे किसानों को काफी लाभ हो सकता है। इसके

अतिरिक्त हमारे इस मांझा एरिया में जब कभी सैलाब आ जाता है तो कोई भी सरकारी सहायता नहीं पहुंच पाती है क्योंकि बीच में इतने नदी नाले पड़ते हैं कि वहां पहुंचना असम्भव हो जाता है। तो इस उमरी-बेगमगंज रोड को अगर पुख्ता बनवा दिया जाय और एक पुल का निर्माण करवा दिया जाय तो मांझा एरिया में जितने भी ४, साढ़े ४ लाख मनुष्य बसते हैं उनको काफी सुविधा हो जाय।

मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि इस काम को करना बहुत आवश्यक है। वैसे तो देश के हर काम को लेना है, लेकिन जिस काम की वजह से जनता के ऊपर आर्थिक असर पड़ता हो उसको पहले लेना चाहिये। इस काम को हाथ में ले लेने से तरबगंज एरिया की साढ़े ४ लाख जनता जिन्दा रह सकती है और वह धीरे-धीरे अपना आर्थिक विकास कर सकती है।

श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो विरोधी पक्ष की तरफ से कटौती का प्रस्ताव पेश है, उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, हर सदस्य ने अपने-अपने जिले तथा अपने-अपने क्षेत्र के लिये कहा है और मैं भी अपने जिले की कुछ बातें माननीय मंत्री जी को बतलाना चाहता हूं। श्रीमन्, हमारे यहां धुमरी का जो पुल बना है उसको माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी देखा है। वहां की जनता ने बड़ा तगड़ा श्रमदान किया जिसकी कीमत १ लाख रुपये आंकी गयी थी। उत्तर प्रदेश में आज तक ऐसा श्रमदान कहीं नहीं हुआ है, लेकिन जनता ने एड़ी से चोटी तक पसीना निकाल कर जो वहां पर मिट्टी डाली उसकी रोक के लिये कोई प्रबन्ध नहीं किया गया जिसकी वजह से एक बरसात में ही इधर-उधर के किनारे कट कर बह गये। जनता ने अपने श्रमदान से उसको तैयार तो कर दिया, लेकिन नदी के बहाव के कारण किनारे इधर-उधर हो गये। अगर वहां पर ईंटें नहीं लगायी गयीं तो शायद अगले साल की बरसात के बाद पता भी नहीं लगेगा कि पुल कहां गया और नदी कहां गयी। वहां इधर-उधर किनारे पर मिट्टी या कंकड़ डलवा देने चाहिये ताकि गरीब जनता का वह धन ठीक से सुरक्षित रह सके। गवर्नमेंट की तरफ से जितने निर्माण के कार्य होते हैं उनका उद्घाटन करने के लिये मंत्री महोदय लोग ही जाते हैं। इस घुमरी पुल का उद्घाटन करने के लिये भी मुख्य मंत्री जी गये थे। श्रीमन्, वहां लोगों को धोका देकर मास्टरों और सेक्रेटरीज तथा पटवारियों द्वारा बुलवाया गया। जनता से कहा गया कि यहां माननीय मुख्य मंत्री जी आ रहे हैं और सब लोगों का लगान माफ हो जायगा। धोखे में आकर जनता वहां पहुंच तो गयी, लेकिन बाद में वहां से सरकार को जिस तरह से कोसते-कोसते पैदल ही आना पड़ा उसके लिये मैं क्या कहूं।

इसी तरह से पिछले साल के बजट में एटा से सहावर की सड़क के पुल के बनने की बात की गयी थी, लेकिन इस साल उसके नाम कुछ भी नहीं है, मालूम नहीं क्या बात हुई। जिले के एम० एल० ए० लोगों ने कहा भी कि सहावर एरिया में काली नदी पर पुल का बनना बहुत जरूरी है ताकि वहां की जनता के लिये यातायात के साधन हो जायं, लेकिन कुछ कांग्रेसी एम० एल० ए० लोगों ने उसको न होने दिया। न मालूम क्यों कर दिया, उनके क्षेत्र में कुछ नहीं होगा। इस तरह की बातें होती हैं जिनकी बाबत क्या कहा जाय।

एक एरिया सकीट का है वहां भी यातायात के साधन नहीं हैं। मुकदमें वाले जाते हैं तो लोग टाइम बे टाइम पहुंचते हैं। वहां से एटा तक सड़क श्रमदान से तैयार हुई लेकिन वह मिट्टी भी बही जा रही है। उस पर कोई काम नहीं हुआ। मैं चाहता हूं कि एटा से सकीट होती हुई इसारा तक सड़क पक्की कर दी जाय तो बहुत अच्छा होगा। इसी तरह से एटा से शिकोहाबाद सड़क जाती है। वह भी ठीक नहीं हो पाती। पक्की सड़क कभी २, कभी ४ और कभी ६ मील बना दी जाती है। ३२ मील का रास्ता ५ घंटे लारी में लगते हैं।

[श्री गंगाप्रसाद वर्मा]

इसी तरह से टूंडला वाली सड़क पर किनारे पर पानी भरा हुआ है। उसे ऊंचा भी नहीं किया गया । मेरा जिला इतना बैकवर्ड है, जैसा कि और भी माननीय सदस्यों ने कहा है, जिसकी ओर माननीय मंत्री जी को विशेषरूप से ध्यान देने की आवश्यकता है ।

श्री गणेशप्रसाद पांडेय (जिला गोरखपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह अनुदान प्रस्तुत करके उन्नति का बहुत कुछ मार्ग सुलभ कर दिया है । मैं आपके द्वारा उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि गोरखपुर की बांसगांव तहसील पर दुनिया में सब से ज्यादा आबादी का बोझ पड़ता है । १ वर्ग मील में वहां साढ़े १० सौ आदमी बसते हैं। इतनी घनी आबादी संसार में कहीं भी नहीं है । इस तहसील भर में आज तक सरकार की तरफ से यातायात का साधन कोई भी नहीं था, लेकिन मैं श्री लक्ष्मीरमण आचार्य जी का आभारी हूं कि उन्होंने एक बार कृपा करके जाकर उस तहसील को देखा और एक पक्की सड़क इस बार पंचवर्षीय योजना में बनाने को रक्खी, लेकिन वहां उसको भी पूरा नहीं रक्खा क्योंकि ४८ मील में से केवल ३८ मील बनाया जा रहा है बाकी १० मील गोला से बड़हलगंज तक छोड़ दिया गया है। उस तहसील में एक हिस्सा दुआबे का है जो कुआनो और घाघरा नदी के बीच में पड़ता है जिसकी आबादी ५० हजार है और क्षेत्रफल २५ वर्ग मील एरिया उसमें पड़ता है । वहां हर साल बाढ़ के कारण ईख की खेती के अलावा दूसरे अन्न की सब खेती असफल हो जाती है । वहां किसान को ईख की खेती से कुछ राहत मिल जाती है, लेकिन यातायात के साधन न होने के कारण उस गन्ने की हालत यह होती है कि उसे मिल तक नहीं पहुंचाया जा सकता । नतीजा यह होता है वह लकड़ी से भी कम कीमत पर ८ आने मन के हिसाब से बीज के लिये दूर-दूर के देहातों में बैलगाड़ियों पर ले जाया जाता है। यदि वह गन्ना मिल तक पहुंच पाता तो १ रुपये ७ आने मन पर बिकता, लेकिन यातायात के साधन न होने से वहां के किसानों की बहुत बड़ी आर्थिक क्षति होती है ।

तहसील बांसगांव के लोग इतने गरीब हैं कि वे अपना घर छोड़ कर संसार के हर देशों में जाकर नौकरी और मजदूरी करते हैं जैसे बर्मा, श्याम, मलाया, हिन्देशिया, इन्डोचीन, सुमात्रा, जावा, हांगकांग, फिलीपाइन्स, नेटाल, जोहन्सवर्ग और अमेरिका के निकट ट्रिवीडाट आदि टापुओं में जाकर रोजी कमा कर वहां से मनीआर्डर द्वारा अपने घर वालों के लिये कुछ रुपया भेजा करते हैं । हिन्दुस्तान भर में कोई भी तहसील ऐसी नहीं है जहां के आदमी कुली के रूप में संसार भर में मजदूरी करते पाये जायं । संसार के प्रत्येक देश में आपको बाँसगांव के लोग कुली का काम करते मिलेंगे। इतने पिछड़े हुए क्षेत्र की तरफ सरकार का ध्यान जैसा जाना चाहिये नहीं जा सका है । इतनी बड़ी तहसील के अन्दर १ इंच भी रेलवे की सड़क नहीं है और एक भी मिल या कारखाना नहीं है और न कोई उद्योग-धंधा ही वहां है । यदि सरकार वहां पक्की सड़कें बनवा दे जिससे यातायात के साधन हो जायं तो वहां उद्योगधंधे भी हो जायं और किसान अपनी उपज आसानी से बाजार तक पहुंचा सकें और अपना जीवन उन्नत कर सकें। जो सड़क पिछले साल बनाई गई है उसमें सिकरीगंज से बेलघाट होकर कूरी बाजार तक एक कच्ची सड़क जाती है इसको सरकार पक्का करा दे तो गन्ना मिलों को आसानी से पहुंचाया जा सकता है । गोला से बड़हलगंज जो १० मील का हिस्सा पक्का होने से छोड़ दिया गया है उसको भी पूरा कर दिया जाय तो बांसगांव तहसील के पश्चिमी हिस्से के लोग अन्य आस-पास के जिलों से सम्बन्ध स्थापित कर सकते हैं । इसी तरह से गोला से जो सड़क आजमगढ़ तक जाती है वह गोला से कौड़ीराम तक पक्की कर दी जाय तो आजमगढ़ जिले से सम्बन्ध स्थापित हो सकता है । इसी प्रकार बांसगांव से धुरियापार घाट होकर नरगड़ा घाट तक पक्की बनवा दी जाय तो आजमगढ़, फैजाबाद और गोरखपुर से सम्बन्ध स्थापित हो सकता है । इसलिये मैं आपके द्वारा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अगर इस योजना में न हो सके

तो इन सड़कों को तृतीय योजना में जरूर पक्का करा देने की कृपा करें। एक सड़क बांसगांव से खजनी हो कर के सहजनवा को जाती है उसको भी पक्की करा देने की कृपा करें।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)––उपाध्यक्ष महोदय, अंग्रेजी राज्य में जिस तरह से सड़कें बनाने की परिपाटी थी वही परिपाटी इस सरकार के द्वारा भी चालित है। आप देखेंगे कि बहुत पुरानी सड़कें जो रेलवे लाइन के मुकाबले में बनी हैं वही सड़कें सुन्दर ढंग से और अच्छी प्रकार से बनाये जाने की योजना इस सरकार की भी है। सारे प्रदेश में जहां रेलवे लाइन है उसी के पैरेलल पक्की सड़कें बनती जा रही हैं। जो पुरानी सड़कें हैं उन्हीं पर कंकड़, सीमेंट और तारकोल। यही सरकार की योजना है। सही माने में तो यह होना चाहिये कि जो सुदूरपूर्व के गांव हैं, पिछड़े हुए हैं, विकसित नहीं हैं, आने-जाने के कोई साधन नहीं हैं। रेल लाइन बिछाना तो इस सरकार के अधिकार में नहीं है, उसमें ज्यादा पैसा भी खर्च होता है, तो सर्वप्रथम कर्तव्य यह था कि वहां जाने के लिये कंकड़ की ही सड़क सही, सरकार बनवा दे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। नई सड़कें जो गांवों में मेल कराती हैं वह नहीं बन रही हैं। इस सदन में कई बार कहा जाता है कि जो क्षेत्र बाढ़पीड़ित हैं वहां बाढ़ के जमाने में आने जाने का कोई साधन नहीं रहता सरकार यदि वहां के लोगों को सहायता देना चाहती है तो यातायात के साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराये। लेकिन कुछ नहीं। पुलिस स्टेशन बहुत से ऐसे हैं जहां पर पहुंचने का कोई साधन नहीं है। लेकिन सरकार उन स्थानों पर कोई ध्यान नहीं देती है। माननीय दीपनारायणमणि त्रिपाठी जी ने कहा कि बहुत जरूरी है शान, शौकत के महल भी बनाये जायं। मैं इस सम्बन्ध में इतना ही कहूंगा कि ठीक है महल भी अच्छे बनें, सड़कें भी बनें, लिफ्ट भी लगें, लेकिन साथ ही साथ अपने गांवों में पहुंचने के लिये और देश को विकसित करने के लिये लोगों को आने-जाने के साधन देने के लिये, पिछड़े हुए क्षेत्रों को ऊंचा उठाने के लिये, जो देहात की कारीगरी है उसको दूर तक पहुंचाने के लिये आवश्यकता है कि गांवों की सड़कें पहले बनायी जायं। आप देखें हम लोग जहां गढ़लशफा में रहते हैं वहां बहुत अच्छी बीच में एक इमारत थी वह तोड़ी गई उसमें कितना पैसा खर्च हुआ और तोड़ने के बाद उस स्थान पर सीमेंट की सड़क बनायी जायगी।

अब सोचने की बात है कि एक तरफ जहां प्रदेश में लोगों के रहने के लिये घर नहीं हैं, इसी शहर में लोग सड़कों पर रहते हैं, वहां सरकार पुराने बंगलों को जिसमें विधायक रह सकते हैं तोड़ कर सीमेंट की सड़क बनायी गई। यह भी सुनने में आता है कि एक पास के और बंगले को तोड़ कर के विधान भवन के सामने की सड़क में मिलायी जाने वाली है। जिस प्रदेश में लोगों को यातायात के अभाव में मीलों पैदल चलना पड़ता हो, वहां के आदमी पैदल चलते रहें और जहां हम लोग रहते हैं हम ५ कदम पैदल न चलें। सीमेंट की सड़क सिर्फ इसलिये बनायी जाय कि बाहर के लोग आकर देखें कि प्रदेश की सरकार गरीब नहीं है, बहुत धनी है। इसीलिये ही दिल्ली में मंत्रियों के रहने के लिये लाखों रुपया खर्च किया जा रहा है। लिफ्ट अपंग आदमियों के लिये आवश्यक है। विधान भवन में लाखों रुपये की सजावट की बात है जो अंग्रेजी राज्य का बना हुआ है। उसको जरूरत नहीं थी सजाने की। लेकिन जो सरकार अपने को समाजवादी ढांचे में ढालना चाहती है वह सरकार ८ लाख रुपया खर्च करके इस विधान भवन को सुसज्जित करना चाहती है। इसलिये कि बाहर के आने वाले लोग देख कर समझें कि सही मानी में उत्तर प्रदेश की सरकार उसी प्रकार की सजावट गांवों में भी करती है। लेकिन गांवों में जाने के लिये पैदल के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। यह जो किताब बटी है अगर माननीय निर्माण मंत्री का ध्यान इस पर जाता हो तो सही मानी में कुछ अर्थ निकलता। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के वाक्य उद्धृत हैं कि सड़क वहां बननी चाहिये जहां लोग पैदल

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

चलते हैं और घोड़ों के अलावा और कोई साधन नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह जो बजट है इससे कहां इस आदेश का प्रतिपालन हो रहा है? श्रीमन्, जिस एरिया से आप आते हैं, मैं आता हूं, उसे देखें। जो बाढ़पीड़ित एरिया, गंगा और घाघरा के किनारे के एरिया हैं जहां हर साल हजारों की तादाद में गांव टापू बन जाते हैं, उनको बचाने के लिये, पिछड़े क्षेत्र को ऊंचा उठाने के लिये सरकार का कुछ प्रावीजन है? कोई नहीं है। हमारे यहां से जौअनपुर–बिलरियागंज–महाराजगंज–कमरिया होकर फैजाबाद रास्ता जाता है। वहां पैदल चलना भी मुश्किल है। मधुबन–दुबारी–परसिया, वर्ष के ९ महीने आदमी नहीं चल सकते हैं। कबूतर की तरह लोग बन्द होकर रहते हैं। इसलिये पहले उन स्थानों का विकास होना चाहिए जो पिछड़े हुए हैं। क्या आवश्यकता है कि एक सड़क जो पहले से कंक्रीट की है उसको तारकोल लगाते हैं, सीमेंट लगाते हैं। एक तरफ तारकोल और सीमेंट लगाया जाता है और एक तरफ पैदल चलने के लिये भी रास्ता नहीं मिलता। यह ठीक नहीं है। मैं कहूंगा सरकार से कि जो अंग्रेजों की परिपाटी है उसको बदलो। पहले गांव बनाये जायं, गांव में रास्ता दो, उजड़े हुए क्षेत्रों को बसाओ तब ही यह क्षेत्र आगे बढ़ सकेंगे। विधान भवन और विधायक निवास को सजाने से नहीं बढ़ेंगे। जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उनको आगे बढ़ाने के लिये यातायात सुलभ किया जाय। इसी में सरकार और प्रदेश का लाभ है।

श्री मान्धातासिंह (जिला बलिया)---उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुदान सदन में पेश है मैं उसका समर्थन करता हूं। आजादी हासिल करने के बाद ११ वर्ष में जो इस मुहकमें के भीतर काम हुआ है वह सबके सामने जाहिर है। जब अंग्रेज यहां पर थे उन दिनों जो यातायात के साधन थे और जो भी निर्माण-कार्य में थे वह अपने तरीके और अपने ढंग के उन्होंने बनाये थे। आज जो साधन सरकार उपलब्ध कर रही है इसमें कोई संदेह नहीं कि वह नागरिक का खयाल रखते हुए कर रही है। जहां घोड़े चलते हैं वहां पर सड़क बननी चाहिये थी, लेकिन जब तक कि शहर से शहर का मिलाव नहीं होगा, तहसील से शहर का मिलाव नहीं होगा, जिले का मिलाव नहीं होगा, तो क्या बीच में ही देहातों में बना कर हम कोई फायदा पहुंचा सकते हैं?

आज हमारे माननीय मित्र को मालूम होगा कि जो योजना हमारे सामने पेश है, हम अपने तमाम प्रान्त को छोटे-छोटे टुकड़ों में बांट रहे हैं। कुछ प्लानिंग सेंटर बना रहे हैं, विकास योजना चालू कर रहे हैं। मेरा मतलब यह है कि उस सेंटर तक पहुंचने के लिये हम छोटे-छोटे रास्ते बनाकर सबको सुविधा उपलब्ध करायेंगे ताकि सेंटर पर हर व्यक्ति पहुंच सके और वहां जो जरूरत की चीजें सरकार इकट्ठा करेगी वह सब हासिल कर सकें। कहा गया कि यह सरकार अंग्रेजों के नकशेकदम पर चल रही है, यह सुनकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। आज तक कभी भी विरोधी दल की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं कही गई कि इस लोकप्रिय सरकार ने कभी भी कोई एक काम भी सराहना या तारीफ का किया है। कम से कम वह जनता के सामने यह भी बताये कि यह यह काम सरकार ने किये हैं और यह-यह बाकी हैं। सरकार कब कहती है कि उसने देश का सम्पूर्ण निर्माण कर लिया अभी तो उसे बहुत कुछ करना है, हम सदियों से गुलामी की जंजीरों में बंधे रहे, हमारे हाथ बंधे हुए थे और हमारा देश नीचे स्तर पर पहुंच चुका था तो क्या ऐसे सदियों के बिगड़े हुये देश को हम दस साल में बना सकते हैं? हमारा दावा है कि अगर उधर के लोग इधर सरकार में होते तो वह शायद इतना काम भी न कर पाते जितना इस सरकार ने किया है। मैं अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा।

हमारे निर्माण विभाग में जो रखरखाव की बात है जो इंजीनियर्स हैं ओवरसीयर हैं या वर्क एजेंट्स हैं या मेट्स हैं उनकी तरफ मैं आप के द्वारा मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इंजीनियर्स के बारे में कहा जाता है कि इन बड़े-बड़े वेतन लेने वालों को नहीं रखना चाहिये और साथ ही यह भी कहा जाता है कि बड़ा करप्शन है। एक तरफ यह भी कहा जाता है कि

करप्शन का कारण यह है कि वेतन कम दिया जाता है तो इस के माने यह हुये कि वेतन अधिक होने चाहिये। वेतन अवश्य बड़े हों। लेकिन मैं माननीय उपाध्यक्ष जी, आप के द्वारा मंत्री जी से कहूंगा कि वह अपने विभाग में थोड़ी सी सख्ती रखें, जो पुराने विभाग के तौर तरीके चले आते हैं उन के लिये जरा सख्ती की जरूरत है । आज देश अपना है, यह इंजीनियर्स भी अपने भाई हैं हम उन को करप्ट नहीं कहेंगे, ओवरसियर कौन है वे भी हमारे ही भाई हैं मेट कौन है वह भी हमारे ही भाई हैं, बार बार अपने ही भाइयों को करप्ट कहना अच्छा नहीं लगता, अगर एक ईमानदार आदमी को भी बार-बार चोर कहें तो वह भी सुनते सुनते चोर हो सकता है । इसलिये किसी को भी बार-बार करप्ट कहने से कोई लाभ नहीं है । इस वास्ते थोड़ी सख्ती की जरूरत है ।

मुझे एक बात यह भी कहनी थी कि सड़कों के किनारे जो पेड़ लगे हुये हैं उनकी ओर इंजीनियर्स कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं हमारे जिले में अक्सर देखा जाता है कि वह पेड़ काटे जाते हैं कभी आधे धड़ से और कभी ऊपर नीचे से सब काट लिये जाते हैं । कोई रोक इनकी नहीं होती ।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान खास तौर से बलिया जिले के एक पुल की तरफ और दिलाना चाहता हूं । हमारे यहां पिपराघाट का पुल बन रहा है उसके लिये मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं और बहुत अच्छी बात है। उस के लिये ११-१२ लाख रुपया मंजूर हुआ है, लेकिन वहां के इंजीनियर्स ने जो साइट उसके लिये तजवीज की है वह बहुत खर्चीली है और उस में बहुत से जरखेज खेत आ जाते हैं । अच्छा होता यदि जो इंजीनियर्स मौजूदा सड़क निकल रही है उसी को सामने रख कर अगर पुल बनाते । इंजीनियर्स का कहना यह है कि ज्यादा खर्चा होगा, लेकिन उससे जो जनता की खेती निकल रही है उसका मुकाबला किया जाये तो बहुत जरूरी है ।

एक बक्सर का पुल है जो बनना बहुत जरूरी है क्योंकि उसके बन जाने से बिहार से यू० पी० का एक तरह से संबंध हो जाता है । बक्सर के पुल से पूर्वी जिले के मजदूर या अन्य लोग गुजर कर बंगाल और बिहार में जाते हैं और जो कुछ भी कोयला, लोहा वगैरह वहां से इस तरफ आता है अगर वह पुल बन जाता है तो सड़क द्वारा वह लोहा, कोयला और सीमेंट बिहार से बलिया को ही नहीं बल्कि अन्य पूर्वी जिलों में पहुंच सकता था और उससे सबको बड़ा फायदा होता ।

एक सुझाव आपके द्वारा मंत्री जी को देना चाहता हूं कि जो श्रमदान की सड़कें बन रही हैं उनमें जनता पैसा और श्रम देकर अपना योग देती है, लेकिन उनके रख-रखाव का कोई इन्तजाम नहीं है । यदि उसके लिये अलग से बजट में प्राविजन कर दें और वह फौरन पी० डब्ल्यू० डी० में आ जाय और रख-रखाव हो तो इससे सब लोग उत्साहित होंगे और अधिक से अधिक श्रमदान देकर सड़कें बनाने की कोशिश करेंगे ।

इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं ।

श्री बालकराम (जिला शाहजहांपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि कल से १२ घंटे के बाद आपने मुझे ७ मिनट का मौका दिया है ।

कहना मुझे यह है कि जैसे अभी मानधाता जी ने कहा कि विरोधी दल के लोग कहते हैं कि यह सरकार इंगलैंड और अमरीका के ढंग पर चलती है, लेकिन उन्होंने ऐसी दलील कोई नहीं दी कि इंगलैंड और अमरीका के ढंग पर कैसे नहीं चलती है । मैं इसकी दलील दूंगा कि यह अमरीका और इंगलैंड के ढंग पर चलती है । सड़क जो बनती हैं तो कंकड़ की सड़क एक मील १०-१२ हजार में बनती है और सीमेंट की १०-१२ लाख में तो फिर सीमेंट की सड़क बननी चाहिये या कंकड़ की ? अब तक अगर कांक्रीट की सड़कें बनती रहीं तो इसलिये बनती रहीं कि यह सरकार भी पूंजीवादी ढंग पर चलती थीं, कोई बात नहीं थी, लेकिन अब कम से कम जब यह तय

[श्री बालकराम]

हो गया है कि देश में समाजवादी ढंग का समाज बनाया जायगा तो फिर हमें १०-१२ लाख रुपया लगवा कर सड़क नहीं बनवाना है बल्कि पूरे प्रदेश में कम से कम कंकड़ की सड़कें बनवानी हैं ।

दूसरी बात, हमारे त्रिपाठी जी चले गये, शायद हैं, उन्हें देवरिया में जो सड़क बनी है वह तो उन्हें दीख गयी कि दूने से ज्यादा बन गई, लेकिन पीलीभीत और शाहजहांपुर की तरफ उन्होंने नहीं देखा जहां एक में २१ और एक में १७ मील की सड़क ही बनी है । उन्हें पूरे सूबे की तरफ नजर दौड़ानी चाहिये । यह कोई देवरिया का तो सवाल है नहीं, पूरे सूबे का है ।

श्री उपाध्यक्ष---आप माननीय मंत्री जी से निवेदन करें, हर एक सदस्य अपने अपने लिये कहते हैं ।

श्री बालकराम---शिकायत यह है कि वह अपने देवरिया की मिसाल देकर कहते हैं कि इस सरकार ने दूने से ज्यादा सड़कें बनवा दीं ।

श्री उपाध्यक्ष---तो आप अपनी बात कह लीजिये ।

श्री बालकराम---तो मेरे कहने का मंशा यह है कि सरकार वहां से हार गयी इसलिये सरकार को उधर नजर नहीं डालनी है । सौतेली मां की तरह से उसे अपनी रस्मोरिवाज रखना है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा । जैसे आप और जगह से टैक्स वसूल करते हैं तो वहां से भी तो लेते हैं । इसलिये आपकी सरकार वहां भी है और यदि आपको समाजवादी समाज कायम रखना है तो उसको भी उसी नजर से देखना है जैसे कि देवरिया को देखते हैं । पीलीभीत के ऊपर मैं जोर दे रहा हूं कि जो सड़क टनकपुर मंडी से राजस्थान तक गई है उसका ८ मील का टुकड़ा पीलीभीत में कच्चा है उसे हमारी सरकार पक्का करा दे तो टनकपुर मंडी से राजस्थान तक पूरी सड़क हो जायगी । इसमें ज्यादा खर्चे की भी जरूरत नहीं है । आप उसे कंकड़ की सड़क ही बना दें जैसे कि बाकी बनी हुई है । इसमें इतना ही खर्चा होगा जितने में आपकी एक मील की सीमेंट की सड़क बनती है । इससे दोनों जिलों की सड़क पूरी हो जायगी और दोनों जिले वाह वाह करने लगेंगे ।

मान्धातासिंह जी चले गये उन्होंने इंगलैंड और अमरीका की बाबत दलील दी थी । जैसा कि और लोगों ने बताया है कि इसको सजाया जायगा । लिफ्ट बनी है । त्रिपाठी जी ने कहा था कि इसलिये बनी है कि हम जल्दी आ जायं । मैं उनको चुनौती देता हूं कि मैं पैदल आऊंगा और वह लिफ्ट से आयें तो देखें कौन पहले आता है । आप ४, ६, १० वर्ष के लिये यह सजाना छोड़ दीजिये । जब अपने प्रदेश में हर आदमी को खाना पीना दे सकें, पढ़ाई लिखाई पूरी कर सकें और देहात की सड़कें इस काबिल हो सकें कि जिन पर लढ़िया, रहलू वगैरा चल सकें तो फिर आप चाहे सीमेंट की बनाइये और चाहे रबर की बनवाइये, हमें इंकार नहीं है । वही मसल है कि "घर में नहीं दाने अम्मा चली भुजाने" आपके देहात के लोग भूखों मरते हैं और आप विधान मंडल को सजाने चले हैं, सीमेंट की सड़क बना रहे हैं ।

मान्धातासिंह जी ने यह भी कहा था कि हर शहर से शहर को मिला रहे हैं तो देहातों में सड़कें बनाने से क्या लाभ होगा ? मेरी समझ में कोई ऐसा शहर नहीं है जो किसी दूसरे शहर से न मिला हो । अगर एक भी शहर ऐसा होता तो वह बता देते और मैं मान जाता ।

यहां पक्की सड़क इसलिये बनाई जा रही है कि कहीं मिनिस्टर साहब की मोटर में ठस्का न लग जाय, लेकिन जो हमारे लिये नये कमरे बन रहे हैं उनमें एक कमरा घटा दिया है । रोटी बनाने की जरूरत नहीं है । आप समझते हैं कि हर आदमी होटल में खाना खायगा । अगर कोई खाना बनाना चाहे तो आपका क्या नुकसान है ? १० रुपये में ही तो वह गुजर करेगा जो आप उसको देते हैं । इस ढंग से काम चलेगा तो समाजवाद नहीं होगा । जिसको आप नये कमरे देंगे तो झगड़ा होगा और वह कहेगा कि पुराना लूंगा और नये कमरे कोई नहीं लेगा । इसकी मिसाल मौजूद है । अभी श्री महाराजसिंह भारतीय जी को नया कमरा नंबर ४६ दिया गया था, तो उन्होंने इंकार कर दिया कि मैं बाल-बच्चों को साथ रखूंगा इसलिये मेरी इसमें गुजर नहीं होगी ।

श्री उपाध्यक्ष---समय समाप्त ।

श्रीमती बृजरानी मिश्र (जिला कानपुर)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा निर्माण मंत्री जी को बधाई देना चाहती हूं । निर्माण का हमारे देश में बड़ा अभाव है और जो अनुदान रखा गया है उसमें पैसा बहुत कम है । मैं अपने जिले की और तहसील की बात कहना चाहती हूं कि हमारे यहां पहली पंचवर्षीय योजना में तीन सड़कें मंजूर हुई थीं । इसमें एक चौबेपुर-बेला रोड है । कानपुर से इटावा को जाती है उस पर कुछ काम हुआ है । एक बात और यह कहना चाहती हूं कि इससे पहले बोलने वाले भाई ने यह कहा कि भाई बिल्लौर तहसील में जिला कानपुर में उसी जगह काम हुआ है जहां से कांग्रेसी जीत कर आये । मैं आपको बताऊं की अकबर-पुर तहसील में सेंगर नदी पर पुल भी बन रहा है । जो निर्माण-पुस्तिका है उसमें मैंने देखा । आशा है कि माननीय मंत्री जी उसको जल्दी से जल्दी बनवाने की कोशिश करेंगे । हमारी यह सड़क पहली पंचवर्षीय योजना में मंजूर हुई थी । उस पर कुछ काम हुआ है । बाकी जो बिल्लौर-रसूलाबाद को सड़क जाती है उस पर मिट्टी पड़ गई है और एक पुलिया पूरी हो गई है। परन्तु अभी वह बाकी है । यह भी सड़क पहली पंचवर्षीय योजना में मंजूर हुई थी । हमें मालूम हुआ है कि १९५७-५८ में जो कटौती हो गयी थी वह भी वापस आ गयी है । इसको पूरा किया जाय । बिल्लौर तहसील में मकनपुर जाने वाली छोटी सी तीन, चार मील सड़क है । यह भी पी० डब्लू० डी० की है और काफी खराब है । तो हम चाहते हैं कि इस सड़क की माननीय मंत्री जी मरम्मत करवा दें ।

मकनपुर में एक बहुत बड़ा मेला होता है, जो उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा मेला है । यहां काफी संख्या में लोग आते हैं, ट्रकें और जानवर भी बहुत आते हैं । तो ऐसी हालत में मैं मंत्री जी से मांग करूंगी कि हमारी इस सड़क की जल्द से जल्द मरम्मत करवा दें । इससे आने जाने में और व्यापार में भी बड़ी सुविधा होगी। दूसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि फर्रुखाबाद जिले में तिरवा से लेकर मकनपुर और वहां से असालगंज और बेला रोड को मिलाती हुई एक सड़क है इसको भी सरकार अगर ले ले और तीसरी पंचवर्षीय योजना में रख ले तो इटावा, फर्रुखाबाद और कानपुर तीनों जिले मिल जायेंगे । इससे भी आने जाने की बहुत सुविधा हो जायगी और व्यापार का रास्ता सुगम हो जायगा । एक बात और यह कहनी है कि हमारे बहुत से भाई यह कहा करते हैं कि बनारस के घाट बनवा दिये गये इसलिये कि वहां से बहुत से मिनिस्टर आते हैं । हमको, आपको गर्व होना चाहिये कि किसी जगह कोई रहने लगे तो वह जगह उसकी नहीं हो जाती । वह जगह उन महान आत्माओं की है जो कि हरिश्चन्द्र ऐसे महान व्यक्ति वहां पैदा हुये और जिनकी वजह से कि वह जगह अमर हुई । इसी तरह से हमारे बिठूर में भी नानराव पेशवा साहब हुये हैं । मैं चाहती हूं और हमारे जिले के सब लोगों की मांग है कि बिठूर से लेकर बेला रोड तक सड़क बना दी जाय । इसे अगर मंत्री महोदय मंजूर कर लेंगे तो बड़ी कृपा होगी । (व्यवधान) मकनपुर तो मैंने पहले भी कह दिया । जो मैं भूल जाऊं उसे अवस्थी जी कह देंगे । तो मैं चाहती हूं जनता की सबसे बड़ी मांग है कि बिठूर से चौबेपुर-बेला रोड को बना दिया जाय क्योंकि उसका बहुत बड़ा महत्व है । एक तो वहां के महान नेता जो हुये हैं उनकी वजह से और दूसरे साल में दो मेले भी होते हैं । इसलिये इस सड़क को जो कि आठ-सात मील के करीब पड़ेगी, मंत्री जी ले लें तो बड़ी दया होगी ।

वैसे तो हमारे यहां बहुत कुछ मंजूर है, लेकिन काम बहुत कम हुआ है । हमारे जिले में एक, दो बड़ी सड़कें पहले से हैं, लेकिन हमारे जो जिले पिछड़े हुये हैं जैसा कि अभी फतेहपुर का जिक्र किया गया, मैं भी मांग करती हूं कि मंत्री जी उन पिछड़े हुये जिलों को लें । फतेहपुर भी एक ऐसा जिला है जहां बाढ़ भी आती है, कुछ सिंचाई के साधन भी नहीं हैं । तो इस तरह के

[श्रीमती बूजरानी मिश्र]

जो भी पिछड़े हुये जिले हैं जहां कुछ भी काम नहीं हुआ है, नयी सड़कें जो ली जायं वह पहले वहीं ली जायं । जो मंजूर हैं उन्हें तो पहले करना ही है और हमारी प्रार्थना है कि पहले उनको किया जाय । नयी जब ली जायं तो उन जिलों में ली जायं जहां कि बिलकुल काम न हुआ हो । तो मैं इतना ही कहना चाहती हूं क्योंकि हमारी और भी बहनें कुछ कहना चाहती हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—श्रीमती कैलाशवती । आप लोग इतनी ज्यादा सड़कें गिना देती हैं कि पैसा ही नहीं रह जाता ।

श्रीमती कैलाशवती (जिला गोरखपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी से कुछ अनुरोध करना चाहती हूं । हम बाढ़ क्षेत्र के रहने वाले हैं । वहां के लोग बड़ी मुसीबत में रहते हैं । वहां जो बांध बन रहे हैं और श्रमदान से जो सड़कें बन रही हैं उन पर भी माननीय मंत्री जी का कुछ ध्यान होना चाहिये । मंत्री जी ध्यान तो देते हैं, लेकिन गरीब जनता की तरफ उनका ध्यान कम जाता है अमीर लोगों की तरफ ज्यादा जाता है । आजकल सब तरफ चहल-पहल यही रहती है कि गांव की तरफ चलें, लेकिन गांव की तरफ जायं कैसे ? रास्ता है नहीं जाने का, कोई साधन है नहीं । तो हम तो उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा यही अनुरोध करते हैं कि गांव के मार्ग बनावें जिससे हमारे मंत्री महोदय भी वहां पहुंचे और गांवों की दशा को देखें कि वहां के लोगों की क्या हालत है, कैसे गांव में लोग रहते हैं । कुछ जिक्र हमारी तहसील का पांडेय जी ने किया । बांसगांव तहसील इतनी भारी है कि एक जिले के बराबर है । बड़ी घनी आबादी है और बड़ी गरीबी है । वहां इतनी गरीबी है कि हम बार-बार उसका क्या जिक्र करें । हम उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मंत्री जी से यह अनुरोध करते हैं कि बाढ़ के इलाके में भी यातायात का साधन होना चाहिए और मइहरपुर से बैरियाघाट तक एक सड़क का साधन कर दिया जाय तो अच्छा होगा । वहां के लोग बीमार पड़ते हैं तो दवा नहीं मिल सकती । बाढ़ के दिनों में जब बाढ़ आ जाती है तो बड़हलगंज में दियासलाई, खाने-पीने के साधन और जरूरी चीजें नाव द्वारा पहुंचाई जाती हैं । अगर उस पार नाव है तो इस पार लोग ताकते रहते हैं । अगर यातायात के साधन हो जायं तो लोग अपनी झोंपड़ी डालकर अपना बसर कर लें । तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करती हूं कि उस बाढ़क्षेत्र की ओर भी थोड़ा ध्यान देने की कृपा की जाय और आपके द्वारा माननीय मंत्री से उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रार्थना करना चाहती हूं कि उन गांव वालों की ओर अधिक ध्यान देने की कृपा करें । बस, मुझे और नहीं कहना है ।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय बंशीधर शुक्ल । लेकिन दो ही मिनट में आप खास-खास सड़कें गिना दें ।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—लखीमपुर में सिर्फ (३०) तीस सड़कें अंग्रेजी सरकार ने निर्माण कराई थीं और वही हैं । वह सड़कें क्या गलियारा हैं । तीन नदियां और तीन पक्की सड़कें हैं । बरसात में इतनी मुसीबत होती है कि बस जय भारत माता की याद आती है । तो हमारा कहना है कि आप यानी सरकार ३५ हजार रुपया एक मील कंकड़ की सड़क में खर्च करते हैं और तारकोल में ५५ हजार एक मील पर और सीमेन्ट की सड़क पर १ मील में ७५ हजार खर्च करती हैं । तो इस तरह से सरकार सड़कें नहीं बनवा सकती । बेकार का परिश्रम है । आप सड़कें अगर बनवाना चाहते हैं तो देहात की पंचायतों द्वारा बनवायें । आज आठ मुहकमें सड़कें बनवाते हैं । केन सोसाइटी भी बनवाती है, सार्वजनिक निर्माण विभाग भी बनवाता है और गांव की पंचायतों में श्रमदान भी होता रहता है । जिला बोर्ड बनवाता है । मगर सब एक ठेकेदार को ठेका देते हैं अपने आप नहीं । वह गरीब मजदूरों से, बिना पढ़े-लिखे लोगों से सड़क बनवाता है और उस ठेकेदार से आपके

यहां के लोग मुनाफा में हिस्सा लेते हैं। तो क्या इस तरह से सड़कें आप बनवा पायेंगे ? अगर आपको सड़क बनवाना है तो देहात के लोगों से बनवायें। अपनी अफसरावली या ठेकेदार से नहीं।

यह क्या जरूरी है कि हमारे जिले में जितनी सड़कें हैं वह पी० डब्लू० डी० की तरफ से बनाई जायं। वे तो हमारे यहां मेहमान-गृह बनाया करते हैं और उस पर ६३ हजार रुपया फी हाउस खर्च किया गया है। सड़क बनाने के नाम पर बिल्कुल खर्च नहीं हुआ है। माननीय मन्त्री जी ने कहा कि हम दो सड़कें वहां पर बनाने की सोच रहे हैं और इसी योजना में वे निर्माण होने को हैं मगर अभी तक एक भी नहीं बनीं। ७ मील सड़क इस वर्ष बनने की बात है जो पिछली प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बनी थी। आज हम देखते हैं कि इस द्वितीय योजना के अन्तर्गत उस पर मिट्टी पड़ी है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में उस पर कंकड़ डाले जायेंगे। जब तक यह काम होगा वह मिट्टी भी बह जायगी। हम तो यह कहते हैं कि आप इस विभाग को ही बन्द कीजिये और जनता से जो यह रुपया मांग रहे हो उसको वापस कीजिये। जनता अपने आप सड़कों का निर्माण अपनी जरूरत के अनुसार कर लेगी। आप चुपचाप बैठे रहिये। जनता से जाकर माफी मांगिये कि हमसे गलती हो गई और यह काम गलत हो गया जो हम कर नहीं पा रहे हैं। श्रीमन्, जितना भी पैसा किसी काम के लिये दिया जाता है उसको अफसर खा जाते हैं। सड़क बनाने के लिये श्रमदान मांगने चलते हैं:—

आज दान मांगने की उठी है विकट आन्धी,
सभी मुफ्त खोरे चले मांगने विविध दान।
कोई धन दान, पशुदान, पिन्ड दान मांगे,
कोई टैक्स दान, चन्दा दान, कोई भूमि दान।
कोई लिये पिस्टल गली में मांगे प्राणदान,
कोट, ओट दान, नोट दान, गला घोंट दान।
श्रमी दीन देश की डकार के कसाई आज,
सारे शर्म हीन चले मांगने शरम दान।

इसलिये मंत्री महोदय से मैं प्रार्थना करूंगा कि आपने जो निर्माण विभाग का काम अपने हाथ में लिया है उससे जिलों में मेहमान गृह का निर्माण न कराइये जैसा कि सम्पूर्णानन्द नगर बसाया गया है।

अब मैं थोड़ा-सा निवेदन अपने जिले की सड़कों के बारे में भी करना चाहता हूं। एक सड़क मैलानी से खुटार तक बनने को है। वह खुटार में २० फीट चौड़ी और सरकारी जंगलों में है। ३० फुट चौड़ी तो वह जंगल में वन विभाग में है इसलिये जब वह किसानों के खेतों में से गुजरी तो वहां पर १०० फुट चौड़ी हो गई और जब वह मैलानी बस्ती में आई तो वहां पर ६० फुट चौड़ी हो गई। उसके लिये वहां पर १४ दुकानें उखाड़ी जा रही हैं। मैलानी की रौनक को खत्म किया जा रहा है। इसके लिये लोगों ने दरख्वास्त दी, लेकिन कोई भी उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। एक सड़क रोशन नगर से खुटार को जा रही है। रोशननगर बस्ती में सड़क को पक्की करने के लिये मकान गिराये जा रहे हैं। यह क्या हो रहा है ? मैंने पिछले साल भी कहा था विजुवा, भीरा रोड, मझगई रोड बनवाया जाय मगर उसको बनवाया नहीं गया। कहा जाता है कि रुपया नहीं है। अगर इस ठेकेदारी सिस्टम को समाप्त कर दिया जाय तो फिर बहुत पैसा बच सकता है। इन ठेकेदारों के

[श्री बंशीधर शुक्ल]

द्वारा सड़कें नहीं बन सकती हैं । आपने १०० गांवों में विकास के लिये १२ लाख रुपया रक्खा है उसमें सवा चार लाख नौकरों के मकानों के लिये रखे हैं बाकी आधा रुपया तो सरकारी नौकरों की चाय, रिश्वती जेबों, भत्तों में चला जाता है या उनके मकान बनाने के लिये खर्च कर दिया जाता है । कुछ ठेकेदार के लिये निकल जाता है । आखिर में जाकर बहुत थोड़ा काम हो पाता है ।

वैल से बैहजम के लिये ५, ७ मील लम्बी एक सड़क बनाई गई है पर शायद ही उस पर कोई सवारी जाती हो । वन विभाग की सड़कों पर कोई चलने ही नहीं पाता । एक सड़क भीरा से लखीमपुर की जरूरत है पर वह बनाई नहीं जा रही है । हमारा कहना है कि यह सड़क किसानों के लिये बहुत लाभदायक है । इसके बनने से उनकी बहुत खिदमत हो जायगी । एक सड़क १२० मील लम्बी है जो पलिया-टिकैतनगर से मजगई तक जाती है । यह प्रान्तीय सरकार की है । वहां शारदा नदी पर पुल नहीं है । शारदा के पार सारे गांव बरसात के दिनों में पानी से घिर जाते हैं । कोई वहां पर पहुंच नहीं सकता है और आज भी वहां पर जाने की कठिनाई है । इस वजह से हमारे जिले की तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिये क्योंकि हमारा जिला नेपाल के करीब का जिला है जहां पर जंगल ५ लाख एकड़ जमीन में लगे हुये हैं । उस जंगल के जानवर हमला करते हैं, डाकू हमला करते हैं । ऐसी दशा में हमारे जिले की तरफ विशेष ध्यान होना चाहिये । ३०० मील लखनऊ से महमूदाबाद सेडला रेंउसा तम्बौर मल्ला पर कटौली ईसानगर-निघासन-पलिया होकर टनकपुर से हलद्वानी तक जाती है । अंग्रेजी जमाने की बनी हुई है जो टिकैत नगर रोड कहलाती है । हमारा निवेदन यह है कि शारदा नदी पर पुल बनाया जाय । हमारे जिले में घाघरा नदी पर भी पुल बनाने की जरूरत है । बरसात के दिनों में बहुत परेशानी होती है । अगर इसका पुल बन जाय तो हमारे जिले के लिये बहुत बड़ा काम हो जाय । अच्छी पैदावार भी वहां पर होने लगे । नैपाल से मिले हुये जिले को इस उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिये । लाखों मन धान नैपाल से आता है और अगर वहां यातायात की सुविधा हो जाय तो काफी अच्छा काम हो सकता है । व्यापार चल सकता है तो कुदरत की कृपा है कि उधर चोरी कम होती है । जैसी चोरी यहां होती है वैसी वहां हो तो फिर रहना कठिन हो जाय यहां का जुल्म देख कर तो यही कहना पड़ता है कि जय भारत माता की जय । इसलिये मंत्री महोदय से उपाध्यक्ष जी के द्वारा प्रार्थना है कि हीरा रोड और मजगुई रोड पर आपका ध्यान सब से पहले जाना चाहिये और ठेकेदारों द्वारा जो सड़क बनाने की बात है उसको बन्द कर देना चाहिये ।

श्री इन्दुभूषण गुप्त—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने इस कटौती के प्रस्ताव में भाग लिया है, मैं उनका आभारी हूं । चाहे वह सदस्य इधर के हों अथवा उधर के, सभी ने इस बात को एक स्वर से स्वीकार किया है कि इस विभाग में जो कार्य हो रहा है उसकी प्लानिंग डिफेक्टिव है । मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता और उस भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहता कि जो यहां प्रयुक्त हुई है, लेकिन एक शब्द में कहूंगा कि प्लानिंग डिफेक्टिव है । मैंने अपने कटौती के प्रस्तावों के द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया था कि वह कौन-सी कमियां विभाग में हैं और अगर उनको दूर कर दिया जाय तो इस विभाग का संगठन और काम और पायेदार हो सकता है । सरकार की तरफ बैठने वाले वक्ताओं ने बनारस के घाटों का उदाहरण दिया और इस विभाग द्वारा किये गये और बहुत से निर्माण कार्यों की प्रशंसा की । मैं भी एक दो उदाहरण आप के समक्ष रखना चाहता हूं । क्या यह बात सरकार के विचार करने की नहीं है कि बनारस में जो निजी घाट बनते हैं धर्मार्थ, जैसे बिड़ला जी ने तुलसीघाट बनवाया, उसकी पायेदारी को वह देखे और उसे अपने द्वारा बनवाये गये घाटों से मुकाबला करे । वहां पर जो नहाने की सुविधा है, स्नान करने वालों को क्या वैसी ही सुविधा सरकार की ओर से बनने वाले घाटों

पर मिलती है ? आप देख लीजिये । पाये गल भी रहे हैं और ढह भी रहे हैं । मैटीरियल, लेबर, मजदूरी सब वहीं लग रहा है, लेकिन जो काम जनता के पैसे से होता है उसका नक्शा देखिये और जो एक व्यक्ति अपने पैसे से धर्मार्थ कर रहा है उसका नक्शा देखिये । तो क्या यह प्रशंसा की बात है ? क्या यह गंभीरतापूर्वक विचार करने की बात नहीं है ? जो व्यक्तिगत आक्षेप किये गये उनका उत्तर उसी क्वायन में देना हम लोगों की परम्परा नहीं है और इसके लिये आप मुझे क्षमा करेंगे । एक माननीय सदस्य के लिये कहा गया कि कुत्ता रखे हैं, चूंकि वे ताल्लुकेदार हैं इसलिये गरीबों के लिये बोलने के अधिकारी नहीं है । मैं तो कहता हूं कि जमींदार और ताल्लुकेदार ही गरीबों के लिये बोलने के अधिकारी थे । चूंकि उन्होंने बीच में बोलना छोड़ दिया था इसलिये जनता से उनका सम्पर्क हट गया । जब उन्होंने फिर बोलना शुरू कर दिया तो जनता ने उनको फिर अपना लिया और आपको ठुकरा दिया । इस बात का सारा नक्शा आपके सामने है ।

दूसरी बात मैं आपके समक्ष यह रखना उचित समझूंगा कि जो भी काम विभाग की ओर से हो वह सोच समझकर किये जायें । इस समय सदन में ज्यादा बात सड़कों के लिये कही गयी और सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि सारे प्रदेश में हमने विकास नहीं किया है और ऐसा नहीं है कि जितनी जरूरत थी वह सब हमने पूरी कर दी है । यह सही है कि जितना कार्य आपको करना चाहिये उतना आपने नहीं किया और कोई भी काम जब आपको करना होता है तो आप उसके लिये जबरदस्ती कर बैठाने लगते हैं । कहते हैं साहब हमको इसकी जरूरत है, लेकिन हम इस बात को भी देखते हैं कि जो महत्वपूर्ण और आवश्यक कार्य हैं वह नहीं होते बल्कि जो धन कर लगाकर आज आप जनता से उगाही कर रहे हैं वह कई गुना ज्यादा कर रहे हैं और वह ऐसी बेकार की चीजों पर खर्च कर रहे हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है । अगर आप सही ढंग से खर्च करें, जैसा कि हमारे उधर के कुछ बैठने वालों ने उदाहरण भी दिये हैं तो बहुत कुछ फायदा हो सकता है ।

इधर से कहा गया कि अच्छा सा मकान गिरा दिया गया जिसमें कि विधायक रह सकते थे और दूसरी तरफ बर्लिंगटन होटल में ढाई सौ रुपये पर कमरे लिये गये हैं और उनका विधायक निवास बनाया गया है । तो मैंने इस तरह की मोटी-मोटी बातें सामने रखकर, बिना किसी क्रिटिसिज्म के यह बताने की कोशिश की कि जो खामियां हैं उनको सुधारा जाय और जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उनको किया जाय । मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि बड़हलगंज से दोहरीघाट के पुल की बहुत जरूरत है जैसा कि बांसगांव के दो प्रतिनिधियों ने भी कहा । लेकिन उन्होंने एक बात नहीं कही और वह यह कि वहां पर रेलवे नहीं है । मेरा तो बांसगांव में इलाका था और आज भी बहुत सम्पर्क है और मैं इस बात को जानता हूं कि बांसगांव में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज तक रेल का इंजिन भी नहीं देखा है और अगर कुछ लोगों को जाना होता है तो वे दोहरीघाट जाकर के रेल पकड़ते हैं और २४ घंटे में एक गाड़ी ही मिलती है । इसलिये जो इतना महत्वपूर्ण पुल है उसका आप निर्माण करें और अगर आपके पास साधन नहीं है तो कुछ समय के लिये चह की व्यवस्था करके वहां की जनता को सुविधा पहुंचावें ।

श्री गिरधारीलाल---अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का बहुत आभारी हूं कि उसने इस विभाग के विषय में बहुत से सुझाव दिये और खामियों की तरफ इशारा किया । और कुछ अपने-अपने क्षेत्रों की सड़कों या पुलों की बात कही । जहां तक ऐसी चीजों का सम्बन्ध है, जैसाकि मैंने कल कहा था और आज भी दोहराये देता हूं कि उनको नोट कर लिया गया है और अगर वे दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर नहीं हैं तो तीसरी योजना में उनके लिये विचार किया जायगा ।

[श्री गिरधारीलाल]

जहां तक और सुझावों का सवाल है उसमें बहुत सी बातों का जवाब कल ही दे चुका हूं, लेकिन दो-चार ऐसी बातें हैं जिनके बारे में मैं कुछ कह देना जरूरी समझता हूं । एक तो यह इशारा किया गया कि कंकड़ की सड़क को तारकोल की सड़क और तारकोल की सड़क को सीमेन्ट की सड़क बना दिया जाता है तो मैं समझता हूं कि कोई भी इस स्थान पर इस तरह से काम करने वाला होगा उसको इसी तरह से काम करना होगा क्योंकि सबसे पहले किफायतशारी की तरफ देखना है । कंकड़ की सड़क मजबूत नहीं होती क्योंकि आजकल बड़ा हैवी ट्राफिक, मर्सीडीज ट्रक्स चलती हैं दो-तीन सौ मन का बोझा लेकर, इसलिये चार छः महीने में वह सड़क पर धूल और गर्दा पैदा कर देती हैं और सड़कों की जिन्दगी बड़ी जल्दी खत्म हो जाती है । इसलिये अगर उस पर तारकोल का प्लास्टर हो जाता है तो वह मजबूत हो जाती है । कंकड़ की सड़क पर एक वर्ष नहीं तो दूसरे वर्ष जरूर फिर से कंकड़ डालना पड़ता है, लेकिन पत्थर की सड़क तीन साल तक तो बगैर किसी रोक टोक के चलती है और उसके बाद जैसी हालत होती है उसके अनुसार पेंटिंग की जरूरत पड़ती है । एक्सपर्टस की सलाह है कि उनकी १५ साल की लाइफ होती है । और सीमेन्ट की सड़कों के सिलसिले में मैं दो एक बातें कहना चाहता हूं । मैं समझता हूं कि इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ख्वाहिश होगी कि सारे प्रान्त में सीमेन्ट की सड़कें बन जायं क्योंकि उनकी लाइफ लगभग १०० वर्ष की होती है, न किसी सफाई की जरूरत है और न रिपेयर्स की । एक दफा बना दीजिये, हमेशा के लिये हो जाती है । लेकिन उसमें बहुत काफी पैसे की जरूरत है जो इच्छा होते हुये भी हम नहीं कर सकते । कहीं किसी शहर के बीच में से जहां ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो या नेशनल हाई वे पर किसी-किसी स्थान पर एकाध मील का टुकड़ा बना दिया गया हो तो वह दूसरी बात है । लेकिन आम तौर पर सीमेंट की सड़कें नहीं बनाई जा रही हैं । बजट लिट्रेचर में पढ़ा होगा कि सीमेंट के कुछ कंक्रीट ट्रैकवेज बन रहे हैं । चीनी के कारखानों के इलाकों में डेवलपमेंट काउन्सिल की ओर से कुछ टैक्स होते हैं, पटरियां दोनों ओर होती हैं जिन पर गाड़ियां सामान ले जाती हैं, तो अगर कंकड़ की सड़कों पर तारकोल या पेंटिंग हो गया तो वह स्टेट के पैसे की रक्षा के खयाल से तो अच्छी बात हुई है ।

श्री इन्दुभूषण जी ने कुछ अच्छे सुझाव दिये और मैं समझता हूं कि उन्होंने काफी विचारा है । उनका सबसे पहला सुझाव नान-लैप्सेबिल ग्रान्ट्स के संबंध में था । विभाग इस प्रश्न पर काफी अर्से से विचार कर रहा है और वित्त विभाग इत्यादि का जो अंतिम फैसला होगा वह सब लोगों के सामने आवेगा । लेकिन फिर भी जहां तक सड़कों की बात है इनमें २,३ वर्ष से कोई विशेष लैप्स नहीं हो रहा है । रही इमारतों की बात । यहां मैंने आम हवा यही पाई कि सड़कें हमारे शरीर की नसें हैं जिनमें खून चलता है और उनकी बहुत जरूरत है और यदि इमारतों को टाल दिया जाय तो कोई बात नहीं । ऐसी सूरत में अगर इमारतों में लैप्स हो गया, तो उस पर ज्यादा एतराज नहीं होना चाहिये । यद्यपि उसमें और भेद हो सकते हैं जिनमें मैं इस वक्त जाना नहीं चाहता ।

एस्टीमेट्स के लिये कहा गया कि वे गलत बनते हैं और बढ़ जाते है । आजकल का आम स्वभाव है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाती है, ६ महीने या सालभर के बाद कंकड़, पत्थर, सीमेंट, लोहे वगैरह की कीमतें बढ़ने से एस्टीमेट्स भी बढ़ सकते हैं । एक सुझाव यह भी दिया गया कि एस्टीमेट्स बिलकुल ठीक होने के लिये एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाई जाय । जैसा मैंने कल भी बतलाया था, हमारे एस्टीमेट्स शुरू में रफ बनते हैं । बजट से तो हम केवल मंजूर करते हैं और उसके बाद डिटेल्ड एस्टीमेट तैयार होता है । हमारे गोविन्द सिंह जी ने कहा था कि डिटेल्ड ऐस्टीमेट्स पहले तैयार कर दिये जावें । हर एस्टीमेट्स के तैयार करने में वहां पर सर्वे करने के लिये लोगों को भेजना और ऐसे ही कामों में ४००–५०० रुपया फी मील खर्च हो जाता है । जब तक एक चीज

पहले निश्चय न हो जाय उस वक्त तक डिटेल्ड ऐस्टीमेट नहीं बन सकता है । हम यहां, गवर्नमेंट लैविल पर, टैक्निकल सैल कायम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि उससे इन चीजों में भी हमें काफी सहायता मिलेगी ।

इसके अलावा एक बात, वैसे कोई खास बात नहीं है और है भी, लेकिन यह कहा गया कि तीन-तीन सौ वर्षों की पुरानी इमारतें आज भी खड़ी हैं और जो इस वक्त की इमारतें हैं वे गिर रही हैं । मैं इस बात से सहमत हूं, लेकिन क्या तीन-तीन सौ वर्ष पुरानी सभी इमारतें जो कि उस वक्त बनी थीं हमारे देश के अन्दर सब की सब मौजूद हैं ? कुछ खास प्रकार की वे इमारतें होंगी, जैसे गोमती के किनारे एक-दो खास इमारतें आज भी बनी हैं और गोमती के किनारे जो हमारा मेमोरियल बना हुआ है वह भी हजारों वर्ष तक चलेगा, बहुत काफी अर्से तक चलेगा । इस तरह की बहुत सी इमारतें हो सकती हैं जो खास तौर पर बनायी जाती हैं और जिनका खासतौर पर ध्यान रखा जाता है कि वे बड़े एजेज से गुजरेंगी । बाकी जो बहुत सी इमारतें होती हैं उनकी लाइफ ५० साल, १०० साल की होती है और उसी तरीके से वे चलती हैं, लेकिन हमारा मतलब यह नहीं है कि जो गलत बात हुई उसको भी हम डिफेंड कर रहे हैं । कुछ ऐसी खामियां हो जाती हैं, कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से जैसा कि कहा गया कि किसी मकान की छत गिर पड़ी या और इस तरह की जो चीजें होती हैं उनकी काफी छानबीन की जाती है और जो उचित कार्यवाही होती है वह सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी या ठेकेदार के खिलाफ की जाती है ।

कुछ इस तरह की बात भी कही गयी कि पी० डब्ल्यू० डी० के सरकारी कर्मचारी ने किसी के साथ बदतमीजी का व्यवहार किया । मुझे अफसोस है कि उसी वक्त मेरे पास पत्र लिखकर इसकी सूचना नहीं दी गयी ....

श्री इन्दुभूषण गुप्त---उसी वक्त आपको पत्र मैंने लिखा था जिसका आप के यहां से जवाब गया है कि उस पर कार्यवाही हो रही है ।

श्री गिरधारीलाल---अगर आपने पत्र लिखा था तो मैंने उस पर कुछ कार्यवाही की होगी । जैसा कि आप कह रहे हैं कि जवाब गया है कि कार्यवाही हो रही है तो जरूर उसके ऊपर कार्यवाही हुई होगी और फिर मैं उसको देखूंगा । लेजिस्लेचर ही नहीं बल्कि तमाम जनता के साथ सरकारी कर्मचारियों का बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिये क्योंकि उनको एक अच्छी मिसाल समाज के अन्दर कायम करनी है ।

हमारे दूसरे भाई श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी ने जहां और कई बातें कहीं वहां उन्होंने ठेकेदारी प्रथा के सिलसिले में भी कहा था । मैंने कल ही उसका खास तौर पर जवाब दे दिया था कि आप इस पर अच्छी तरह से विचारें कि आज की वर्तमान स्थिति के अन्दर सरकारी तौर पर ही काम हो सकता है जिसको स्टेट मैनेजमेंट या डिसइंटरेस्ट सिस्टम कहा करते हैं । तो डिसइंटरेस्टेड सिस्टम के अन्दर आज जितना खर्चा होता है दूसरे तरीके से और भी ज्यादा खर्चा हो सकता है, इस पर हम लोगों को पहले अच्छी तरह से सोच कर कोई कदम उठाना है । यह हो सकता है कि १४ करोड़ का काम सूबे में लगा हुआ है तो हम पहले ५० हजार या एक लाख का काम दूसरे तरीके से करा कर देखें और आहिस्ता-आहिस्ता उधर आगे बढ़ सकें तो इस तरह की चीज हो जायगी कि हम सबकी सहायता सभी कामों में ले सकें ।

[श्री गिरधारीलाल]

एक बात श्री ब्रजनारायण तिवारी जी ने बोर्डर एरिया के सिलसिले में कही कि सरकार को इस तरफ ध्यान रखना चाहिये। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार का ध्यान उस तरफ है और जो भी काम हो सकते हैं वह किये जा रहे हैं या जो कुछ भी वहां पर होगा, वह सब सदस्यों के सामने और सदन के सामने आ जायेंगे।

एक बात देहली आवासगृह के सिलसिले में कही गयी। श्रीमन्, जब मैंने बहुत से जिलों का दौरा किया तो मेरा व्यक्तिगत तजुर्बा है कि यह कोई इस प्रकार से रहने के मकान की बात नहीं है। मेरे कई सरकारी साथियों ने और दोस्तों ने इस बात की शिकायत की कि फलां कर्मचारी, फलां आफिसर, फलां बड़े आदमी के घर पर ठहरे, फलां सेठ के घर पर ठहरे। उसको नहीं ठहरना चाहिये था। मैं उनकी उस बात से सहमत हूं। मैंने जानने की कोशिश की। उन्होंने यह बतलाया कि इस इलाके में हमारे पास कोई स्थान नहीं है जहां जाकर ठहर सकें। दौरा करना जरूरी है। उस वक्त मैं समझा कि हमको हर इलाके में ज्यादा से ज्यादा डाक बंगलों की जरूरत है, क्योंकि ठहरने के लिये अच्छे स्थान की आवश्यकता होती है। तो ऐसी चीजों पर हमको एतराज नहीं करना चाहिये। हो सकता है कि बहुत से साथी उधर के हैं उनके सुपुर्द सरकारी काम किया जाय और वे वहां जायं तो उनको भी दिक्कत हो सकती है। फिर शिकायत हो सकती है कि फलां आदमी के यहां वे ठहरे, सेठ के रिश्तेदार थे या सेठ थे, लेकिन स्थान बनवा देने से यह दिक्कत दूर हो जाती है। एक जिले में मैं गया। मेरे बहुत से साथियों ने जोर दिया कि फलां जगह ठहरूं। मैंने कहा नहीं, फलां स्थान पर ठहरूंगा। ६ करोड़ नागरिकों के टैक्स से जो भवन निर्माण हुआ है उसमें ठहरूंगा, उसका अहसान मेरे ऊपर होगा और वहां ठहर कर मैं हर दल के व्यक्ति से स्वतंत्र रूप से मिल सकूंगा। इसलिये मेरा कहना है कि यह छोटी-छोटी बातें हैं, इन पर एतराज करना मुनासिब नहीं है। इतना लम्बा चौड़ा बजट है। इतना लम्बा-चौड़ा एरिया है। वहां हर स्टेट अपने-अपने मकानों को बना रही हैं।

तिरमल सिंह जी ने एटा के सम्बन्ध में कहा कि उनका जिला पिछड़ा हुआ है। ऐसे इलाकों का पूरे तौर पर खयाल रखा जाता है और ये चीजें मैंने नोट कर ली है और उन पर ध्यान दिया जायगा।

डिजाइन्स के बारे में कहा कि अमेरिकन डिजाइन या यूरोपियन डिजाइन के मकान बन रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमें एक स्वतंत्र रूप से चलने की जरूरत है। स्वतंत्र रूप के यह मानी है कि जो डिजाइन अच्छा हो उसे लेना चाहिये और जो अच्छा न हो उसे नहीं लेना चाहिये। बहुत सी बातें हमारे देश की बहुत अच्छी है उन्हें अख्तियार करना चाहिये। इसी तरह से स्वतंत्र रूप से हर स्थान के डिजाइनों को देखा जाता है और उनमें से कुछ स्टैंडर्ड कायम करते हैं, उनके हिसाब से भवनों का निर्माण किया जा रहा है।

श्रमदान की सड़कों के सम्बन्ध में कहा गया। ये सड़कें सूबे में ४० हजार मील हैं। अभी तो भवन व सड़कों के निर्माण के लिये १४ करोड़ रुपये के अनुदान के लिये हमें काफी दिक्कत होती है तो उनके लिये तो करीब दो अरब रुपये की जरूरत होगी। श्रमदान की सड़कों में से ५८० मील सड़कें हमने ली भी हैं। इस प्रकार की सड़कों को सार्वजनिक निर्माण विभाग ने लिया है। १४–१५ लाख रुपया उन पर हर साल खर्च होगा। बाद में पैंटिंग होगी, रखरखाव होगा। ४० हजार मील श्रमदान से बनाई गयीं यह बड़ी तारीफ की बात है। गांव के वे भाई जो कल तक हल पर हाथ लगाना अपनी शान व धर्म के खिलाफ समझते थे आज वे श्रमदान से मिट्टी डाल रहे हैं और सड़कें निर्माण कर रहे हैं यह बहुत ही सराहनीय है, लेकिन यह ठीक है कि पी० डब्लू० डी० की सड़कों जैसी वे नहीं हैं। ये सड़कें काफी ऊंची हैं, ड्रेनेज का इन्तजाम है। पहले इन सड़कों को श्रमदान की उस लेविल पर लाना है उसके बाद फिर पक्की करना है। इन तमाम बातों के लिये काफी धन की जरूरत होगी जो इस वक्त वर्तमान स्थिति के अन्दर हमारी शक्ति के बाहर है। एक बात प्रायरिटी के सिलसिले में कही गई।

जिस वक्त धन की कमी है और काम बहुत ज्यादा हो तो, जितने लोग यहां पर बैठे हैं वह सब समझदार हैं कि काम प्रायरिटी के हिसाब से ही करना पड़ रहा है। हर डिस्ट्रिक्ट में देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट में भी हर स्थान पर देखते हैं कि सबसे पहले कौन–सी सड़क हैडक्वार्टर से तहसील को जोड़ती है। फलां इलाके से जोड़ती है और इस तरीके से उस इलाके का आर्थिक विकास होगा। इन तमाम बातों का खयाल रख कर प्रायरीटी रक्खी जाती है।

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सड़क के बारे में कहा गया। उसकी भी एक कहानी है। उसमें से करीब २,४०० मील सड़क पहली योजना के अंदर ले ली गई थी और कई सौ मील इस वक्त ली गई है। १,७०० मील बाकी थी जिसमें से ३०० मील इस योजना के अन्दर पूरी की जायेगी। विभाग लेकर अपने पास रक्खेगा और जैसे विभाग की अपनी सड़क है उन्हीं लाइन्स पर रक्खेगा। बाकी सड़कों के लिये धन की उपलब्धि के हिसाब से फिर उस पर विचार किया जायगा।

ओवरसियर्स वगैरह के सिलसिले में कहा गया। मैं उस बात से सहमत हूं। जितनी ही आर्थिक दशा लोगों की सुधरती है, जितनी लोगों की दिक्कतें दूर होती हैं, उनकी मांगों की पूर्ति होती है, उतना ही भ्रष्टाचार खत्म हुआ करता है। हमारे हिन्दुस्तान में समाज में काफी डिसपैरिटी बहुत से किस्म की है। गरीब और अमीर के अलावा और भी बहुत सी बातें हैं। उन तमाम बातों का असर खराबियों के ऊपर पड़ता है जिनका जिक्र होता है, जिनके लिये हमारे दोस्त भी परेशान रहते हैं। एक मिसाल दी गयी कि ओवरसियर को १२५ रुपये के बजाय २५० रुपया दिया जाय। मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूं, लेकिन हमें पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को देखना होगा। जिस वक्त हम देखेंगे तो नीचे के और ऊपर के लोगों को भी देखना होगा। फिर भी यह देखना होगा कि जिस मर्ज का यह इलाज बताया जा रहा है, वह ठीक भी हो जाएगा। वह इलाज ठीक भी रहेगा या नहीं। अगर वह मर्ज वैसा ही रहता है और रुपया भी खर्च हुआ तो उससे कोई फायदा नहीं।

मैं उन चीजों में नहीं जाना चाहता। हमारे बहुत से साथियों ने गवर्नमेंट को बहुत से मामलों में उपदेश भी दिया। उनका उपदेश शिरोधार्य है, लेकिन वह समझें कि बहुत ऐशो–इशरत के साथ जिन्दगी काटते हैं, तो इस बात को हमारे सब साथी जानते हैं।

शिड्यूल आफ रेट्स के सिलसिले में कहा गया कि उसमें समानता होनी चाहिए। हमें उसमें यह देखना है खास तौर पर कि एक तरफ शिकायत होती है कि काम कमजोर है और दूसरी तरफ इस प्रकार की डिसपैरिटी है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जो शिडयूल रेट्स हैं, म्युनिसिपल बोर्ड के हैं, टाउन एरिया के हैं, पंचायतों के हैं, वह कम होंगे। जैसी उनकी शक्ति है और काम है। गांव की सड़क पर ज्यादा हैवी ट्रैफिक नहीं होगा, लेकिन जो सड़क यहां से कानपुर जाती है कितना हैवी ट्रैफिक उसके ऊपर है? उसके लिये वैसा ही शिडयूल आफ रेटस है।

ऐसे ही इमारतों की बातें हैं। भवनों के निर्माण की बात है। इस सिलसिले में एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि भाई जगदीशप्रसाद जी ने कहा कि उनके इलाके में कोई दिक्कत आई बरसात के दिनों में और वहां पर वहां के पी० डब्ल्यू० डी० के कर्मचारियों ने सहयोग नहीं दिया। मुझे खेद है। वह अगर थोड़ा–सा कष्ट करके मेरे नोटिस में इस बात को ले आते तो मैं देखने की कोशिश करता और जो कुछ मुनासिब कार्यवाही होती उसको करता।

एक बात नान-आफीशियल एजेन्सी के सिलसिले में कही गई कि उनका पूरा-पूरा सहयोग लिया जाय। जहां तक यह बात है...

श्री उपाध्यक्ष--मंत्री जी शायद अभी दो एक मिनट और लें, इसलिये मैं घोषणा करता हूं कि जब तक अनुदान स्वीकृत न हो जाय तब तक सदन बैठा रहेगा।

श्री गिरधारीलाल--तो जहां तक नान-आफिशियल एजेन्सी के सहयोग की बात है वह तो लिया ही जाता है और हर जिले में जितने विधान सभा या संसद के सदस्य हैं या अन्य नान-आफिशियल्स हैं उनकी हर जिले में समितियां बनी हुई हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी--कभी वह कमेटियां बुलाई भी जाती हैं ?

श्री गिरधारीलाल--इस तरह से हर जिले में कमेटियां बनाई गई हैं जो कि वहां के निर्माण आदि के कामों में सलाह देती हैं।

एक बात यह कही गई कि भवनों का रुपया सड़कों की तरफ लगाया जाय। मैं यह कह चुका हूं कि हर चीज की अलग-अलग विशेषता होती है, हर चीज अपना-अपना स्थान रखती है, भवन, सड़क, एजूकेशन, खेती सब का स्थान है और सब जरूरी हैं। सभी भवन से हटा कर उधर लगा दिया जाय तो यह मुनासिब न होगा, लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने बताया कि इस वर्ष भी सवा करोड़ रुपया भवनों के निर्माण की तरफ से बचाकर और दूसरे कामों में लगाया गया है। मैं इस वक्त ज्यादा समय नहीं लूंगा।

दस करोड़ रुपये के घपले की बात कही गई, यह सुनकर मुझे बड़ी हैरत हुई कि इतना छोटा सा विभाग है दस करोड़ रुपये का इकट्ठा ही क्या घपला हो गया। पता लगाने पर मालूम हुआ कि वह एक आडिट का एतराज इस तरह का हुआ जैसे कि कुछ एस्टीमेंट्स हैं और माननीय सदस्य चाहते हैं कि काम जल्दी हो जाय और उनका समय से एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं मिला और काम पूरा हो गया और उसी पर आडिट आब्जेक्शन हो गया, इस तरह से कई साल से कुछ रुपया बढ़ा। यह केवल हिसाब की इर्रेगुलेरिटी थी और कोई बात नहीं है। कोआपरेटिव के सम्बन्ध में मैंने शुरू में ही बता दिया था। अब इतना कह कर मैं अपनी बात खत्म करता हूं और आशा करता हूं कि सदन इस ग्रान्ट को स्वीकार करेगा।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान ३५ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--नीति का व्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्य की स्थापना पर अनियन्त्रित व्यय किया जाना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान ३५ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--नीति का व्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है। वर्कचार्ज स्टाफ की मजदूरी या वेतन का न बढ़ाया जाना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान ३५ के अधीन मांग की राशि में १०० रुपये की कमी कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है। प्रस्तावित योजनाओं पर प्राक्कलित व्यय का न होना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान ३५ के अधीन मांग की राशि में १०० रुपये की कमी कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य---विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है। सरकारी लेबर आर्मी द्वारा निर्माण-कार्य न करा कर केवल ठेके पर कार्य कराना जिसके फलस्वरूप अधिक व्यय तथा कार्य कमजोर होता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३५---सार्वजनिक निर्माण कार्य स्थापना पर व्यय---लेखा शीर्षक ५०---नागरिक निर्माण कार्य और ८१---राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों की पूंजी का लेखा के अन्तर्गत ८१,१२,२०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---अब मैं दूसरे अनुदान के कटौती के प्रस्ताव लिये लेता हूं। प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान ४९ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दिया जाय। कमी करने का उद्देश्य---नीति का व्योरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है---अनुदान से संबंधित योजना का लक्ष्य समय से पूरा नहीं किया जा रहा है।

(प्रश्न उपस्थित किया किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान ४९ के अधीन मांग की राशि को घटा कर एक रुपया कर दिया जाय। कमी करने का उद्देश्य---नीति का व्योरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है---राजकीय निर्माण कार्यों में अपव्यय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान ४९ के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दो जाय। कमी करने का उद्देश्य---नीति का व्योरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है। विधान भवन के लिये नये पार्श्व (विंग) में दो उत्थानकों (लिफ्टों) के अधिष्ठापन की अनावश्यकता पर चर्चा।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान ४९ के अधीन मांग की राशि में २७५ हजार रुपये की कमी कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य---विशेष विषय जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है---विधान भवन की सजावट की अनावश्यकता।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान ४९ के अधीन मांग की राशि में १०० रुपये की कमी कर दो जाय। कमी करने का उद्देश्य---विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है---अत्यधिक गमनागमन वाली सड़क सिधौली से महमूदाबाद और सिधौली से बिसवां का आधुनिकीकरण न कराये जाने की ओर ध्यान आकर्षित करना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४९---राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों पर लागत---लेखा शीर्षक : ८१---राजस्व लेखे के बाहर निर्माण -कार्यों का पूंजी लेखा के अन्तर्गत ९,७३,७२,५०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिए स्वीकार की जाय। ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ५ बज कर ९ मिनट पर सोमवार, ९ मार्च, १९५९ के ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
६ मार्च, १९५९।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५७४ पर)

VARANASI :
15th September, 1958.

HIS EXCELLENCY SHRI V. V. GIRI,
GOVERNOR, U. P., LUCKNOW.

SIR,

Most humbly and respectfully the undersigned citizens and Medical Practitioners want to bring the following facts to your honour's notice for favourable consideration :

1. That ours being a poor country the medical aid should be very cheap in order to be within the reach of all sections of our people. That Homeopathy perhaps fulfils this requirement best.

That some of the outstanding Homeopaths of Varanasi are prepared to offer their services free of charge if other facilities are provided in a hospital.

That Government hospitals have no facility for the treatment of patients through Homeopathic science.

That now the Uttar Pradesh Government has given full recognition to Homeopathy as a Medical science.

That the Shiva Prasad Gupta Hospital being the main district Hospital and being situated in the heart of the city needs a Homeopathic section urgently.

Hence it is prayed that due consideration be given to the above facts and proper instructions be given to the department concerned.

We thank you very much Sir, in anticipation of favourable consideration.

Yours faithfully,

(Sd.) 1. DEVI PRASAD AGARWAL,
2. DR. BHIMRAJ SHARMA,
3. DR. BASUDEO CHATTERJEE
AND OTHER CITIZENS.)

ADDRESS :
DR. DEVI PRASAD AGARWAL,
62!7A, BHULETON,
VANANASI, U.P.

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३० का उत्तर पीछे पृष्ठ ५७६ पर)

मास	संख्या
अप्रैल, १९५७	५४
मई, १९५७	५८
जून, १९५७	५७
जुलाई, १९५७	५८
अगस्त, १९५७	५७
सितम्बर, १९५७	५५
अक्तूबर, १९५७	५४
नवम्बर, १९५७	५४
दिसम्बर, १९५७	६५
जनवरी, १९५८	८०
फरवरी, १९५८	८५
मार्च, १९५८	८४
अप्रैल, १९५८	९२
मई, १९५८	१०३
जून, १९५८	१०४
जुलाई, १९५८	१०५
अगस्त, १९५८	९७
सितम्बर, १९५८	१०१
अक्तूबर, १९५८	१०३
नवम्बर, १९५८	१०४
दिसम्बर, १९५८	१०२

श्री कमलापति त्रिपाठी,
गृह मंत्री ।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५८० पर)

मुकदमों का ब्योरा

मुकदमें जो (एक साल से ऊपर) पैंडिंग थे	..	..	१६
मुकदमें जो (छः माह से ऊपर) पैंडिंग थे	..	..	१०२
मुकदमें जो (दो माह से ऊपर से) पैंडिंग थे	..	..	३०६
मुकदमें जो दो माह के अन्दर थे	..	..	२४८
योग			६७५

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५९२ पर)

इस जिले में परिगणित जातियों के निम्नलिखित वाचनालय एवं पुस्तकालय चल रहे हैं और गतवर्ष विभाग द्वारा इनको दी गई धनराशि उनके नाम के सामने अंकित है

पुस्तकालयों के नाम	स्वीकृत धनराशि
	रुपया
१--हरिजन पुस्तकालय, उरई	४८०
२--मूल भारतीय सर्वोदय पुस्तकालय एवं वाचनालय, गांधीनगर कोंच	६२४
३--हरिजन पुस्तकालय, एटा	३८४
४--हरिजन पुस्तकालय, हरीपुर	३०६
५--हिन्दी विद्यार्थी सम्प्रदाय, पुस्तकालय हिन्दी भवन, कालपी	५१६

इसके अतिरिक्त गत वर्ष १५० रुपया की दर से प्रत्येक पुस्तकालय को अनावर्तक अनुदान भी स्वीकृत किया गया था ।

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५९२ पर)

१—एक प्रधान लिपिक
२—एक प्रधान अंकिक
३—तीन सहायक लिपिक
४—दो सहायक अंकिक
५—एक प्रधान कापीइस्ट
६—एक कापीइस्ट
७—एक पुलिस अधीक्षक का स्टेनोग्राफर
८—एक अभिलेखपाल
९—एक उप पुलिस अधीक्षक शिकायती का हिन्दी स्टेनोग्राफर
१०—एक सहायक अभिलेखपाल
११—एक वैतनिक शिशुक्ष
१२—एक पुलिस अधीक्षक का पेशकार (सब-इंस्पेक्टर नागरिक पुलिस)।
१३—एक पुलिस अधीक्षक का सहायक पेशकार (हेड का० नागरिक पुलिस)।
१४—एक पुलिस अधीक्षक की पेशी का अहलमद (का० नागरिक पुलिस)।
१५—एक उप पुलिस अधीक्षक का पेशकार (हेड का० नागरिक पुलिस)।
१६—एक उप पुलिस अधीक्षक का अहलमद (का० नागरिक पुलिस)।
१७—एक विज्ञापन मुहर्रिर (का० नागरिक पुलिस)।
१८—दो डिस्पेचर (का० नागरिक पुलिस)।
१९—एक पेटिशन मुहर्रिर (का० नागरिक पुलिस)।
२०—एक मुहर्रिर पत्र व्यवहार शाखा में नियुक्त (का० नागरिक पुलिस)।
२१—एक मुहर्रिर लेखा शाखा में नियुक्त (का० नागरिक पुलिस)।
२२—एक अधिकारी जिला अपराध अभिलेख शाखा (सब-इंस्पेक्टर नागरिक पुलिस)।
२३—एक मुहर्रिर जिला अपराध अभिलेख शाखा में नियुक्त (कां० नागरिक पुलिस)।
२४—एक दफ्तरी।
२५—दो चपरासी।
२६—एक पानीवाला।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—२ एल० ए०—१९५९—८४५।